हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार , दिनांक 18 मार्च, 2026 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न पुनः आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

18.03.2026/1100/ए.पी. /एच.के. -1

अध्यक्ष : आप सबका बजट सत्र के दूसरे चरण में स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि सभी माननीय सदस्य प्रदेश हित के विषयों को इस माननीय सदन में गंभीरता से विचार-विमर्श करते हुए इस माननीय सदन को पूरा सहयोग करेंगे। आज माननीय सदस्य श्री पूर्ण चन्द ठाकुर जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

स्थगित प्रश्न संख्या :2319

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लगाया है उसमें ओ0डी0आई0 के अंदर अधिकारी या अन्य कर्मचारी आते हैं। The any "Officers of Doubtful Integrity" उसमें यह माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं-न-कहीं किसी गलत काम, जैसे रिश्वत या अन्य मामलों में पकड़ा गया है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रभावशाली पद पर नहीं लगाया जाना चाहिए, आगे के लिए ऐसी परम्परा रहती है। लेकिन मैंने कई क्षेत्रों में देखा है कि जिन लोगों को ओ0डी0आई0 में डाला गया है, उन्हें भी वर्तमान सरकार द्वारा प्रभावशाली पदों पर रखा गया है। हमारी ऊना विधान सभा क्षेत्र में, मेरे गांव में बंदोबस्त का काम चल रहा है। वहां के तहसीलदार को रिश्वत कांड में पकड़ा गया था लेकिन उसके बाद उन्हें तीन बार सेवा विस्तार दिया गया। जहां बंदोबस्त हो रहा है, उस गांव के लोगों ने आंदोलन किया, धरना-प्रदर्शन भी किया और हाई कोर्ट में केस भी दायर किए कि हमारी जमीनें प्रभावशाली लोगों द्वारा उस तहसीलदार से अपने नाम करवा ली गई हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि क्या वे सदन के फ्लोर पर यह आश्वासन देंगे कि ओ0डी0आई0 में रखे गए अधिकारियों को आगे ऐसी जगहों पर तैनाती नहीं दी जाएगी, ताकि वे अपने सेवा विस्तार के दौरान गलत लोगों के कहने पर गरीबों की जमीनें हड़प न सकें। वहां पर गरीब लोगों द्वारा बार-बार धरना प्रर्दशन किया जा रहा है, गरीब लोग हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं और उन्हें बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। लगभग 60 किसान इसका शिकार हुए हैं। उनका कहना है कि वहां के प्रभावशाली व्यक्तियों ने उस

तहसीलदार को वहां पर लगाया। आप सी0आई0डी0 से पता करवा सकते है कि वहां पर प्रभावशाली व्यक्ति कौन हैं? नहीं तो मुकेश जी आपको बता देंगे। उन व्यक्तियों ने अपने नाम गरीब किसानों की जमीनों को लिखवा लिया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसे लोगों को जल्दी हटाएंगे और उनकी जगह ईमानदार अधिकारी लगाएंगे, तभी वहां के लोगों के साथ न्याय होगा। यही मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है।

18.03.2026/1100/ए.पी. /एच.के. -2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा जो बातें सामने लाई गई हैं, **उस पर मैं केवल आश्वासन नहीं देता बल्कि सीधी कार्रवाई करता हूं कि जितने भी ओ0डी0आई0 अधिकारी हैं, उन्हें सरकार द्वारा तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा।**

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती द्वारा इस माननीय सदन में पूछा गया है। जिसके उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ओ0डी0आई0 की सूची में जो कुछ अधिकारी थे जिन्हें नियुक्ति दी गई थी, उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटाए जाने की बात उन्होंने इस माननीय सदन में कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1105 /AT/HK /01

प्रश्न संख्या 2319 जारी.. श्री जय राम ठाकुर जारी ....

कि क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने भी ODI की लिस्ट सरकार से मांगी थी? क्या वह ODI की लिस्ट आपने हाई कोर्ट में प्रस्तुत की है? यदि आपने लिस्ट प्रस्तुत की है तो क्या उस लिस्ट के अंतर्गत यही तीन नाम हैं, जिनका जिक्र इस माननीय सदन में हो रहा है या इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे नाम हैं? मैं इसकी जानकारी चाहता हूं। यदि हैं तो वे कौन-कौन हैं?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। यदि माननीय विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी कोई नाम देंगे, तो उसे भी तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा।

18.03.2026/1105 /AT/HK /02

स्थगित प्रश्न संख्या 3082

श्री सुधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें बताया गया है कि 10 समितियां कैबिनेट में गठित की गईं जिनमें से 9 ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है लेकिन जो सूचना आई है उसमें केवल 7 समितियों का ही विवरण है। उसमें भी नंबर दो पर विमल नेगी मामले में जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। इस प्रकार कुछ रिपोर्टें अभी भी अपेक्षित हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो जांच समितियां गठित की गई हैं क्या इस सत्र में इस प्रश्न की पूरी जानकारी आ जाएगी और जो जांच रिपोर्टें अभी अपेक्षित हैं, उन समितियों के लिए क्या कोई समय-सीमा तय की गई है? चूंकि कैबिनेट ने ये जांच समितियां गठित की हैं, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी समय-सीमा निर्धारित करेंगे ताकि सभी जांच रिपोर्टें निर्धारित समय के अंदर कैबिनेट को सौंप दी जाएं?

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना अपलोड कर दी गई है। यह लगभग 200 पेज की सूचना है। निश्चित रूप से कई जांच समितियों की रिपोर्ट गोपनीय होती है, जिन्हें हम सार्वजनिक नहीं करते और केवल कैबिनेट के सामने ही रखते हैं। कैबिनेट की रिपोर्ट को हम सभा पटल पर नहीं रख सकते। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है, यदि वे किसी विशेष जांच रिपोर्ट की मांग करेंगे और वह गोपनीयता के आधार पर नहीं होगी, तो उसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री सुधीर शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर यदि कोई भी विधायक सरकार से कोई जानकारी पूछता है, तो क्या इन जांच समितियों की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है? यदि कैबिनेट ने निर्णय लिया है तो प्रदेश हित

में जानकारी सभा पटल पर रखी जानी चाहिए। क्या ऐसा कोई निर्णय हुआ है या सरकार ने कानून में कोई बदलाव किया है कि इन जांच समितियों की रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा?

18.03.2026/1105 /AT/HK /03

अध्यक्षः वैसे तो इन्होंने यह कहा है कि कुछ जांच समितियां ऐसी होती हैं जिनकी रिपोर्ट केवल कैबिनेट में ही रखी जाती है। जब तक उस पर कोई एक्शन प्रपोज नहीं होता, तब तक उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। जब एक्शन प्रपोज हो जाता है उसके बाद वह विधान सभा के पटल पर लाई जा सकती है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1110/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या 3852

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है लेकिन आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसका पहला चरण पूर्ण हो चुका है और दूसरे चरण का पैसा भी मंजूर हो चुका है। तीसरे चरण के पैसे की डी0पी0आर0 बनाई जाए और मैं लोक निर्माण मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह कब तक बन जाएगी और सड़क का निर्माण कब तक पूर्ण होगा?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य किशोरी लाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यह प्रश्न हर बार विधान सभा के अलग-अलग सत्रों में गूंजता है। हमारे भरमौर के विधायक भी इस प्रश्न को समय-समय पर उठाते रहते हैं। सरकार इस सड़क के निर्माण पर बहुत गम्भीर है। होली-उतराला सड़क की कुल लंबाई 71.00 कि0मी0 है। इस सड़क का 39.00 कि0मी0 भाग (होली से सुराही पास) लोक निर्माण विभाग मण्डल भरमौर व 32.00 कि0मी0 भाग (सुराही पास से उतराला) लोक निर्माण विभाग मण्डल

बैजनाथ के अधीन पड़ता है। भरमौर मण्डल के अन्तर्गत सड़क के भाग होली से इलाका माता मंदिर कि0मी0 0/00 से कि0मी0 17/00 भाग में सड़क निर्माण कार्य स्टेट हैड के तहत पूर्ण कर लिया गया है तथा उक्त सड़क पर ब्लैक टॉप का कार्य चला हुआ है। इलाका माता मंदिर से सुराही पास कि0मी0 17/00 से 39/00 तक जिसकी लम्बाई लगभग 22.00 कि0मी0 है, के भाग कि0मी0 17/0 से 19/100 तक फारमेशन/कटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सुराही नाला पर एक 40.00 मीटर स्पेन स्टील ट्रस पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

दूसरी तरफ जो हमारी बैजनाथ की साइड है उसमें दो सड़कें हैं। प्रथम चरण के कार्य उतराला से बकलूड कि0मी0 0/0 से 13/00 तक की स्वीकृति NABARD (RIDF&XXVII) के तहत की गई है। दूसरे चरण का कार्य 13 से 19 किलोमीटर तक पुल सहित मु0 921.31 लाख रुपये की स्वीकृति नाबार्ड से प्राप्त हो चुकी है। इसकी टैक्निकल सेंक्शन का कार्य चीफ इंजीनियर, मण्डी द्वारा करवाया जा रहा है। हमारे ई0एन0सी0 ने उनसे बात की है। And likely in another 1-2 days this permission will be granted by the Chief Engineer, Mandi Zone. इसका कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और जो इसके अंत का

18.03.2026/1110/केएस/वाईके/2

भाग है, हमारे स्टेट हैड के तहत उसका कार्य करवाया जा रहा है। इसको अलग-अलग फेजिज़ में, अलग-अलग हैड्ज़ द्वारा पूरा करवाया जा रहा है। यह सड़क हमारे जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार इसके लिए समय-समय पर बजट का प्रावधान करती रहती है। **इसको समय पर पूरा करवाना हमारी वचनबद्धता है और सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।**

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तीसरे फेज़ की डी0पी0आर0 कब तक बन जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **हम डी0पी0आर0 जल्दी बनवाने के निर्देश देंगे क्योंकि प्लानिंग के माध्यम से नाबार्ड को सरकार की प्राथमिकताएं तय हो कर जाती हैं।**

मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे और जल्दी से जल्दी इसकी सेंक्शन नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त होगी ताकि इसके अंतिम चरण का कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जा सके।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क मेरे चुनाव क्षेत्र और बैजनाथ चुनाव क्षेत्र को जोड़ रही है। अनेकों वर्षों से कांगड़ा और चम्बा के लोग इस सड़क की मांग करते आए हैं। इसके बनने से लोगों को बहुत अधिक सुविधा होगी जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल सरकार से इतना आग्रह करता हूं कि विधायक प्राथमिकता में भी हमने इस विषय को उठाया है और पिछले वर्ष की विधायक प्राथमिकता में भी इसको अपनी ओर से नाबार्ड की सेंक्शन के लिए भिजवाया था। विधायक प्राथमिकता की बैठक में मुझे सरकार से, माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन भी प्राप्त हुआ था कि हम इसको आपकी नाबार्ड की स्कीम में भेजने जा रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से यही आग्रह करता हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो इस सड़क का भाग है, उसके लिए वित्तीय पोषण की, जो मुख्य मंत्री जी ने नाबार्ड से करवाने का आश्वासन दिया है, उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृति प्रदान करें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.03.2026/1115/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 3852----- क्रमागत डॉ0 जनक राज------ जारी

क्योंकि यह सड़क अगर बैजनाथ साइड से बन जाएगी और मेरी साइड से नहीं बनेगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा।

अध्यक्ष : इस प्रश्न का उत्तर लोक निर्माण मंत्री जी दे रहे हैं।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, परंतु इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था।

Speaker : He will be replying thereafter if already the Hon'ble Chief Minister wants to supplement.

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क अगर दोनों साइड्ज से बनेगी इसका फायदा तभी होगा वरना एक तरफ से बनाकर और दूसरी तरफ से नहीं बनाई जाएगी तो वह भी पांच वर्षों में खराब हो जाएगी।

अध्यक्ष : मंत्री जी, वैसे तो इसका डिटेल्ड उत्तर आ गया है। He has said that State is doing in the different phases यानी इसको स्टेट सैक्टर और नाबार्ड के अंतर्गत किया जा रहा है।

डॉ0 जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से इस सड़क के कार्य की गति बहुत कम है।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज ने अगर इस विषय को विधायक प्राथमिकता की बैठक में उठाया है और मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में आश्वासन दिया है तो **निश्चित तौर पर अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जो प्राथमिकताएं तय होंगी सरकार उस बारे में गम्भीरता से कार्य करेगी।** अगर इसके लिए नाबार्ड से स्वीकृति नहीं भी आई है, the Government and the Department is of absolute resolve **ट्राइबल एरियाज को जोड़ने के लिए हमारी सरकार पूरे तरीके से कार्य कर रही है।। want to assure the Hon'ble Member till the time the NABARD sanctions does not come even than from the State Head we will try to expedite this work और**

18.03.2026/1115/av/yk/2

इस सड़क का कार्य निश्चित समयावधि के अंदर किया जाएगा। नाबार्ड से स्वीकृति आने पर इस सड़क का कार्य उसके पैरामीटर्ज के तहत किया जाएगा और मैं माननीय सदस्य को यही विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि होली-उतराला सड़क का निर्माण कार्य कब और किस-किस स्कीम के अंतर्गत शुरू हुआ था और यह जब शुरू हुआ था तो इसके लिए कितने बजट का प्रोविजन था? यहां पर दी गई

जानकारी के अनुसार यह सड़क दिनांक 10.09.2025 को नाबार्ड को प्रेषित की गई थी। मुझे यह बताया जाए कि इससे पहले इस सड़क का कितना कार्य किस-किस स्कीम के अंतर्गत हो चुका है? इसके लिए नाबार्ड से जब सैंक्शन आएगी; वह अलग बात है परंतु इस सड़क का कई चरणों में पहले ही कार्य हो चुका है इसलिए आप सदन के अंदर उस बारे में भी जानकारी दें।

Speaker : You have a given a detail reply yet clarify.

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय पर पहले ही बहुत डिटेल में जवाब दे चुका हूं कि इसके दो छोर के कार्य नाबार्ड के पास है। उसमें से एक का कार्य पूर्ण हो चुका है और दूसरे छोर के कार्य की हमें स्वीकृति मिल चुकी है। यह मैटर चीफ इंजीनियर के पास है और जैसे ही वहां से टैक्निकल सैंक्शन मिलेगी work will commence निश्चित तौर पर 27 व 28 अलग-अलग आर0आई0डी0एफ0 होते हैं, यह उसके तहत आया है। मैं दूसरे छोर के बारे में पहले ही कह चुका हूं कि भरमौर सैक्शन के अंतर्गत करवाया जा रहा है। It is already a matter of record and I have stated it very clearly, so there is no further need of elaboration.

18.03.2026/1115/av/yk/3

प्रश्न संख्या : 3853

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, यहां दी गई सूचना के अनुसार मेरे विधान सभा क्षेत्र में आंशिक एवं पूर्ण रूप से प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा 4,17,10,000/- रुपये की धनराशि राहत के तौर पर प्रदान की गई। जिसमें से पूर्णतः क्षतिग्रस्त 92 घरों के लिए 2,95,10,000/- रुपये दिए गए। यहां सदन के अंदर आदरणीय मुख्य मंत्री सहित सत्ता पक्ष के लगभग सभी सदस्यों ने कहा है कि इस प्रकार से प्रभावित परिवारों को 7-7 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसमें 92 घरों के लिए 2,95,10,000/- रुपये की धनराशि दी गई। अगर इस 2,95,10,000/- रुपये की राशि को 92 से भाग किया जाए तो यह राशि

320760.86 रुपये प्रति परिवार बनती है। यहां पर जब यह कहा गया कि 7 लाख रुपये की राशि दी जाएगी तो उस हिसाब से यह आंकड़ा गलत आ रहा है।

अध्यक्ष : यह पहली किस्त है।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2023 का पूछा है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमारी स्कीम को ठीक से नहीं समझा। हम इस प्रकार की राहत राशि एकमुश्त नहीं दे रहे हैं। हम इसको किस्तों में दे रहे हैं। इसमें पूर्णतया क्षतिग्रस्त परिवार को एक तो 7 लाख रुपये की राशि दी जा रही

टी सी द्वारा जारी

18.03.2026/1120/टी0सी0वी0/ए0जी0-1
प्रश्न संख्या : 3853. क्रमागत्
माननीय राजस्व मंत्री ... जारी

और इसके अतिरिक्त पहले जो राशि 70 हजार रुपये दी जाती थी उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है और पहली किश्त के रूप में 4-4 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके बाद जब यह राशि खर्च कर दी जाएगी तो उसके बाद दूसरी किश्त जारी की जाएगी तथा अंत में 20 हजार रुपये अंतिम किश्त के रूप में दिए जाएंगे। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि वे स्कीम को समझने का प्रयास करें।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि 4 लाख रुपये पहली किश्त के रूप में दिए जाएंगे, यदि इस राशि का औसत निकाला जाए तो यह 3 लाख 20 हजार 760 रुपये बनती है। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की जो किश्त आई थी उस राशि को भी इसमें जोड़ दिया गया है? इसके तहत कुछ लोगों को 7-7 लाख रुपये दिए गए और कुछ को आप 4-4 लाख रुपये दिए जाने की बात कर रहे हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह आपदा केवल वर्ष 2023 की नहीं है बल्कि वर्ष 2024 और 2025 में भी इससे काफी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। माननीय सदस्य ने जो सूचना मांगी है, वह वर्ष 2025 से संबंधित है जिसमें पहली किश्त के रूप में 4-4 लाख रुपये दिए गए हैं और उसका विवरण मैंने दे दिया है।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय राजस्व मंत्री प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपदा में जो मकान पूर्णतया नष्ट होता है उसको केन्द्र सरकार की ओर से 1 लाख 30 हजार रुपये की सहायता मिलती है। उस राशि को भी उसमें जोड़ा जाता है लेकिन 7 लाख रुपये तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं।

18.03.2026/1120/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

प्रश्न संख्या 3854

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा- उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 3855

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है और इसमें इन्होंने कहा भी है कि सेब उत्पादन अब केवल तथाकथित क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह गया है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण बिलासपुर जैसे क्षेत्रों में भी सेब उत्पादन शुरू हुआ है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय इसे आग्रह है कि चुराह विधान सभा क्षेत्र तथा चंबा के अन्य क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से हॉर्टिकल्चर सैक्टर में स्टाफ की भारी कमी है जिसके कारण भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए पिछली सरकार के समय में प्रयास भी किए गए थे। लेकिन अब हाई डेंसिटी प्लांट्स के नाम पर विभिन्न नर्सरियों से अलग-अलग गुणवत्ता के पौधे आ रहे हैं। हमने मनरेगा के माध्यम से सेब के पौधों को अलग-अलग पंचायतों में लगवाने की भी कोशिश की थी लेकिन उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया। मेरा मंत्री जी से निवेदन है

कि चुराह जैसे विधान सभा क्षेत्र या जहां हम सेब के उत्पादन से इकोनोमी को बढ़ा सकते हैं वहां इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मैंने विधायक प्राथमिकता की बैठक में भी मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन किया था कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विभाग में बहुत सारी पोस्टें खाली चल रही हैं जिसकी वजह से हमें ढंग के प्लांट्स नहीं मिल पाते हैं। पहले एक पेड़ से 10 किलोग्राम के 80-80 बॉक्सों तक उत्पादन होता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। क्या राजस्व मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि चुराह और चंबा जैसे रिमोट क्षेत्रों के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी जिसके माध्यम से भारत सरकार को प्रपोजल भेजी जाए और प्रदेश सरकार भी इसमें सहयोग करे ताकि बागवानी के माध्यम से वहां की इकोनॉमी को मजबूत किया जा सके?

राजस्व मंत्री श्रीमती एन0एस0 द्वारा .... जारी

18-3-2026/1125/NS-AG/1

प्रश्न संख्या : 3855 -----क्रमागत

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का मूल प्रश्न यह था कि सेब की खेती या बागवानी को किसी एक इलाके में सीमित न रख कर पूरे प्रदेश में समान रूप से विकसित किया जाए। मैं इस विषय पर यह कहना चाहता हूं कि हमने इसको एक क्षेत्र में सीमित नहीं रखा है बल्कि पूरे प्रदेश में सेब की पैदावार हो रही है। यहां तक कि जो हमारे निचले क्षेत्र हैं वहां पर भी सेब की पैदावार शुरू हो गई है जैसे शाहपुर विधान सभा क्षेत्र में भी सेब तैयार हो रहा है और इस बात का माननीय केवल सिंह पठानिया जी को पता है। पालमपुर व अन्य क्षेत्रों में भी सेब की पैदावार हो रही है। हमारी सरकार की एक स्कीम है और यह हाई डेंसिटी प्लांटेशन को लेकर वर्ल्ड बैंक से एडिड स्कीम थी। अगर मैं इसका जिक्र करूं तो यह स्कीम पहले थी और अब समाप्त हो गई है तथा इसमें जिलावार बजट का प्रावधान भी किया गया था। इसमें चंबा जिला को लगभग 23 करोड़ रुपये मिले, किन्नौर जिला को 6 करोड़ रुपये, मंडी जिला को 36 करोड़ रुपये, कुल्लू जिला को 60 करोड़ रुपये, शिमला जिला को 49 करोड़ रुपये, कांगड़ा जिला को 11 करोड़ रुपये और लाहौल-स्पीति को 5

करोड़ रुपये मिले हैं। सारे जिलों में एक समान वितरण किया गया है। माननीय सदस्य की चिंता चुराह क्षेत्र को लेकर है और हाई डेंसिटी प्लांटेशन को लेकर है। जहां तक हाई डेंसिटी प्लांटेशन की बात है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट में नर्सरी अवलेबल है। 24 से अधिक रूट स्टॉक की किस्में हमारे पास हैं, कल्टीवेज हमारे पास हैं। हमने इस बार हाई डेंसिटी के तीन लाख से अधिक रूट स्टॉक्स वे चाहे स्टोन फ्रूट के हों या अन्य फलों के हों तो हमने बागवानों को उपलब्ध करवाए हैं। अगर हम चुराह क्षेत्र की बात करें तो वहां पर मनरेगा में जिला चम्बा में लगभग 9 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्लांट्स स्वयं लिए गए हैं और ये हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया था। आपने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट को इससे बाहर रखा और पता नहीं कहां से प्लांट्स लाए। मैंने जब इस बारे में तहकीकात की तो पता चला कि ये प्लांट्स ज्यादातर खत्म हो गए हैं और टिक ही नहीं पाए। चम्बा में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर स्टाफ की कमी है और इस बात को मैं मानता हूं। हमने स्टाफ के बारे में यह फैसला किया है कि बहुत सारे हमारे एच0डी0ओज0 व सब्जैक्ट मैटर स्पेशलिस्टस विदेशों के टुअर करके आए हैं और अब हम इनको फील्ड में भेज रहे हैं। हम इसके लिए एक स्कीम बना रहे हैं और उसके तहत आपको ये अधिकारी हाई डेंसिटी पौधों के रखरखाव हेतु ज्ञान देंगे। माननीय सदस्य के इलाके में हाई डें

18-3-2026/1125/NS-AG/2

सिटी पौधों की शुरुआत करने वाले लोगों ने अपने बागीचे लगाए हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि चुराह क्षेत्र के लिए हाई डेंसिटी पौधों के बारे में जानकारी देने हेतु कैंप लगाए जाएं और आपसे प्लांट्स की डिमांड भी ली जाएगी। एम0आई0एस0 के तहत ड्रिप इरीगेशन की स्कीम्ज हैं, सोलर फेंसिंग की स्कीम्ज हैं और इनको हम सभी जिलों में दे रहे हैं। जिला चम्बा को भी हर वर्ष का शेयर दिया जाता है।

डॉ0 हंस राज : माननीय मंत्री जी ने सही कहा कि बहुत सारे अधिकारियों को अलग-अलग देशों के एक्सपोजर विजिट करवाए गए हैं और बहुत सारे रूट स्टॉक्स भी आए हैं। अध्यक्ष महोदय, धरातल में जहां प्लांटस पहुंचने चाहिए थे तो वे उस अवस्था में नहीं पहुंचे कि वे फलीभूत होते और आज उनका कुछ रिजल्ट आता। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि चम्बा को 23 करोड़ रुपये मिले तो उसका टर्नआउट नहीं आया

है। दूसरा, जो सब्जैक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की बात कही गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पहले कभी सब्जैक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हुआ करता था लेकिन उसको विद पोस्ट उठा लिया गया था। मेरे क्षेत्र में मंत्री जी दो बार दौरे पर आए हैं। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि जहां पोटैंशियल है और हमारा जो अपर जोन है जिसमें बैरागढ़, झाझा, हिमगिरी, चांजू-चरड़ा और कलेहल और मणि मसरूंड व जुलाड़ा का जो जोन है तो इसमें बहुत पोटैंशियल है। यहां पर ड्रिप इरीगेशन की भी बात की गई है तो हमने उसमें एम0एल0ए0 प्रायोरिटीज भी दी हैं कि आने वाले 10 वर्षों में उस विधान सभा क्षेत्र में इकोनॉमी के हिसाब से सेबों को अगर मेन व्यवसाय बनाते हैं

आर0के0एस0 द्वारा----जारी

18.03.2026/1130/RKS/AS-1

प्रश्न संख्याः 3855... जारी डॉ0 हंस राज जारी....

वैसे हमारे क्षेत्र के लोग मटर की खेती स्वयं करने लगे हैं। जिस दिन हमारी एम.एल.ए. प्रायोरिटी की बैठक थी उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा कि किसान खुद ही अपनी खेती कर रहे हैं और कृषि विभाग द्वारा सॉइल टेस्टिंग आदि नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सप्लीमेंट्री कीजिए।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो 23 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है, वह राशि कहां वितरित की गई? दूसरा, यदि सरकार ने रिमोट एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए सेबों के संदर्भ में कोई योजना बनाई है तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि आने वाले समय में आप चुराह विधान सभा क्षेत्र या चम्बा का विशेष दौरा करेंगे ताकि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार की सहायता से एक संयुक्त योजना बनाकर उस क्षेत्र को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया जा सके।

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, चम्बा में वर्तमान में 12,728 हेक्टेयर भूमि में सेब की खेती हो रही है। यदि हम पैदावार की दृष्टि से देखें तो वहां 4,200 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन

होता है जो उस क्षेत्र के हिसाब से बहुत कम है। माननीय सदस्य जो बैरागढ़ अथवा अपने निर्वाचन क्षेत्र के ऊपरी इलाकों की बात कर रहे हैं वहां उच्च गुणवत्ता के सेब तैयार करने की काफी संभावना है। **इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम वहां विशेष कैम्पों का आयोजन करेंगे। आप हमें अपनी मांग दें कि आपको कितने सेब के पौधे चाहिए। आपको जिस किस्म के पौधे चाहिए होंगे, जैसे रूट स्टॉक्स अथवा उस ऊँचाई के अनुरूप जो भी उपयुक्त किस्में चाहिए होंगी हम उन्हें उपलब्ध करवाएंगे।** आप जो 23 करोड़ रुपये का हिसाब मांग रहे हैं वह पैसा आपकी सरकार के समय खर्च हुआ है। मैं तो वर्ष 2023 में राजस्व मंत्री बना हूं, उस समय वह योजना हांफ गई थी। इस योजना में 6 महीने की एक्सटेंशन ली गई थी अगर आपको इसका हिसाब चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन इसमें आपकी सरकार का ही कच्चा चिट्ठा खुलेगा।

18.03.2026/1130/RKS/AS-2

प्रश्न संख्या : 3856

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, धर्मशाला का वॉर मेमोरियल हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है उनके संदर्भ में मैंने यह प्रश्न पूछा था। पहला परमवीर चक्र जिला कांगड़ा के स्वर्गीय श्री सोमनाथ शर्मा जी को प्राप्त हुआ था। यदि पूरे देश की बात करें तो 21 परमवीर चक्रों में से 4 हमारे हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों को प्राप्त हुए हैं। प्रश्न के उत्तर में धर्मशाला वॉर मेमोरियल के विकास और सौंदर्यीकरण हेतु 60 लाख रुपये व्यय किए जाने का उल्लेख किया गया है। करोड़ों रुपये की लागत से बने इस म्यूजियम में 25 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अप्रैल को हमारे प्रदेश के मंत्रियों तथा महामहिम राज्यपाल ने वहां का दौरा किया था। वहां भूतपूर्व सैनिकों की एक समिति भी गठित की गई है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्व में सत्ता में थी तब जिला कांगड़ा के सभी विधायकों की निधि भी इस वॉर मेमोरियल में लगाई गई थी लेकिन पिछले लंबे समय से वह मेमोरियल बंद पड़ा है। इस भवन पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। उस मेमोरियल में 1962 और 1971 के युद्धों में दी गई शहादतों का ब्यौरा तथा सेना के गठन से लेकर अब तक का पूरा इतिहास उपलब्ध है। प्रश्न के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि यह स्मारक सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुला रहता है लेकिन मेरा प्रश्न विशेष

रूप से म्यूजियम के संबंध में है। क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस म्यूजियम को 24x7 खोला जाएगा? यह एक ऐतिहासिक स्मारक है। माननीय मुख्य मंत्री ने पर्यटन की दृष्टि से जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किया है। वहां सैलानियों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। HPCA धर्मशाला को भी हजारों पर्यटक देखने जाते हैं। मैंने तथा भूतपूर्व सैनिकों की समिति ने मंत्री जी से इस म्यूजियम के रख-रखाव हेतु आग्रह किया था। मैं माननीय मंत्री जी से इस म्यूजियम के रख-रखाव के लिए आश्वासन चाहता हूं। वहां डिप्टी कमिश्नर साहब को इसका प्रमुख बनाया गया है परंतु वे वर्ष में केवल 2-3 बार ही वहां जाते हैं। वहां परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों और हमारे वीर योद्धाओं का इतिहास सुरक्षित है जिनकी बदौलत हमें तिरंगा झंडा प्राप्त हुआ है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

18.03.2025/1135/बी.एस./ए.एस.-1

श्री केवल सिंह पठानिया जारी...

मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि कोई ऐसा मेकैनिज्म बने जिससे 24x7 लोगों को वहां जाने की सुविधा मिले। इसके लिए कोई कमेटी बनें। जो टूरिस्ट धर्मशाला आते हैं वे भी वहां वार मेमोरियल पर जाएं। इस संबंध में मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

Health and Family Welfare Minister : Hon'ble Speaker, Sir, It is a very-very important issue. मैं सोचता हूं कि ऐसा इंस्टीट्यूशन पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए, अभी तो मैं करता हूं कि हमारे for the youngers who are also joining the Armed Forces. इन सबके लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत है और यह एक गौरवशाली स्थान है और जहां तक इन्होंने हमारे वीर जवानों की बात की है। हमारे सोमनाथ शर्मा जी और मेरी ही पलटन के भंडारी साहब जो बिलासपुर से संबंध रखते हैं। First Victoria cross. मैं समझता हूं कि इन सब लोगों के लिए जो स्थान बना है वह और भी अच्छे वे में ऑर्गेनाइज हो। जब भी हमारा वहां पर हाउस होता है। I will certainly go there and see the place in detail और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं जिन्होंने प्रश्न उठाया है। He is

really concerned about it. **मैं इनको कहना चाहता हूं कि एक्स सर्विसमैन की अच्छी सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो इन सब चीजों में जाएगी और मैं डायरेक्टर और पूरी टीम को लेकर खुद भी वहां पर जाऊंगा और जितने भी चीजें वहां और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करनी होगी।** Hon'ble Speaker, Sir, I just want to inform the House that in England, couple of years back I had gone to see the War Memorial where solemn tributes is also served to Bhandari Ram Shah, who was an Indian recipient of the Victoria Cross. That war memorial was very beautifully organized. We should really visit it and with the blessing of Hon'ble Chief Minister we will visit that place in England and try to follow those parameters and make the War Memorial of Dharamshala more attractive. As the Hon'ble Member said it should be opened for the public. शहीदी स्मारक तो खुला है उसे तकरीबन 09:00 सुबह खोल दिया जाता है और शाम के तकरीबन 6:30 बजे तक खुला रहता है। यह गर्मी में भी और सर्दी में भी खुला रहता है। इसमें 5 साल की उम्र के बच्चों से 20 रुपये और पार्किंग शुल्क के 20-30 रुपये ले रहे हैं।
18.03.2025/1135/बी.एस./ए.एस.-2

if war memorial is opened, it will also give us an added revenue. So, it should be made more attractive. I also seek the blessings of this House as well as of the Hon'ble Chief Minister that we should make it more attractive-more beautiful and more presentable, so that people come and see it.

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय,मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो वार म्यूजियम है इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और किस-किस श्रेणी के हैं? ये कांट्रेक्चुअल है या नियमित है? क्या सरकार यह विचार रखती है कि जब इस म्यूजियम को खोला जाएगा तो इसमें क्यूरेटर के पद भी सरकार क्रिएट करेगी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला है यह केवल सैनिक कल्याण बोर्ड का ही नहीं है बल्कि Language, Art and Culture, Public Works Department और सभी डिपार्टमैंट का है। मैं उपमुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि वे भी इसमें भाग लें। हम एक अच्छी किस्म का संग्रालय बना सकें। हमारा जो लक्ष्य है वह एक

अच्छा शहीदी स्मारक बनाने का है। On the left side of it is a museum and on the outside of it is Sahidi Samarak तो हम इसे देख रहे हैं। The Himachal Pradesh State War Memorial Development Society, Dharmashala, is seeing it very nicely but they need our support too. I also request the Hon'ble Chief Minister that whatever the charges which are being taken from the general public at the moment, we will take this matter to the Cabinet and it should be condoned. Because our soldiers have given their lives to the country and they are also looking after such a war memorial, so why should we keep on charging from the public. As far as the matter of opening of this War Memorial is concerned, let's make it more presentable we will open it.

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा स्पेसिफिक है कि वार म्यूजियम के रखरखाव के लिए कितने कर्मचारी किस-किस श्रेणी के कार्यरत हैं?

Speaker : Hon'ble Health Minister, if you have an information supply it to the Hon'ble Member and if you don't have the information the same may be supplied to the Hon'ble Member.

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.03.2026/1140/DT/DC-1

प्रश्न संख्या 3856 जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो कर्मचारी वहां पर सेवारत हैं वहां की आवश्यकतानुसार उनकी संख्या सचमुच री नहीं है। इसलिए वहां पर और कर्मचारी लगाने की आवश्यकता है। **इसलिए यह जो एक्स-सर्विसमेन सोसायटी बन रही है इसमें आपको भी सदस्य के रूप में रखेंगे।** Because we belong to that area only.

18.03.2026/1140/DT/DC-2

प्रश्न संख्या 3857

श्री डी0एस0 ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय,जो उप-मुख्य मंत्री महोदय, ने सूचना सभा पटल पर रखी है, इसमें इन्होंने कहा है कि संसाधनों की कमी के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा चलाने का कोई विचार नहीं है।

मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारा क्षेत्र है वह एक पिछड़ा क्षेत्र है, इसमें सलूणी की कई पिछड़ी पंचायतें भी आती हैं। वहां से जो मरीज टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किए जाते हैं उनको वहां से दो-तीन बसिज को बदलनी पड़ती है तब जाकर वह टांडा पहुंचते हैं। कई बार लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा समय पर नहीं मिलती जिसके कारण रोगी की मृत्यु हस्पताल जाते हुए ही हो जाती है। यह सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधि सुविधाओं को उपलब्ध करवाये। आज समाचारों पत्रों में भी छपा है कि इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र को बढ़ावा दिया जायेगा। इसलिए मेरा उप-मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस रूट को लंगेरा से सलूणी क्षेत्र से होते हुए डॉ0 राजेन्द्र राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा के लिए बस चलाई जाए ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके।

18.03.2026/1140/DT/DC-3

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि चंबा में अपना मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है जिसको वर्तमान सरकार लगातार स्ट्रेन्थन कर रही है। इस कॉलेज को स्ट्रेन्थन करने लिए 175 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में 63 बसिज चलती हैं। इनके निर्वाचन क्षेत्र से चंबा को कंनेक्ट करने के लिए वर्तमान में छः बसिज चल रही हैं। इसके अतिरिक्त चंबा से धर्मशाला, चम्बा से नगरोटा, इनमें से एक बस तो भंझराडू से वाया नगरोटा टांडा के लिए जाती है। इसके साथ चंबा से शिमला, चंबा से पठानकोट, चंबा से चण्डीगढ़-ये सारी बसिज चलती है और इन सारी बसिज के साथ आगे कंनेक्टिड बसिज उपलब्ध हैं।

दूसरा, जहां पर माननीय सदस्य बस चलाने की बात कर रहे हैं वहां पर बस के रूट से कोई इंकम ही नहीं है। अगर बस वहां जाती है उस बस को केवल दस या बारह रुपये

इंकम हो रही है तो कोई लाभ नहीं है। हां, अगर 40 परसेंट या 50 परसेंट इंकम भी उस रूट्स से बसिज की इंकम होती है तो हम बस चलाने को तैयार हैं। लेकिन जहां पर बस रूट्स से केवल दस या बारह रूपये की इंकम हो रही है उन बसिज का रूट किसी भी ढंग से फिजिबल नहीं है क्योंकि हमें यह ऑर्गनाइजेशन भी चलानी है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि चंबा में मेडिकल कालेज भी स्थापित हो चुका है और वहां से नगरोटा के लिए बस भी उपलब्ध है और कई अन्य कंनेक्टिड बसिज भी हैं। इसलिए इस समय तो यह संभव नहीं है कि यह बसिज चलाई जा सके।

श्री डी0एस0ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, उप-मुख्य मंत्री जी के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। लंगेरा ऐसा क्षेत्र हैं जो जम्मू-कश्मीर के साथ लगने वाला क्षेत्र है तो हमें जम्मू-कश्मीर के साथ लगा दो क्योंकि वहां से जम्मू-कश्मीर नजदीक पड़ता है। हमारा राज्य एक वेल्फेयर स्टेट है। इसमें पैसा नहीं देखा जाता बल्कि इसमें लोगें का हित देखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री जी चंबा मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, इसके संबंध में मैं यही कहूंगा कि विधायक प्राथमिकता की बैठक के दौरान मेरे द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.03.2026/1145/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3857.....जारी श्री डी0 एस0 ठाकुर..... जारी

चम्बा मेडिकल कॉलेज बिल्कुल छोटा पड़ा चुका है। नई बिल्डिंग में उसे शिफ्ट नहीं किया जा रहा है और पुराने भवन में एक-एक बैड पर 3-3 पेशंट होते हैं। वहां पर डॉक्टर्स की भी बहुत कमी है। हमारे क्षेत्र के लोगों को टांडा मेडिकल कॉलेज में जाना ज्यादा सूट करता है। पठानकोट में लोगों को उपचार करवाने के लिए 2 से 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। मेरा उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि यह बस सेवा आरम्भ करना बहुत जरूरी है। मेरा सुझाव है कि इस बस सेवा को एक माह के लिए चला कर देखिए और यदि इसमें घाटा होता है तो इस सेवा को बंद कर देना।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमें जे0 एण्ड के0 के साथ लगा दिया जाए। हम इनकी बात को इनके विधान सभा क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा देंगे कि इन्होंने माननीय सदन में कहा है कि हम जे0 एण्ड के0 के साथ लगना चाहते हैं।...(व्यवधान) इन्होंने अभी कहा है।...(व्यवधान) अभी बोला है।...(व्यवधान)

Speaker: Please order in the House. ...(Interruption).

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं और माननीय सदस्य ने आपके सामने अभी यह बात रखी है कि हमें जे0 एण्ड के0 के साथ लगा दिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने यह कहा है कि जे0 एण्ड के0 हमारे साथ ही है तो हम उपचार के लिए वहां चले जाएं।

18.03.2026/1145/डी.सी.-एन.जी./2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ पंजाब राज्य के 17 बॉर्डर लगते हैं तो क्या मेरे क्षेत्र के लोग पंजाब में चले जांएगे? यह तो कोई बात नहीं है।...(व्यवधान) हम माननीय सदस्य की भावना बता देंगे।...(व्यवधान)

Speaker: Let the Hon'ble Deputy Chief Minister reply. ... (Interruption).

उप-मुख्य मंत्री : ऐसा है (विपक्ष के माननीय सदस्यों की ओर देख कर कहा), जबरदस्ती करने से बस नहीं लगेगी।...(व्यवधान) वहां पर 6 कनैक्टिड बसें हैं। चम्बा से धर्मशाला व नगरोटा आदि के लिए भी बसें चलती हैं। आप क्या चाहते हैं कि एक 47 सीटर बस केवल 3 आदमियों के लिए चले? वहां पर चम्बा के लिए कनैक्टिड बसें उपलब्ध हैं। उससे आगे वहां से चण्डीगढ़, पठानकोट, धर्मशाला, शिमला आदि हर अस्पताल के लिए कनैक्टिड बसें उपलब्ध हैं। इस प्रकार से तो माननीय सदस्य कहेंगे कि माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा के विधान सभा क्षेत्र श्री नैना देवीजी और एम्ज़ के लिए भी बस लगा दो। ऐसा नहीं होता है।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर कनैक्टिड बसें उपलब्ध हैं और इस बस सेवा को चलाने का औचित्य नहीं है।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, आज कल उप-मुख्य मंत्री जी जल्दी आवेश में आ जाते हैं। एक नए विधायक ने इनसे गुजारिश की है कि आप इस बस सेवा को ट्रायल बेस पर चलाएं। हमारी सरकार में तो बैरागढ़ से शिमला, बंजराडू से टांडा मेडिकल कॉलेज और नालागढ़ के लिए भी बसें चलाई गई हैं और ये सभी सबसे कामयाब बसें हैं। हमारे माननीय विधायक का कहना सही है कि कुछ समय के लिए चला कर देखिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला चम्बा में बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जो पिछले 3-4 सालों में 'null & void' कर दिए गए हैं। चम्बा से बैरागढ़ के लिए सुबह 6:30 बजे बस चलती थी और यह बहुत पुरानी बस सेवा है। मैं केवल अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं और माननीय विधायक, श्री डी0 एस0 ठाकुर का दर्द बिल्कुल सही है।

18.03.2026/1145/डी.सी.-एन.जी./3

लेंगरा क्षेत्र बिल्कुल लास्ट में है और वहां से कनैक्टिंग बसें भी केवल सलूणी तक ही मिल सकती हैं। उसके बाद कोई मरीज कब चम्बा पहुंचेगा और कब रैफर होकर टांडा मेडिकल कॉलेज जाएगा? आपने जो स्ट्रैंथन की बात कही है वह तो बिल्कुल रोबोटिक सर्जरी की तरह हो गई है कि रोबोट तो भेज दिए गए हैं और सर्जरी हो नहीं रही है। मैं आपको असलीयत बता रहा हूं। मेरा उप-मुख्य मंत्री जी से केवल इतना ही निवेदन है कि माननीय विधायक, श्री डी0 एस0 ठाकुर ने जैसा कहा है, उसे करने में कोई गुरेज नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इनका प्रश्न क्यों पूछ रह हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चम्बा जिला में ऐसे कितने रूट हैं जिन्हें बसों की कमी के कारण 3-4 सालों में बंद कर दिया गया है? चम्बा जिला एक आकांक्षी

जिला है और साथ ही आकांक्षी ब्लॉक्स को भी कवर करता है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में ऐसे कितने बस रूट्स हैं जिन्हें बसों की कमी के कारण बंद कर दिया गया है? इसके अलावा उप-मुख्य मंत्री जी क्या माननीय सदन को आश्वस्त करेंगे कि उन सभी रूट्स को बहाल कर दिया जाएगा?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चम्बा जिला में 203 बसें चल रही हैं। ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए। मैंने भी आपको आराम से सुना है और आप भी मुझे सुन लीजिए। (***)...(व्यवधान)

Speaker: This is not a part of the reply. ...(Interruption). This is in lighter way. This will not form part of the record.

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।**

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

8.03.2026/1150/ए.पी. /एच.के. -1

प्रश्न संख्या : 3857 जारी.....
उप-मुख्य मंत्री जारी ....

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इतनी देर खड़े होकर उन्होंने पूरी वकालत की है और आप कह रहे हैं कि 'not a part of reply'. एम0एल0ए0 सक्षम है अपनी बात रखने के लिए। अगर उन्होंने इतनी वकालत की है तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है। अध्यक्ष महोदय, वहां से 6 बसें चम्बा आती हैं और आगे कनेक्टेड बसें भी बिल्कुल हैं। एक बस तो टांडा-नगरोटा जा रही है। लेकिन जिन बसों से केवल 10-12-15 रुपये की

कमाई हो रही है, उन बसों को नहीं चलाया जा सकता। इसलिए बस तभी चलेगी जब उसकी कमाई 40-50 रुपये हो, या थोड़ी बहुत तो हो। खाली बसों को हम नहीं चला सकते। इसलिए मैं व्यवहारिक बात कह रहा हूं और इस पर राजनैतिक बात करना सही नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय डी0एस0 ठाकुर जी।

श्री डी0एस0 ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 7 बसें चम्बा से टांडा के लिए चलती हैं। ठीक है, वे चलती हैं लेकिन यह भी सोचिए कि सलूणी और लंगेरा की दूरी चम्बा से ही 100 किलोमीटर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मरीज पहले चम्बा आएगा और उसके बाद उसे टांडा रेफर किया जाएगा। ऐसे में तो मरीज रास्ते में ही मर सकता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस रूट पर बस बहुत जरूरी है और यह पिछड़ा क्षेत्र भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार शिक्षा और स्वास्थ्य पर यह बयान दिया है कि इन क्षेत्रों में अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा। उसी बजट से आप हमें एक बस दीजिए ताकि हमारे लोगों को सुविधा मिल सके। दूसरी बात, अगर मैं चम्बा डिपो की स्थिति पर ध्यान दिलाऊं तो परिवहन विभाग की 110 बसों में से 70 बसें पंद्रह साल पुरानी हैं जो जगह-जगह खराब होकर खड़ी हो जाती हैं। अगर प्राइवेट रूट न हो तो एच0आर0टी0सी0 की हालत बहुत खराब है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी, आप चम्बा का दौरा करें और देखें कि वहां बसों की हालत कितनी खराब है। अभी जो नई बसें आ रही हैं,

18.03.2026/1150/ए.पी. /एच.के. -2

उनमें से कम-से-कम 20 बसें चम्बा को दी जाएं। क्योंकि हमारा क्षेत्र पहाड़ी और दुर्गम है, बसें जल्दी खराब हो जाती हैं और रास्ते में खड़ी हो जाती हैं।"

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एच0आर0टी0सी0 इस समय 3200 रूटों पर बसें चला रही है। जिससे पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख लोग अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। यह धारणा होना कि एच0आर0टी0सी0 की हालत खराब है, यह सही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एच0आर0टी0सी0 की बसें एक तय फार्मूले के तहत चलती हैं। जिन बसों की लाईफ 15 वर्ष

पूरी हो जाती है या जो बसें 9 लाख किलोमीटर चल चुकी होती हैं, उन्हें फ्लीट से हटा दिया जाता है। यह कहना कि एच0आर0टी0सी0 पुरानी बसें चला रही है, यह गलत है। जो बसें अभी चल रही हैं, उनकी लाईफ अभी पूरी नहीं हुई है और न ही वे बसों 9 लाख किलोमीटर चली हैं। इसलिए वे बसें अभी भी चल रही हैं। अब आप कह रहे हैं कि नई बसें आएंगी और आपको दी जाएं। जब नई बसें आएंगी, उस समय निर्णय लिया जाएगा। पिछली बार भी चम्बा के लिए आपने यही कहा था और उस समय परिवहन विभाग ने आपको 10 नई बसें दी थी। चम्बा को उस समय सबसे अधिक बसें मिली थीं। लेकिन इस समय की स्थिति के मुताबिक यह एक सैद्धातिंक फैसला है। जहां तक बसों को बंद करने की बात है, कई जगहों पर बसें केवल 10-12-15 रुपये तक किराया दे रही हैं। उन बसों को चलाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे रूट खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हमारे किराए कम हैं और चंडीगढ़ तक हमारी बसें चल रही हैं, क्योंकि हमें लोगों को गंतव्य तक पहुंचाना है। लेकिन चंडीगढ़ से आगे दिल्ली तक जो बसें जाती हैं, वे सारी समच पर चली हुई है। कहीं पर दिल्ली-चम्बा, धर्मशाला-चम्बा, हमीरपुर-चम्बा चली हैं और उनमें केवल 10 सवारियां बैठती हैं। इसलिए हम रेशनलाइज कर रहे हैं कि एक समय पर एक ही बस जाएगी और वह पूरी तरह भरी होगी। यह तो हमारे माननीय सदस्यों का शौक हो गया है कि सब कहते हैं कि बैजनाथ-चम्बा, धर्मशाला-चम्बा रूटों पर बसें चलनी चाहिए। लेकिन चंडीगढ़ से आगे सवारी ही नहीं है, बसें खाली जा रही हैं। मैं सदन के समक्ष आग्रह करता हूं कि हम आपके सामने पूरा शिट रख देंगे। आप देख लीजिए कि यदि चंडीगढ़ से आगे सवारी है तो हम उस रूट पर बस चलाएंगे, अन्यथा जहां-जहां जरूरत है, वहीं बसें चलाई जाएंगी। मैं

18.03.2026/1150/ए.पी. /एच.के. -3

आपको बता दूं कि आपके विधान सभा क्षेत्र में 63 बसें चल रही हैं। मैं उनके आंकड़े आपके सामने रख दूंगा। आप देख लीजिए कि उनका माइलेज कितना है और उस रूट पर कितनी कमाई हो रही है। आप बता दीजिए कि किसे रद्द करना है और किसे चलाना है, हम वैसा कर लेगे।

अध्याक्ष जारी .....

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1155 /AT/ HK/01

प्रश्न संख्या 3857जारी .....

अध्यक्ष : माननीय जय राम ठाकुर जी।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह प्रश्न केवल डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित है... (व्यवधान) यह प्रश्न एक ऐसी जगह फंस गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में एच0आर0टी0सी0 जब से है यह एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते यह ठीक है कि प्रॉफिटेबिलिटी उल्लेखनीय होती है लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे रूट पर बस देना जनहित में आवश्यक होता है और यह काम आज से नहीं वर्षों से किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह क्राइटेरिया, जिसका आप जिक्र कर रहे है क्या यह अक्षरशः लागू हो रहा है? या आप हिमाचल प्रदेश में सत्ता पक्ष के विधायकों के नोट पर बसें और रूट स्वीकृत कर देते हैं? जबकि विपक्ष बार-बार एक बस के लिए आग्रह करता रहता है। माननीय विधायक महोदय एक बस के लिए आग्रह कर रहे हैं और उस पर आपने बहुत गंभीर टिप्पणी की। विधायक महोदय जी को कहना पड़ा कि इससे बेहतर तो फिर हम जम्मू-कश्मीर की बार करें... (व्यवधान)

अध्यक्ष : सप्लीमेंट्री, प्लीज।

श्री जय राम ठाकुरः तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे? मैं यह कह रहा हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में दर्जनों बसें आपने बंद कर दीं। जिस दिन सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न था उस दिन बसें पहुंचीं लेकिन उसके बाद वे बसें फिर बंद पड़ी हैं। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में भी जहां viable routes हैं वहां बसें चलाई जाएंगी? क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे? क्योंकि

इनका नजरिया सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों तक सीमित है यह सच्चाई है, अध्यक्ष महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं।

18.03.2026/1155 /AT/ HK/02

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन हैं हम इनका सम्मान करते हैं। लेकिन इनकी कांस्टीट्यूएंसी में जब डिजास्टर ... (व्यवधान) आप सुनते नहीं हैं, अपनी बात रख लेते हैं। जब चुनाव क्षेत्र में डिजास्टर आया वह इस स्तर का था कि बसें बंद करनी पड़ीं। उसके बाद जहां-जहां सड़क खुली है और यदि आपको लगता है कि कोई बस बंद हो गई है और सड़क अब खुल गई है तो हम उस सड़क पर बस चला देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है। यह सरकार पूरी तरह संतुलित काम कर रही है। विकास में संतुलन है, काम में संतुलन है और बस देने में कोई भेदभाव नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्षः **अगला प्रश्न 3858 माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया जी। अनुपस्थित। अगला प्रश्न 3559 माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह निक्का जी।** ...**(व्यवधान)** Hon'ble Member Shri Rakesh Kalia is not on his seat then what can I do? ...**(व्यवधान) माननीय सदस्य,** आपने प्रश्न पूछना है तो जरा आराम से बैठिये। ...(Interruption)**.** Hon'ble Member please behave yourself**.**

प्रश्न संख्या 3858 श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी **.....**

18.03.2026/1200/केएस/वाईके/1

प्रश्न संख्या : 3858

श्री राकेश कालिया : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना दी गई है उसमें यह कहा गया है कि लाइट्स लगाने पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि इसके ऊपर खर्चा ज्यादा आता है। लाइटों के लिए अगर कनेक्शन लें तो उसका खर्चा अलग से है। आजकल सोलर लाइट्स चल पड़ी हैं तो मेरा उप-मुख्य मंत्री जी से प्रश्न रहेगा कि क्या आप वहां सोलर लाइट्स के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चिन्तपुरनी से

गगरेट तक और गगरेट से पंजाब के बॉर्डर तक कुछ सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं की मृत्यु ना हो?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे और फोरलेन को छोड़कर माननीय सदस्य जहां भी और जिस भी पद्धति से लाइटें लगाने के लिए कहेंगे, हम तैयार हैं।

श्री राकेश कालिया : सर, मेरा मंदिर से सम्बन्धित एक और प्रश्न है। वहां पर अभी कोर्ट के फैसले के अनुसार गरीब लोगों को शादियों हेतु पैसा देने और गरीब लोगों को इलाज के लिए पैसा देने पर रोक लगी है। कई लोग उसमें केस करते रहते हैं। चिन्तपुरनी मंदिर एक डिस्प्युटिड सा टैम्पल बन गया है जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश के मंदिर सैटल हो चुके हैं। बाबा बालक नाथ मंदिर, नैना देवी मंदिर, बजरेश्वरी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर आदि के सरकार ने फैसले कर दिए हैं। मैंने पिछली सरकार के समय में भी प्रयास किया था लेकिन शायद किसी ने मुख्य मंत्री जी के कान में कुछ कह दिया होगा और चिन्तपुरनी का मामला रुक गया था। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सभी मंदिर सैटल हो गए हैं। वहां कोर्ट में तब मैटर जाता है जब उनके कोई इशूज़ होते हैं। एक बार बैठ कर जितना बाकी मंदिरों को दिया है, उतना ही चिन्तपुरनी वालों को भी दिया जाए क्योंकि वहां पर भी 600-700 शेयर होल्डर्ज़ हैं। क्या आप विचार रखते हैं कि ये मंदिर के डिस्प्यूट रोज़ कोर्ट में ना जाएं? दूसरे, जो हमारे बिल्ज़ वगैरह रुके हैं, वे भी आराम से चलते रहेंगे क्योंकि वे ही लोग कोर्ट में जाते हैं। क्या चिन्तपुरनी मंदिर का फैसला भी सरकार बाहर ही कर लेगी और जो बाकियों को मिल रहा है, मैं यह नहीं कहता कि उनको ज्यादा मिले, बल्कि उनको दो परसेंट चाहे कम ही दो लेकिन इस काम को करवा दो। मैं लगभग 20 साल से इस

माननीय सदन में हूं और मैं भी वहां का छोटा-मोटा पार्टनर हूं। 2-3 लाख रुपये मुझे भी वहां से साल के आते हैं।

मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप बाहर फैसला कर लेंगे ताकि हमें हाईकोर्ट के चक्करों से छुटकारा मिल सके? सरकार कोई फैसला कर दें, मैं यह आश्वासन चाहता हूं।

Speaker: This part of the Question, I am entertaining under the Zero Hour because the Question Hour is over. I would request the Hon'ble Chief Minister to reply to the queries which have been raised by the Hon'ble Member Shri Rakesh Kalia.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चिन्तपुरनी मंदिर से सम्बन्धित बात की। हाईकोर्ट ने उसमें कुछ ऑब्ज़र्वेशन्ज़ लगाई हैं। मैं माननीय **सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ऑब्ज़र्वेशन्ज़ को हम ठीक करवाएंगे और पहले जो प्रथा चली आई है, हम उस प्रथा को बढ़ाने की दिशा में आगे विचार करेंगे।**

श्री राकेश कालिया : सर, हम चाहते हैं कि उसमें कम्प्रोमाइज़ हो जाए।

अध्यक्ष : कालिया जी, आप अलग से नोटिस दे देना।। will allow that.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो हमारे ध्यान में बात लाई है, मैं इस पर पूरा विचार करुंगा, आप निश्चिंत रहें। जो भी हो सकता होगा, हाईकोर्ट की डेट को भी हम देख रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जो कम्प्रोमाइज़ करने के बारे में इनके विचार हैं, उसके बारे में हम आगे हाईकोर्ट में लड़ेंगे और मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा इशूज़ नहीं हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे।

Speaker: Thank you. I have not received any issue under the Zero Hour.

18.03.2026/1200/केएस/वाईके/3

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे। Item number 2 I am taking up.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार हैः-

बुधवार, 18 मार्च, 2026- (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा

वीरवार, 19 मार्च, 2026- (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) अनुपूरक बजट प्रथम एवं अन्तिम किस्त वित्तीय वर्ष 2025-26-प्रस्तुतिकरण एवं पारण।

i. सामान्य चर्चा
ii. मांगों पर चर्चा एवं मतदान, और
iii. विनियोग विधेयक-पुरःस्थापना, विचार-विमर्श एवं पारण।

(3) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा।

शुक्रवार, 20 मार्च, 2026- (1) शासकीय/विधायी कार्य।

(2) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-चर्चा एवं पारण। शनिवार, 21 मार्च, 2026- बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2026-2027-प्रस्तुतिकरण

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2026/1205/av/yk/1

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है :-

(1) हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 4);

(2) अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2026 का अधिनियम संख्यांक 5);

(3) हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 6); और

(4) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2026 का अधिनियम संख्यांक 7)

18.03.2026/1205/av/yk/2

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा

अध्यक्ष : अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुती है। इस प्रस्ताव पर चर्चा हेतु कुल तीन दिन का समय निर्धारित किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री दिनांक 20 मार्च, 2026 को इस चर्चा का उत्तर देंगे। समय की उपलब्धता को देखते हुए प्रस्तावक को 20 मिनट्स और इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन करने वाले को 15 मिनट्स, नेता प्रतिपक्ष जी को 25 मिनट्स तथा अन्य सदस्यों को 10 से 15 मिनट्स का समय मिलेगा। अतः मैं चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्य इसी समयसीमा में रहकर अपनी-अपनी बात रखें और जिन बिन्दुओं पर पहले ही चर्चा हो चुकी हों उन्हें न दोहराएं।

अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता हूं :-

"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का दिनांक 16 फरवरी, 2026 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का दिनांक 16 फरवरी, 2026 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"

अब माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार चर्चा में भाग लेंगे।

18.03.2026/1205/av/yk/3

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिनांक 16 फरवरी, 2026 को पढ़ा था। मैं इसमें थोड़ा-सा विचलित इसलिए हुआ हूं क्योंकि राज्यपाल महोदय ने संवैधानिक परिपाटी से हटकर इस अभिभाषण के मुख्य बिन्दुओं को पढ़ने में कुछ गुरेज किया। हालांकि राज्यपाल महोदय इस सरकार के मुखिया हैं और एक मुखिया होने के नाते उनको इस सरकार की उपलब्धियों तथा सरकार के सामने आने वाली उन तमाम चुनौतियों का ब्यौरा रखना होता है।

टी सी द्वारा जारी

18.03.2026/1210/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री सुरेश कुमार... जारी

लेकिन पता नहीं किन कारणों या दबाव के कारण उन्होंने अभिभाषण में यह कहा कि जो लिखा गया है, वह पढ़ा हुआ समझा जाए जबकि यह सदन की गरिमा और कार्यवाही के विपरीत है। फिर भी मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के लिए धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को बने हुए 3 वर्ष 3 महीने हो गए हैं। इन 3 वर्ष 3 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए लोकहित के वे फैसले लिए हैं जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए अति आवश्यक थे। हमारी यह सरकार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वह सरकार है जिसको अभी तक की सभी सरकारों में सबसे ज्यादा चुनौतियां, सबसे ज्यादा आर्थिक संकट और इस प्रदेश को आगे ले जाने से जुड़ी सबसे अधिक चिंताएं मिली हैं। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार प्रदेश-हित में बेहतर कार्य कर रही है। हमारी सरकार अपनी संवेदनशीलता, वचनबद्धता, जिम्मेदारी व पूरी ईमानदारी के साथ से काम कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की संवेदनशीलता इसी बात से झलकती है कि जब हमारी सरकार का गठन हुआ और मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की, उस समय सामान्यतः यह परंपरा रही है कि शपथ ग्रहण के बाद मुख्य मंत्री अपने कार्यालय जाते हैं। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने ऐसा न करते हुए उस स्थान पर जाना उचित समझा जहां वे बच्चे रहते हैं जिनका कोई सहारा नहीं है जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और जो अनाथ आश्रम में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी वहां गए, उन्होंने बच्चों का हाल जाना और उनके साथ कुछ समय बिताया। सामान्यतः मुख्य मंत्री अपना समय कार्यालय में बिताते हैं लेकिन यह कोई सामान्य घटना नहीं थी और न ही यह कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम था। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच का परिचायक था और एक स्पष्ट संदेश था कि हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करेगी और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेगी जो व्यक्ति बेसहारा है, जिसकी आवाज नहीं सुनी जाती है उस व्यक्ति की आवाज यह सरकार बनेगी। यह संकेत मुख्य मंत्री जी ने अपने उस भ्रमण के माध्यम से दिया और उन बच्चों के साथ बिताए गए पलों से यह स्पष्ट किया।

18.03.2026/1210/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष महोदय, यह बात यहीं तक सीमित नहीं रही। इसके उपरांत सरकार ने कार्य आरंभ किया और उन बच्चों के लिए योजनाएं प्रारंभ कीं। उनके लिए सुखाश्रय जैसी योजनाएं लाई गईं। बेसहारा विधवाओं के लिए भी योजनाएं लाई गईं और सरकार ने अपनी

संवेदनशीलता को व्यवहार में प्रदर्शित किया। हमारी सरकार को इन 3 वर्षों में 3 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती वर्ष 2023 में आई, जब इस प्रदेश ने अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना किया। इस आपदा के कारण पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई कि प्रदेश अन्य राज्यों से कट गया और लगभग 500 लोगों की मृत्यु हुई। अनेक घर बह गए, सड़कें नष्ट हो गईं, पानी की स्कीमें बह गईं और प्रदेश को आर्थिक तथा प्राकृतिक रूप से भारी नुकसान हुआ। उस समय नई-नई सरकार बनी थी और आपदा हमारे सामने खड़ी थी। लेकिन मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जिस तत्परता से कार्य किया, वह पूरे देश में एक मिसाल बना। मुख्य मंत्री जी स्वयं जीरो ग्राउंड पर गए। अनेक मंत्री और विधायक भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और उन लोगों के बीच गए जिन्हें उस समय इस सरकार संवेदनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता थी।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा .... जारी

18-3-2026/1215/NS-AG/1

श्री सुरेश कुमार ----जारी

इस सरकार ने उस संवेदना को भी समझा और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उस वक्त हिमाचल प्रदेश के अंदर 9200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और यह सिलसिला वहां भी नहीं थमा। वर्ष 2024 में फिर दूसरी आपदा आई और फिर उसी तरीके से यह प्रदेश मुश्किल में पड़ा। वर्ष 2025 में तीसरी बड़ी आपदा आई और इस आपदा का प्रभाव उससे भी ज्यादा था तथा हमारा तीन गुना ज्यादा नुकसान हुआ। मंडी, कुल्लू, चंबा का क्षेत्र और पंजाब से लगते हुए सारे जिले इस आपदा से प्रभावित हुए। पूरा प्रदेश इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ और तीसरी बार फिर हिमाचल प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, हमारे ऊपर 3 वर्षों में इतनी बड़ी मुश्किल आई और उस मुश्किल को हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत, होशियारी व बड़ी सहनशीलता के साथ पार किया और जिसका जो हक बनता था वह हक हमने जनता तक पहुंचाया। हमने पुनर्वास के कार्यों को तुरंत पूरा किया, हमने सड़कों को खोलने का कार्य किया, शिक्षण संस्थानों को खोलने का कार्य किया, हमने पानी की स्कीमों को खोलने का कार्य किया, हमारी सरकार

ने बसों की आवाजाही को सुनिश्चित किया और हम प्रदेश को बहुत अल्प समय के अंदर दोबारा उस स्थिति में लेकर आए तथा यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

अध्यक्ष महोदय, हम इस प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे थे और उस समय हमारे ऊपर दूसरी बड़ी राजनीतिक आपदा आई। उस राजनीतिक आपदा में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया, विधायकों को खरीदने का प्रयास हुआ, पंजाब व हरियाणा की पुलिस यहां पर एंटर हुई और इस सरकार को अस्थिर करने व गिराने का प्रयास किया गया। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है और यह सदन उस बात का गवाह है। उस समय सदन चल रहा था, बजट सत्र हो रहा था और उस वक्त ऐसा माहौल बनाया गया कि यह सरकार अब ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। मैं आपको स्मरण करवाना चाहता हूं कि उस वक्त विपक्ष के नेता आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने इसी सदन में दोनों हाथ खड़े करके कहा था कि अब इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है लेकिन हम भगवान और हिमाचल प्रदेश की जनता के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सरकार को भी बचाया और इस सरकार को दोबारा से समर्थन देकर 40 सीटों पर पहुंचाया। इसके लिए हम

18-3-2026/1215/NS-AG/2

जहां भगवान का धन्यवाद करते हैं वहीं हम प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर ये दूसरी आपदा थी। अध्यक्ष महोदय, पहली प्राकृतिक आपदा, दूसरी राजनीतिक आपदा और तीसरी हमारे ऊपर आर्थिक आपदा आई है। उस आर्थिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक ढांचे को झकझोर कर रख दिया है। हमारी आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी। हमें लोन के रूप में 70,000 करोड़ रुपये विरासत में मिले हैं। इस प्रदेश की जो केंद्रीय ग्रांट्स थीं उनको बंद करने का काम किया गया। केंद्र सरकार ने हमारी बहुत सारी योजनाओं का पैसा रोकने का काम किया। हमारी सरकार के ऊपर वज्रपात उस वक्त हुआ जब इस प्रदेश की जो आर0डी0जी0 थी उसको खत्म करने का ऐलान केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने कर दिया। 50,000 करोड़ रुपये 5 वर्षों के अंदर इस सरकार के केंद्र सरकार ने कम कर दिए। एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश के 10,000 करोड़

रुपये केंद्र सरकार ने बंद कर दिए। हमने जो योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए लानी थीं उनको बंद करने का एक तरह से ऐलान केंद्र सरकार ने किया। हमारे ऊपर आर्थिक आपदा को थोपा गया और

आर0के0एस0 द्वारा----जारी

18.03.2026/1220/RKS/AS-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

केंद्र सरकार द्वारा हमारे गले में हाथ रखकर सांस रोकने का प्रयास किया गया। जब हमारी आर0डी0 जी0 बंद हुई तो हमने बार-बार विपक्ष के साथियों से सहयोग मांगा। जब प्रदेश के अंदर प्राकृतिक आपदा आई थी तो हमने इसी तरह विशेष सत्र बुलाया था। हम उस सत्र में प्रस्ताव लेकर आए कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया जाए और राष्ट्रीय आपदा के तहत जो-जो सहायता केंद्र से मिलती है, वह हमें मिलनी चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस प्रस्ताव के समय भी विपक्ष के लोगों ने वाकआउट कर दिया। वह प्रस्ताव प्रदेश हित में लाया गया था और यह हमारे प्रदेश के लोगों की मांग थी। उस वक्त हमारा प्रदेश आर्थिक बदहाली और आपदा के दौर से गुजर रहा था लेकिन उस वक्त भी विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा और वे सदन से वाकआउट कर गए। एक तरह से इन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध किया। आज हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। केंद्र सरकार द्वारा हमारी आर0डी0जी0 बंद कर दी गई है। हमारी सरकार ने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की थी जिसके माध्यम से हम सारी स्थिति को इस सदन व प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग, आमजन और समस्त जनता के समक्ष रखना चाहते थे। क्योंकि यह प्रदेश हित की बात थी और प्रदेश की आर्थिक स्थिति से हमारे प्रदेश के बच्चे-बच्चे को जरूर वाकिफ होना चाहिए। हम प्रदेश की जनता से यह बात नहीं छुपा सकते हैं कि हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है? यह हमारी सरकार की जिम्मेवारी है और यही हमारी सरकार की संवेदनशीलता भी है। हम हर स्थिति को जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से रखना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस प्रेजेंटेशन का शुभारंभ किया और वित्त सचिव ने उन सारी समस्याओं और तमाम चुनौतियां को प्रदेश के सामने रखा कि अगर

हमारी आर0डी0जी0 बंद होती है तो हमें किन-किन चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। हमारे समक्ष कौन-कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं, उन सब चीजों का जिक्र उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से किया गया। हमारे कर्मचारियों व समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं वे सारी बातें सामने रखी गईं। किन-किन योजनाओं के ऊपर सरकार को कैंची चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, ये सारी बातें उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताई गई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस प्रेजेंटेशन में भी विपक्ष के लोगों ने भाग नहीं लिया। यह प्रदेश हित की बात थी। उस प्रेजेंटेशन के

18.03.2026/1220/RKS/AS-2

माध्यम से हम प्रदेश की जनता को सही स्थिति बताना चाहते थे लेकिन उसमें विपक्ष के लोग अपनी जिम्मेवारी से भाग गये। उस समय पूरा विपक्ष नदारद रहा। यह दूसरा समय था जब विपक्ष के लोग प्रदेश हित के साथ खड़े नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आपदा से निकलते हुए हमारी सरकार ने तीन वर्ष का चुनौतीपूर्ण कार्यकाल पूरा किया है। यह हमारी सरकार का चौथा बजट है। सरकार बनने के बाद हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नारा दिया कि हम इस प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन कोई एक शब्द या कागज में लिखा हुआ कोई आम अक्षर नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश का भविष्य है। व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश के युवाओं की तकदीर है। हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन लेकर आई है। व्यवस्था परिवर्तन भले ही कई लोगों को अटपटा शब्द लगता हो लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन से हम हिमाचल प्रदेश को जिस परिस्थिति में लेकर आए हैं उससे हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हमारी सरकार दिन-रात प्रयासरत है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब लोग पूछेंगे कि व्यवस्था परिवर्तन क्या था तो वे इस बात का जरूर एहसास करेंगे कि किस प्रकार हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन किया था। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय,

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

18.03.2025/1225/बी.एस./ए.एस.-1

श्री सुरेश कुमार जारी...

हमारी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन को आगे बढ़ते हुए और इन चुनौतियों को, जो चाहे आर0डी0जी0 की वजह से हुई हो या पिछली सरकारों के कुप्रबंधन की वजह से हुई हो, उससे पार पाने के लिए हमने एक रोडमैप तैयार किया और इस रोडमैप के माध्यम से सरकार ने अपना अगला कदम बढ़ाया। पहली बार हिमाचल प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई इस सरकार ने लड़ी। इसे प्रदेश के अंदर भी लड़ा और न्यायालय के अंदर भी लड़ा गया और केंद्र सरकार के समक्ष भी लड़ा गया। यह पहली सरकार है जिसने हिमाचल प्रदेश के हितों की बात कही और हर स्तर पर कही गई और पूरे जिम्मेवारी के साथ कही गई। पूरी हिम्मत के साथ कही गई। उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए थे। जो मामले केंद्र के पास अटके थे, हमने सबसे पहले उनको हल करने की कोशिशि की। हमने वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला कोर्ट में लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में गए और हम सुप्रीम कोर्ट में जीते। हमने अच्छे वकील वहां पर किए और उसका नतीजा हुआ कि 500 करोड़ रुपए की वह प्रॉपर्टी हमें सालाना 5 करोड़ रुपए इनकम दे रही है। यह व्यवस्था परिवर्तन का एक नतीजा था।

इसी के साथ जी0एस0डब्ल्यू0 का केस था, उसको भी हमने गंभीरता से लड़ा और उसमें हमाने अपने अधिकारों की बात की और कोर्ट ने हमें सही माना। आज उससे भी दो करोड़ रुपए सालाना प्राप्त हो रहे हैं और उसमें हमें 400 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में मिला। हमारी सरकार के ये कदम आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में थे और 150 करोड़ रुपये सालाना उससे जी0एस0टी0 के रूप में हमें मिलेगा।

इसी के साथ हमारी जो लिकर पॉलिसी थी, उसको भी हमने बदला। लिकर पॉलिसी में पिछले 5 वर्षों से उसी को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाता था और इसी तरह से वह चल रही थी। हमने उस स्थिति में कितना पैसा कमाया? 450 करोड़ रुपये। इसमें हम लोग बदलाव लेकर आए। पहली वर्ष में सरकार ने 460 करोड़ रुपये अर्जित किये और हमने

सरकारी खजाने में इसे जोड़ा। यह हमारी व्यवस्था परिवर्तन के कुछ काम हैं, जो कदम हमने इस हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाए हैं।

18.03.2025/1225/बी.एस./ए.एस.-1

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की आर्थिक स्थिति कैसे बदले? इस प्रदेश के पास कौन से ऐसे साधन हैं जिससे हमारे प्रदेश की इनकम बढ़े? हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। हमारे माननीय सदस्य भी यहां पर बहुत सारे सुझाव देते हैं। मैं पिछले दिनों आदरणीय प्रकाश राणा जी का भी भाषण सुन रहा था। इन्होंने बड़े अच्छे, लच्छेदार तरीके से कहा, ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। लेकिन इन्होंने यह जिक्र नहीं किया जिस तरफ हम बढ़ चुके हैं, उसके लिए इन्हें धन्यवाद करना चाहिए था कि सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है।

इस प्रदेश की जो संपदा है, उसके दोहन से जो पैसा हमें आना चाहिए था, उसके लिए हमने वाटर सेस लगाने की एक नोटिफिकेशन की है। जो बिजली यहां पर बनती है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बिजली पानी से बनती है, उसमें जमीन हमारी और पानी हमारा है। लेकिन उसमें हमें हमारा जो उचित शेयर है, वह हमारे को नहीं मिलता था। हमने यह कहा कि हम वाटर सेस लगाएंगे और वाटर सेस की नोटिफिकेशन की। हमें उसके ऊपर पैसा मिलेगा, तो प्रदेश की खुशी होगी, प्रदेश की इनकम बढ़ेगी और वह पैसा विकास कार्य में लगेगा। इस सोच के साथ हमने वह काम किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस मामला में भी केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और उस काम को भी रोकने का कार्य केंद्र की सरकार ने किया। देर-सवेर वह पैसा हमें मिलेगा और हम कोर्ट में जीतेंगे और जो हमारा राइट है। उस राइट को हम लेकर रहेंगे।

इसके साथ बी0बी0एम0बी0 की बात आई। बी0बी0एम0बी0 में पहली बार सरकार ने अपना शेयर मांगा। जब यहां बी0बी0एम0बी0 के प्रोजेक्ट बने तो यहां से 300 के करीब हमारे जो परिवार थे वे बेघर हुए। उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ा। उनको अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। लेकिन हमें बी0बी0एम0बी0 से क्या मिला?

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.03.2026/1230/डीटी/डीसी-1

श्री सुरेश कुमार जारी....

आज भी हमारा एक हज़ार करोड़ रुपये उनके पास पड़ा है लेकिन वे उस पैसे को नहीं देते हैं। हमारी सरकार उस लड़ाई को भी लड़ रही है और निश्चित तौर पर अब हम BBMB से अपना अधिकार मांग रहे हैं। अब किसाऊ बांध और रेणुका बांध पर वे हमारे पास negotiation के लिए आए हैं। हमने अपना पक्ष बड़ी मजबूती के साथ रखा है। चाहे किसाऊ बांध हो या रेणुका बांध, उनकी मंजूरी इसी बात के ऊपर निर्भर करती है कि BBMB जो हमारे पिछले अधिकार बनते हैं उन्हें वे देते हैं या नहीं। यह प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारा दूसरा कदम है। इसी के साथ सानन बिजली प्रोजैक्ट के मामले को भी हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है। चंडीगढ़ में जो हमारे शेयर हैं उस मामले को भी हमारी सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ उठाया है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने वे सारे कदम उठाए हैं जो प्रदेश को खुशहाल करने व आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हो सकते हैं। हमने अनावश्यक खर्चों को कम करने की दिशा में प्रयास किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और हमने आज ही अखबार में पढ़ा कि उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कैबिनेट रैंक के अध्यक्षों की शक्तियों को कम किया है। इस तरीके से उनके ऊपर जो सैलरी इत्यादि का खर्च होने वाला था उसे सरकार ने 20 प्रतिशत कम किया है। इसी के साथ चाहे बिजली की सब्सिडी छोड़ने की बात हो, उसकी पहल भी हमने अपने से की है। जो विश्राम गृह थे उनके रेट को भी सभी लोगों के लिए एक समान किया है। चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, पूर्व मंत्री हो या आम नागरिक सबको इसका एक समान पैसा देना पड़ेगा। यह भी हमारी सरकार ने सुधार किया है। इसके साथ शिमला में कई ऐसे कार्यालय हैं जिन्हें हमने शिफ्ट किया है। हमारे दूसरे जिलों में भी बहुत सारे सरकारी भवन खाली पड़े हैं, हमने उन भवनों में यहां से दफ्तरों को शिफ्ट करने का काम किया है। हमने कई दफ्तर मंडी, कई धर्मशाला, कई हमीरपुर, कई

बिलासपुर ट्रांसफर किए ताकि शिमला का जो एक्सट्रा लोड है उसे कम किया जा सके और प्रदेश के दूसरे हिस्सों में जो भवन खाली पड़े हैं उनका सही यूज किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आज यहां पर 1 हज़ार करोड़ रुपए की जो बिल्डिंगें हैं वे खाली पड़ी हैं। यह सरकार का पैसा है। यह भवन बनकर तैयार हुए हैं लेकिन उनका उपयोग कोई नहीं हो रहा है। यह पैसे का दुरुपयोग है।

18.03.2026/1230/डीटी/डीसी-2

यह प्रदेश के खजाने का दुरुपयोग किया गया है। इसी तरीके से पिछले दिनों हम देख रहे थे कि आदरणीय जयराम ठाकुर जी के क्षेत्र में भी कुछ भवन बनें हैं। इनके क्षेत्र में भी 12 विश्राम गृह बनाए गए । मेरे चुनाव क्षेत्र के साथ लगते धर्मपुर क्षेत्र में भी 12 विश्राम गृह बना दिए और वे ऐसी जगह बने हैं जहां आज तक कोई नहीं ठहरा हुआ है। ऐसे- ऐसे विश्राम गृह बना दिए हैं जहां लोगों का कोई आना-जाना नहीं है। यह एक तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग समझा जाता है । माननीय मुख्यमं त्री जी ने एक और बड़ा और सुधार का काम किया है। इन्होंने प्रदेश का जो खजाना है उसको अनुशासित करने का काम किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेजरी बंद रहती है लेकिन जब ट्रेजरी खुली थी तो उसकी भी मैं बात बताता हूं। PWD, IPH और दूसरे विभागों में हमारे बहुत सारे ऐसे ठेकेदार/अधिकारी थे जो उस ट्रेजरी का मिसयूज करके करोड़ों रुपए का चूना प्रदेश सरकार को लगा रहे थे। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने treasury को अनुशासित किया और अब आप देखेंगे कि जरूरत के मुताबिक धन का बंटवारा किया जाता है। इसके साथ ही किसी की पेमेंट न रूके, पैसे का कोई मिसयूज न हो इसके लिए भी हमारी सरकार ने कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने कुछ

श्री एन0जी0 द्वारा जारी.....

18.03.2026/1235/डी.सी.-एन.जी./1

श्री सुरेश कुमार..... जारी

रिफॉर्म्स किए हैं। उसमें चाहे रेवेन्यू की बात हो तो हमारी सरकार ने राजस्व विभाग में बहुत बड़ा सुधार किया है। हमारी सरकार रेवेन्यू में एक एक्ट लेकर आई है। लोगों के ऐसे कई मामले जो सालों से पटवारखाने में या तहसीलों में लम्बित पड़े हुए थे और उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती थी। किसी ने अपनी भूमि की डिमार्केशन करवानी हो, किसी ने पार्टीशन या म्यूटेशन करवाना होता था तो कार्यालयों में लोगों का चक्कर काट-काट कर बहुत बुरा हाल हो जाता था। हमारी सरकार एक्ट लेकर आई और उस एक्ट का नतीजा यह हुआ कि 9500 इंतकाल पूरे प्रदेश के अंदर एक दिन में निपटाए गए। हमारी सरकार ने एक ही राजस्व अदालत में 9500 इंतकाल एक दिन में किए। अभी ऐसी राजस्व अदालतें हर माह लग रही हैं। वर्तमान में पटवारी स्वयं कह रहे हैं कि आइए और अपना इंतकाल, पार्टीशन, म्यूटेशन आदि कराइए। यह हमारी सरकार का बहुत बड़ा कदम है।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ हमने पटवारियों के कैडर को भी स्टेट कैडर किया। डी0सी0 ऑफिस, एस0डी0एम0 ऑफिस और तहसील का स्टाफ—इन सबको हमारी सरकार ने स्टेट कैडर किया। पहले होता क्या था कि जो पटवारी एक पटवारखाने में बैठा है, वह वर्षों तक वहीं बैठा रहता था और लोगों की सुनता नहीं था। इसी तरह जो स्टाफ तहसील, एस0डी0एम0 ऑफिस और डी0सी0 ऑफिस का था, वह भी एक ही जगह पर जमा रहता था और इससे लोग बहुत परेशान थे। हमारी सरकार ने फैसला किया कि इनका भी स्टेट कैडर होना चाहिए और इनका भी ट्रांसफर होना चाहिए ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृप्या वाइंड-अप कीजिए।

18.03.2026/1235/डी.सी.-एन.जी./2

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उस निर्णय की सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध पूरे प्रदेश में करने का प्रयास किया। हमने 900 से अधिक शिक्षण संस्थानों को बंद किया और यह फैसला कोई और नहीं ले सकता था। माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, श्री रोहित ठाकुर जी ने यह निर्णय लिया। हमने कौन-से शिक्षण संस्थानों को बंद किया, यह भी बताना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृप्या वाइंड-अप कीजिए।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, 675 स्कूल ऐसे बंद किए गए हैं जिनमें एक भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता था। 250 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक से पांच तक बच्चे थे। इसी प्रकार लगभग 400-450 स्कूल ऐसे थे जिनमें 15 से कम बच्चे थे। यानी के अध्यापक ज्यादा और बच्चे बहुत कम थे। हमने बहुत बड़ा फैसला लिया और उसका नतीजा यह हुआ कि आज हमारी एजुकेशन की रैंकिंग बढ़ी है। जहां हिमाचल प्रदेश पहले 18वें नंबर पर था, आज हम चौथे स्थान पर आ गए हैं और बहुत जल्द पहले स्थान पर आने वाले हैं।

इसके साथ ही हम डे-बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं और हर विधान सभा क्षेत्र में डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, जिनमें हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देने वाले हैं। हमने लगभग 200 स्कूल सी0बी0एस0ई0 किए हैं और उनका कार्य इसी सत्र से शुरू हो चुका है।...(घण्टी)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृप्या वाइंड-अप कीजिए।

18.03.2026/1235/डी.सी.-एन.जी./3

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान हमारी सरकार की एक बड़ी पहल है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। हमने 68 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए हैं, जिनमें 6-6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। पहली बार एम0डी0 डॉक्टर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में नियुक्त किए गए हैं। हर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में एक्स-रे व अल्ट्रासाउंड मशीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यहां तक की सर्जरी की सुविधा भी अब सी0एच0सी0 में उपलब्ध होने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए यह हमारी सरकार की दूरदर्शिता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृप्या वाइंड-अप कीजिए।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज अस्पतालों में पैथ लैब, टेसला व एम0आर0आई0 जैसी अत्याधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में रोबोटिक सर्जरी की भी शुरुआत हुई है। यह हमारी सरकार का स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है।

इसी के साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.03.2026/1240/ए.पी. /एच.के. -1

श्री सुरेश कुमार जारी .....

अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बेहतर कार्य किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिले, इस उद्देश्य से हमारी

सरकार दूध, मक्की, गेहू पर एस0एस0पी0 ले कर आई और आगे बढ़ते हुए हल्दी पर 90 रुपये का खरीद मूल्य तय किया। आज किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। इस वर्ष सरकार ने 90 रुपये के हिसाब से 13 टन हल्दी किसानों से खरीदी है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बड़ा साधन बन रहा है। इसके साथ ही डगबार में एक बड़ा मिल्क प्लांट हमारी सरकार लगाने जा रही है। जिस पर 650 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार ने बेहतर कार्य किया है और इसकी प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है। विरोध केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और कुछ प्रोजेक्टेड लोग जो सोशल मीडिया पर बैठे हैं। बाकी प्रदेश का कर्मचारी हमसे खुश है क्योंकि उन्हें ओ0पी0एस0 हमने दी है, किसान हमसे खुश है, युवा हमसे खुश है, बुद्धिजीवी वर्ग हमसे खुश है। हमारी सरकार जिस प्रकार कार्य कर रही है, हम मिशन रिपीट की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी इसमें सहयोग करे, क्योंकि प्रदेश बड़ी वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है और जनता देख रही है कि कौन प्रदेश के हितों के साथ है और कौन प्रदेश के विरोध में खड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।"

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी।

श्री जयराम ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुरेश कुमार जी ने सदन में मेरा और मेरे विधान सभा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए जो बातें कही हैं, मैं उस सारी बात को गंभीरता से खारिज करता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ खारिज करता हूं। किसी क्षेत्र में विकास करना उस क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि का दायित्व होता है। जो कहा गया कि 12 रैस्ट हाउस खोल दिए गए। आप बताइए कहां खोले गए? कुछ दिन पहले जब पिछली बैठक हुई थी, उसमें यह जिक्र आया था कि जे0जे0एम0 के अंतर्गत सिराज विधान सभा क्षेत्र और धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र को टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बात

कहना चाहता हूं कि वह रैस्ट हाउस नहीं हैं बल्कि इंस्पेक्शन हट की श्रेणी में है। बकायदा वे सभी डी0पी0आर0 की अप्रूवल के बाद उनका प्रावधान था। उसी प्रावधान के अंतर्गत वे बनाए गये हैं। जे0जे0एम0 के अंर्तगत पूरे देश भर में सबसे बेहतर काम करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश उस समय चुना गया था और हमें उसका इंसेंटिव भी मिला, यह आपको भी मालूम है। लेकिन बेवजह की बातों को लेकर बार-बार इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब ये बोल रहे है कि वह प्रावधान केवल आपके विधान सभा क्षेत्र में ही क्यों था? वे इस बारे में पूछ रहे है।

श्री जयराम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सिर्फ मेरे विधान क्षेत्र से ही पूछा गया था। लेकिन इसमें केवल मेरा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों पर इंस्पेक्शन हट के प्रावधान भी शामिल थे। दूसरी बात, मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि नकल करने की कोशिश हो रही है।

अध्यक्ष : आज तो माननीय मुख्य मंत्री जी बोले ही नहीं।

श्री जयराम ठाकुर : मुख्य मंत्री आज नहीं बोले लेकिन जो वे अपने भाषण के दौरान बोलते है कि 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बना दी गई है। यदि वह गलत बनी है तो बुलडोज़र लाइए और उसे तोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसा कब तक बोलते रहेगे। अगर किसी विधान सभा क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ है तो वह कार्य जनप्रतिनिधियों के कहने पर हुआ है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1245/AT/HK /01

श्री जय राम ठाकुर जारी ....

क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हुआ है। लेकिन बार-बार इस प्रकार के आरोप लगाना और इन बातों का बार-बार उल्लेख करना मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। यह एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसके लिए उन्हें क्षमा-प्रार्थी होना चाहिए।

मैं चुना हुआ विधायक हूं और मैंने अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में बिल्डिंगस् बनाई हैं। यदि हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए बिल्डिंग बनी हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र में बनी हैं। मुख्य मंत्री जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में भी बनी हैं जिनका आप आज बाजे-गाजे के साथ उद्घाटन कर रहे हैं। वह भवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बनाए गए हैं जिनका आप आजकल उद्घाटन कर रहे हैं और रिबन काटने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सहन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से गलत बातों का बार-बार जिक्र करना इसे आदत का हिस्सा मत बनइये।...(व्यवधान)

Speaker: Shri Jai Ram Thakurji, please take your seat.

श्री जय राम ठाकुरः आप जो काम करेंगे लोग उसे याद रखेंगे। हमने अगर काम किया है तो लोग उसे याद रखते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बार-बार इन शब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अगर कोई बात कही है तो उन्होंने कुछ तथ्य भी बताए होंगे।...(व्यवधान) 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंगें अपने मित्र ठेकेदारों के लिए आपने बनाई।....(व्यवधान)

Speaker: Please let him complete. मुख्य मंत्री महोदय मैंने तो इन्हें अलाउ ही नहीं किया है। ...(Interruption) Please take your seat. ...(Interruption) Please take your seat.

18.03.2026/1245/AT/HK /02

मुख्य मंत्रीः आप गुस्से में मत आया करें। अब अगर आदत बन गई है तो सच्चाई को आदत में बदलने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। सच्ची बात बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप धर्मपुर जाइए। मैं पहले धर्मपुर में गिना देता हूं। वह भी इनके बड़े मित्र थे। आप बोल रहे हैं कि मित्र बताइए, तो मैं मित्र का ...(व्यवधान) मैं आपको एक बात बता रहा हूं ...(व्यवधान) सुनिए तो सही आप क्यों गुस्सा होते हैं? मैं आपको याद दिला रहा हूं कि बिल्डिंग बना दी गई है लेकिन खाली पड़ी है। अब कुछ ऑफिस मंडी शिफ्ट करने पड़ेंगे। शिव धाम जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था वह तो मैं बना रहा हूं। आप तो केवल फाउंडेशन स्टोन रखकर गए थे। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आपका दोष है ...(व्यवधान)

Speaker: Let him complete. ...(Interruption) Please take your seat.

मुख्य मंत्री : मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हम सृष्टि के रचयिता शिव धाम के लिए पूरे पैसे देंगे। आपने जो 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनाई है वह सच्चाई में खाली पड़ी है।...(व्यवधान) अभी सूची आ रही है। आपने अभी सवाल पूछा है। मैंने कहा और इकट्ठा कर रहे हैं। आपके ही आदमी ने पूछा है कि कितनी बिल्डिंग हैं। उसका जवाब हम आपको अगले सत्र (नवंबर) में देंगे पूरी विवरण और नक्शे के साथ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि शिव धाम हम बना रहे हैं। हमें भगवान शिव का आशीर्वाद है और देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी है। इसलिए सरकार भी बची है और दोबारा 40 विधायक भी पहुंचे हैं।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1250/केएस/वाईके/1

मुख्य मंत्री जारी ---

इसलिए जो विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर कह रहे हैं, यह आपकी गलती नहीं है, आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने अंधाधुंध किया। आपको तो उन्होंने यह बताया कि मैंने छतरी में आई0टी0आई0 की 50 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बना दी जिसमें 32 बच्चे बैठेंगे ।

वहां 32 बच्चे हैं। नाचन में जहां हमने होर्टिकल्चर का कॉलेज शिफ्ट किया, वहां पूरी बिल्डिंग खाली है। वहां हमने होर्टिकल्चर का कॉलेज इसलिए शिफ्ट किया ताकि उस खाली बिल्डिंग का इस्तेमाल हो सके। सरकाघाट में आपने एक्स सर्विसमैन सैल के नाम से एक बिल्डिंग बना दी जो कि बिल्कुल खाली पड़ी है। ...(व्यवधान) तैयार उसको हम कर रहे हैं ताकि उसमें अटल यूनिवर्सिटी खोल सके। हमने उसकी फिनिशिंग के लिए पैसे दे दिए हैं। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं कि पूर्व मुख्य मंत्री जी की नाक के नीचे बिल्डिंगें बनती गईं। वाकनाघाट में चाहे वह ए0डी0बी0 प्रोजैक्ट के तहत बिल्डिंग बनी, प्रोजैक्ट खत्म हो गया। वहां आई0टी0 वालों की 100 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनी लेकिन अभी तक उसका छत नहीं डाल पाए। अध्यक्ष महोदय, हमने चम्बा के मैडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को पूर्ण करने के लिए 175 करोड़ रुपये दिए। हमीरपुर के मैडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को पूरा करने के लिए पैसे दिए। हमने पैसे का सदुपयोग किया। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पैसे का दुरुपयोग किया, हम यही कह रहे थे और इसीलिए कहा गया कि 1000 करोड़ रुपये की बिल्डिंगें बना कर रख दीं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप इन्हीं को गिनाते रहेंगे या खुद भी कुछ काम करेंगे? यही बाजा, यही ढोल आपका पिछले तीन साल से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जहां डवलपमेंट की जरूरत लगती है अगर हमने उसको पूरा किया तो मैं समझता हूं कि हमने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की, कोई पाप नहीं किया । ये सरकाघाट की बिल्डिंग का ज़िक्र कर रहे हैं, इनकंप्लीट बिल्डिंग को कैसे फंक्शनल कर सकते हैं? जिस परपज़ के लिए वह बनाई गई थी, उस इलाके से बहुत बड़ी संख्या में नौजवान फौजी हैं और बाकी बहुत सारे नौजवान भी फौज में जाना चाहते हैं। जब वह फंक्शनल होगी तब वहां पर अकैडमी शुरू हो पाएगी।

18.03.2026/1250/केएस/वाईके/2

...(व्यवधान) आप करिए ना आप क्या कर रहे हैं? आप उस अकैडमी को फंक्शनल करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि वहां पर जगह नहीं रहेगी। उसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा। इसी

तरह से नाचन विधान सभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय की बिल्डिंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अगर आप बिल्डिंग का कार्य पूर्ण होने के बाद उसको फंक्शनल करते हैं, वहां पर उस स्कूल को चलाते हैं तो स्कूल की वह बिल्डिंग जिस परपज़ के लिए बनाई, उसका परपज़ पूरा होगा और ऑप्रेशनल होने के बाद वह पूरी बिल्डिंग युटिलाइज़ होगी। इसलिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने तो कुछ करना नहीं है लेकिन हमने जो जिस परपज़ के लिए किया है, उससे हटकर जो आप शरारतपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि किसी मैडिकल युनिवर्सिटी को यहां से वहां बदल दो, कहीं होर्टिकल्चर कॉलेज बदल दिया तो यह सोच आपकी बहुत निम्न स्तर की है। यह मुख्य मंत्री स्तर की सोच नहीं है। यह संकीर्ण सोच है और इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए मुझे पीड़ा भी हो रही है लेकिन करना पड़ रहा है जब आपकी सोच ही ऐसी है।

मुख्य मंत्री जी अ0व0 की बारी में...

18.03.2026/1255/av/yk/1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री को मंत्री दिन में ही सपने दिखा देते थे कि अग्निवीर शुरू होगी और इतने लोग एकैडेमिक जाएंगे जबकि हमारा आर्मी का कोटा भी कर्टेल कर दिया है। ...(व्यवधान)

मैं आपको कम्प्लीट बिल्डिंग्ज के बारे में बता रहा हूं। हम अभी तो इन्कम्प्लीशन के लिए पैसा दे रहे हैं और वहां पर अटल यूनिवर्सिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने इस बारे में अनाउंस किया है और नेरचौक मेडिकल कॉलेज से हम अटल यूनिवर्सिटी शिफ्ट करके उसे सरकाघाट लाएंगे तथा उसके अलावा उस मेडिकल कॉलेज को भी पूरी तरह से शुरू करेंगे। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक प्रश्न लगा है जिसके अंतर्गत हम सारी कम्प्लीट बिल्डिंग्ज के बारे में बताएंगे। अगर इन्कम्प्लीट बिल्डिंग्ज के बारे में बताने लगूं तो वह सूचना तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मेरी सोच प्रदेश की सोच है और आपकी सोच ठेकेदारों की सोच थी। मैं शब्दों के इस्तेमाल में नहीं जाना चाहता परंतु हमारे समय में न तो आर0डी0जी0 आई और न ही जी0एस0टी0 कम्पनसेशन सैस आया। अगर आप हमारे सवा तीन वर्ष के कार्यकाल में कहीं एक भी जगह बता देंगे कि कोई गलत बिल्डिंग

बनी है, ...(व्यवधान) हम सारे मेडिकल कॉलेज पूरे कर रहे हैं। शिक्षा संस्थानों की बिल्डिंग्ज पूरी कर रहे हैं। आप किस स्वास्थ्य संस्थान की बात कर रहे हैं? आप तो सपने देखते रहे, आप बल्ह में एयरपोर्ट बनाने की सोचते रहे, आप आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के बारे में सोचते रहे। मैं आपको सपने के बारे में बताता हूं। हमने सपना सोचा कि सी0बी0एस0ई0 स्कूल डेढ़ सौ से शुरू करेंगे तो हमने डेढ़ सौ में ही सी0बी0एस0ई0 स्कूल शुरू कर दिए और टीचर्ज भी दे दिए।

अध्यक्ष महोदय, इतनी-सी बात है। विपक्ष के नेता को जरूर गुस्सा आता है क्योंकि इनकी पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है। इनके गुट इन पर इतना दबाव डाल देते हैं कि ये यहां आकर मुझसे लड़ने लगते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप मुझसे मत लड़ा कीजिए। आप पहले अपनी पार्टी की अंदर की लड़ाई लड़िए उसके बाद बाहर की लड़ाई लड़ा कीजिए। आपका फर्ज है, आप बोलिए। आप अखबार में बोलिए, प्रैस कॉंफ्रेंस करके बोलिए या बी0जे0पी0 के सोशल मीडिया सैल में बोलिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश की संपदा की पाई-पाई प्रदेश हित में लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है।

Speaker : The House adjourned for the lunch break and we will reassemble at 2 O' clock. Thank you very much.

18.03.2026/1405/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.05 बजे अपराह्न पुनः माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में **आरम्भ हुई**)

Direction by the Speaker

Speaker: Since the Hon'ble Chief Minister is not in the House, I am requesting the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister, and also requesting all the Members, to be decorous in the House, failing which I will be forced to take action under Rule 319. So, this is what I want to apprise all the Hon'ble

Members, that they should be decorous. Any insinuation or instigation will be dealt with very seriously against the Chair. This is what I wanted to inform both the Members from the Ruling side also, and the Opposition side also. So, the Hon'ble Parliamentary Affairs Minister should ensure that there should be decorum in the House. Some Members are taking the House for granted. I am not to deal with their sickness.

I am now calling Hon'ble Member Shri Kuldeep Singh Rathore to second the Motion.

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुसमर्थन करता हूं। दिनांक 16 फरवरी, 2026 को प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था। मैं उस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वह कुछ हद तक परिपाटी से अलग था। उन्होंने मात्र 4 लाइनों में अपनी बात को समाप्त किया। अच्छा होता कि संवैधानिक प्रमुख होने के नाते वह पूरा अभिभाषण पढ़ते। खैर, इस विषय पर मैं अधिक चर्चा नहीं करना चाहूंगा। मुझ से पूर्व माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में काफी लंबी-चौड़ी तकरीर दी। उन्होंने जिन बिंदुओं पर चर्चा की, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूंगा।

18.03.2026/1405/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर मैं अवश्य बात करना चाहूंगा और वह प्रदेश की वित्तीय स्थिति से जुड़ा हुआ मुद्ददा है।काफी लम्बे समय के बाद आर0डी0जी0 के बंद होने से प्रदेश में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। इस संबंध में सदन में प्रस्ताव भी लाया गया। किन्तु यह मुद्दा किसी एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। यह प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा .... जारी

18-3-2026/1410/NS-AG/1

श्री कुलदीप सिंह राठौर----जारी

अगर हमारा आर्थिक नुकसान होगा तो इसका असर पूरे प्रदेश की जनता पर होगा। जब प्रस्ताव लाया गया तो मुझे लगता था कि हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। मैं नहीं जानता कि उन पर क्या राजनीतिक दबाव है? हमें उनका जो समर्थन मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 275(1) में इस भावना के खिलाफ यह निर्णय है। हम सभी जानते हैं और बार-बार इस पर चर्चा भी होती रही है कि हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है तथा हमारी भौगोलिक स्थिति देश के दूसरे राज्यों से भिन्न है। अब वह फार्मूला कि 17 राज्यों में आर0डी0जी0 बंद हुई तो हिमाचल में भी बंद होनी चाहिए, यह सही नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है अगर उन्होंने बंद किया तो हिमाचल में भी बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह तर्कसंगत बात नहीं है। कर्नाटक जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो उन राज्यों की वित्तीय स्थिति हमसे बिल्कुल भिन्न है। हमको उस श्रेणी में घसीटना गलत है और इसे यकायक बंद करना भी गलत है। आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। सरकारें बनती हैं और आगे भी बनती रहेंगी। केंद्र में आज भाजपा की सरकार है और इससे पहले हमारी सरकारें रही हैं लेकिन आगे क्या होगा, वह भविष्य के गर्भ में है। हिमाचल में भी सरकारें बदलती रही हैं। सरकारें हमारी भी रही हैं और इनकी भी रही हैं। भाजपा की भी रही हैं और आगे भी सरकारें बनती-बिगड़ती रहेंगी। लेकिन यह हिमाचल का हक था और आज अगर हमने हिमाचल के हक को छोड़ दिया तो इस बात को आने वाली पीढ़ियां जरूर कहेंगी। सदन में बैठे तमाम सदस्य भी एक सवाल पूछेंगे कि जब आप विधानसभा के सदस्य थे तो आपने उस वक्त विरोध क्यों नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, यह बात भी सामने आएगी। जी0एस0टी0 कंपनसेशन वर्ष 2022 के बाद बिल्कुल बंद हो गया है। इसके अलावा लोन लेने की लिमिट पर भी बैन लग गया है कि आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते और कोई अन्य सहायता भी नहीं ले सकते। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार का गला घोंटने का प्रयास किया गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि आज सरकार किसकी है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जो पैसा यहां आता है वह हमारी तरक्की व उन्नति के लिए खर्च होता है लेकिन उस पर पूरा प्रतिबंध लग

गया है। हमने तो पहले भी एक बात कही थी और मैंने उस दिन भी तकरीर में हिस्सा लिया था जब यह प्रस्ताव आया था। नेता प्रतिपक्ष भले आदमी हैं और मुझे यह कहने

18-3-2026/1410/NS-AG/2

में संकोच नहीं है। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के साथ और जिन लोगों को आप उचित समझें, आप उनके साथ एक डेलिगेशन लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, माननीय गृह मंत्री जी के पास जाएं, माननीय वित्त मंत्री के पास जाएं और वहां पर हिमाचल के हक की बात करें। हालांकि

आर0के0एस0 द्वारा----जारी

18.03.2026/1415/RKS/AS-1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी...

प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री भी दिल्ली जाकर उनसे मिले। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ठाकुर जय राम जी भी दिल्ली गए और वे भी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मिले। अब वहां क्या बात हुई, हमें मालूम नहीं। ...(व्यवधान) It was communication between two leaders, so we can't say what transpired between them. वहां क्या बात हुई, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है कि वहां कोई सार्थक बात हुई है। हम आप पर कोई शक नहीं कर रहे हैं परंतु सार्थक बात हुई है तो उसका परिणाम सामने क्यों नहीं आया? मैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह दो नेताओं के बीच की बात थी और मुझे लगता है कि इसकी अच्छी खबर मिलने वाली है। परमार साहब, शायद आपका तात्पर्य भी यही है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल ने पिछले कुछ वर्षों में, खासकर जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है हमने प्रतिकूल मौसम की मार सहन की है। वर्ष 2023 में प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई। इस आपदा के कारण हमारे प्रदेश को काफी नुकसान हुआ। आकलन के मुताबिक हमारे प्रदेश को 10 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है और इसके हमने केंद्र से मदद मांगी। आपदा का जायजा लेने के लिए केंद्र से कई टीमें यहां आई। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पूरा दौरा किया । हमें उम्मीद थी

कि हमें केंद्र से मदद मिलेगी लेकिन जो भी मदद मिली वह 'ऊँट के मुँह में जीरे' के बराबर थी। यह बात ठीक है कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल आते रहते । हमारे जो सांसद हैं, वे भी यहां आते हैं। वे आंकड़ें प्रस्तुत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बहुत ज्यादा मदद हुई है। कोई कहता है कि इतने हज़ार करोड़ की मदद हुई और कोई कहता है कि इतने करोड़ की लेकिन वे अलग-अलग आंकड़े पेश करते हैं। जो केंद्र निहित योजनाएं हैं उनको भी आप उस मदद में जोड़ रहे हैं। Central sponsored schemes के तहत जो पैसा मिलता है वह तो हिमाचल का हक है। विभिन्न योजनाओं में पहले से केंद्र सरकार द्वारा राशि जारी की जाती है, यह कोई नई बात नहीं है। जब दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री थे और हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री थे तो उस वक्त भी केंद्र सरकार द्वारा मदद की गई थी। हमने उनका एक बयान पढ़ा था कि उन्होंने किस तरह से डॉ0 मनमोहन सिंह जी के पास जाकर अपनी मांग रखी थी। डॉ0 मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हिमाचल के साथ पूरा न्याय होगा और बाद में हिमाचल प्रदेश की दिल खोलकर मदद भी हुई। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब यह दिल क्यों छोटा हो गया है? वास्तव में अगर मदद हुई है तो मैं बार-बार यह बात कहता

18.03.2026/1415/RKS/AS-2

आया हूं कि आप इस विषय में 'श्वेत पत्र' जारी करें। आप बताएं कि आपदा में हिमाचल की कितनी मदद हुई है? इस सरकार ने सराहनीय काम करके आपदा से बाहर निकलने का प्रयास किया है। वर्ष 2025 में फिर से आपदा आई और इस बार हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वहां कई लोग आपदा के कारण मारे गए। हमें इस पर सहानुभूति है। इनका चुनाव क्षेत्र भी इस प्रदेश का हिस्सा है। वहां भी हमारे ही लोग रहते हैं। दूसरे कई क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे जिला में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपदा के दौरान हमारी सरकार खुलकर लोगों की मदद के लिए आगे आई। मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने आपदा के दौरान अच्छा काम किया। मैं सेब बहुल क्षेत्र से आता हूं। उस समय सेब सीजन का समय था।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

18.03.2025/1420/बी.एस./ए.एस.-1

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी...

हमारे जो बागवान हैं वे बहुत चिंतित थे कि हमारा सेब मार्केट तक कैसे पहुंचेगा? लेकिन दिन रात काम हुआ और सरकार ने हर संसाधन का उपयोग किया और सेब का एक-एक दाना मार्केट में पहुंचा और बागवानों का नुकसान नहीं होने दिया। लोगों के घर ढह गए और अभी भी लोगों को मदद का इंतजार है। वह मदद भी अभी तक नहीं हो पाई है। अब उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ऊपर से आपने आर0डी0जी0 बंद कर दी है।

मेरा सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमें हिमाचल की आर्थिकी को बचाना है। हमारा छोटा सा प्रदेश है। मैंने पहले भी कहा कि हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं और हम जंगलों की सुरक्षा करते हैं। हमारे यहां से पानी नीचले क्षेत्रों में जाता है तभी राजस्थान हरियाणा, पंजाबी हरे-भरे हैं। यह हमारा हक बनता है और मैंने जैसे पहले कहा था और आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि हिमाचल के हमारे जो जवान है जो सीमाओं की रक्षा करते हैं उनका राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान है। आप कोई भी युद्ध लीजिए वर्ष 1962, 1965, 1971 और कारगिल का युद्ध है और अभी भी कोई आतंकी घटना सीमा में होती है तो हिमाचल के जवान अपने प्राणों की आहुति देते हैं। सबसे ज्यादा हमारे प्रदेश के युवा सेना में भर्ती होते हैं। क्या उस राष्ट्रभक्ति का हमें कोई पुरस्कार नहीं दिया जा सकता? यह भी सोचने की बात है। इस अभिभाषण में बड़ी तफशील से चर्चा हुई है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी भी समय है सब लोग मिलकर और खासकर इसमें प्रतिपक्ष के हमारे साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि आज प्रदेश के हक की बात है। आप प्रधानमंत्री जी से मत डरिए। आपको कहने का पूरा अधिकार है और यह आप अपने लिए नहीं मांग रहे। यह आप कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं मांग रहे। यह हिमाचल की जनता के हक की बात। मुझे लगता है कि आप इस दिशा में प्रयास करेंगे। क्योंकि आने वाला जो दो-अढाई साल का समय है वह बहुत संकट का समय रहेगा। इसे आप सभी लोग

जानते हैं। आपने भी सरकार चलाई कि कितनी देनदारियां सरकार के ऊपर होती हैं। लगातार हमारा कर्ज बढ़ रहा है। अब इस बात की चर्चा छोड़िए कि आपके वक्त में इतना

18.03.2025/1420/बी.एस./ए.एस.-2

कर्जा था और हमारे वक्त में इतना कर्जा हो गया। यह दोषारोपण हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सबके वक्त में कर्जा हुआ। हालांकि बहुत सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि इन पर बैठकर चर्चा होनी चाहिए थी कि किस तरह से हम मितव्ययिता से काम कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने इस बारे में काफी पग उठाए हैं और ये स्वागत योग्य हैं। बहुत सारी चीजें पहले भी हो सकती थी। यह भी बात सही है कि खर्चों में भी लगाम लगाने की जरूरत है। अब खाली दोषारोपण से बात नहीं होगी। हम बोल आपकी कोर्ट में फेंक दें और आप हमारे कोर्ट में फेंक दें। ...(घंटी) यह कोई टेनिस का मैच नहीं है। हमें इसे भी समझने की जरूरत है। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया है। बावजूद इसके कि दो बार हमें बहुत बड़ी आपदा से जूझना पड़ा। उसकी चर्चा माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी ने बहुत विस्तार में की है। मैं उन चीजों को ज्यादा दोहराना नहीं चाहता।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.03.2026/1425/DT/DC-1

श्री कुलदीप सिंह राठौर सिंह जारी....

बहुत विस्तार में की अब मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता। सरकार के समक्ष दो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं एक तो है सामाजिक दायित्व-उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र आता है। इस संदर्भ में मैं यही कहूंगा कि इन क्षेत्रों में वर्तमान सरकार के द्वारा अच्छा करने का प्रयास हुआ है। हालांकि बहुत शोर मचा की प्रदेश में कुछ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें गुणवत्ता की शिक्षा की ओर जाने की जरूरत है। कोई भी स्कूल वहां पर पढ़ने वाले बच्चों से बनता है। उस स्कूल में कितने छात्र-छात्राएं पढ़ रहे हैं उनकी संख्या से स्कूल बनता है। स्कूल कभी इमारतों से नहीं बनता। बड़ी-बड़ी इमारतें

बना दें और उन इमारतों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 10,20,25, या 50 हो तो वह स्कूल एक अच्छा स्कूल नहीं कहलायेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसे स्कूल बंद करके सरकार द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया। मैं यही कहूंगा कि हमें शिक्षा की गुणवत्ता में ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार का शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति अच्छा प्रयास रहा है। अभी लगभग 150 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 के अंतर्गत लाया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी दोनों को बधाई देता हूं। निश्चित तौर से इससे प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। इससे हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा बोर्ड और सी0बी0एस0ई के बीच प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा की भावना होगी और दोनों अपने-अपने स्तर पर अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे-ऐसी हमको आशा है। शिक्षा का स्तर भी तभी बड़ पायेगा जब हम गुणवत्ता की शिक्षा देने में सक्षम होंगे।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना के अंतर्गत 17 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है और कुछ क्षेत्रों में यह संस्थान खुल भी चुके हैं। अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सदन में नहीं हैं अभी मैं भी इंतजार कर रहा हूं इन्होंने और आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोलने की घोषणाा की है और मुझे लगता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी जल्द आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खुल जायेगा। स्वास्थ्य हमारी मूलभूत आवश्यकता है और काफी अर्से से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भर्ती नहीं हुई। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों व पैरा मेडिकल स्टॉफ की भर्ती करने का निर्णय लिया है। उसकी प्रक्रिया प्रगति पर है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही वह प्रक्रिया पूरी होगी।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण में बागवानी का भी काफी जिक्र किया गया है। अभिभाषण में कहा गया है कि सरकार बागवानी के

18.03.2026/1425/DT/DC-2

क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यह सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। आज जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य सिक्कम है वह प्राकृतिक खेती में देश भर में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बागवानी संकट के दौर से गुजर रही है। 5000 करोड़ रुपये की हमारी आर्थिकी है। हमें इस बात का दुःख है कि अभी जो फ्रि ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के साथ हुंआ, यूरोपयिन युनियन के साथ हुआ और जो अमेरिका के साथ होने जा रहा है-उसमें कहीं-न-कहीं हिमाचल प्रदेश के बागवानों के हितो का ध्यान

नहीं रखा जा रहा। हमारे प्रदेश में डेढ़ लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो बागवानी में आश्रित हैं। हमारा आयात शुल्क 50 प्रतिशत से आधा कर दिया गया। इससे बागवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है और अभी और लगने वाला है क्योंकि जो मार्किट में हमारा सेब बिक रहा है वह आधे दामों में बिक रहा है। इस विषय में भी मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी हमारा प्रस्तावित समझौता है उस समझौते में हम किसी के दवाब में न आएं-चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों न हों। मैं विदेश निति के बारे में इस सदन में कोई बात नहीं करना चाहता-न ही वह विषय है। वह एक अलग विषय है। लेकिन आज हमें हिमाचल के किसानो, हिमाचल के बागवानों के हितों की रक्षा करनी है उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा समझौता न करें जिसके दूरगामी परिणाम निकले

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.03.2026/1430/डी.सी.-एन.जी./1

श्री कुलदीप सिंह राठौर..... जारी

उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसा समझौता न करें, जिसके दूरगामी परिणाम निकले और आने वाले समय में हमारे हितों को नुकसान हो।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य नशे को लेकर किया है। मैं यह नहीं कहता कि पहले प्रयास नहीं हुए या पिछली सरकार ने प्रयास नहीं किए। मुझे मालूम है कि इस माननीय सदन में मैं और माननीय सदस्य, श्री सुख राम चौधरी जी, हम संयुक्त रूप से नशे के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे और सभी माननीय सदस्यों ने उसका समर्थन भी किया था। आज प्रदेश सरकार ने इस विषय पर काफी कठोर कदम उठाए हैं। जो लोग नशे के व्यापार में संलिप्त थे, उनमें से कुछ पकड़े गए हैं और शेष पकड़े जा रहे हैं। प्रदेश सरकार नशा निवारण केंद्र भी खोल रही है और यह भी बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जहां सरकार इसे एक सामाजिक अभियान के रूप में चलाने का प्रयास कर रही है, वहीं हम सब भी इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और मेरा

आग्रह है कि हम सब मिलकर हिमाचल प्रदेश में इस महामारी को खत्म करने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

18.03.2026/1430/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : अब मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री जय राम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16 फरवरी, 2026 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस माननीय सदन के अंदर जो अभिभाषण प्रस्तुत किया है, मैं उसकी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में हमने बहुत लंबे अर्से के पश्चात इस बात को देखा कि राज्यपाल महोदय जी ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हुए केवल 2 मिनट 7 सेकंड का समय लिया और उसे इतने समय में ही समाप्त कर दिया। इस माननीय सदन में हम कई वर्षों से हैं और कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं कि अभिभाषण लम्बा होता है या राज्यपाल महोदय जी अस्वस्थ हैं या आयु की एक वजह के कारण लम्बा अभिभाषण नहीं पढ़ पाते। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस बार यहां पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। राज्यपाल महोदय जी पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। पिछले वर्ष उन्होंने इसी माननीय सदन में अपने अभिभाषण को पूरा व अक्षरशः पढ़ा था। लेकिन इस बार राज्यपाल महोदय जी केवल 2 मिनट 7 सेकंड में अपना अभिभाषण समाप्त करके यहां से चले पड़े। मुझे लगता है कि इसकी वजह सत्ता पक्ष के लोगों को समझनी चाहिए और पूरे प्रदेश के लोगों ने इस सारी बात को समझा है। खासतौर से जो टिप्पणियां राज्यपाल महोदय जी की ओर से इस माननीय सदन में हुई हैं, वे अपने आप में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि 'पैराग्राफ

01 से 16 तक जिन बातों का जिक्र किया गया है, उनमें गंभीर टिप्पणियां केंद्र सरकार के ऊपर भी हैं, इसलिए मेरे लिए पढ़ना संभव नहीं है'।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.03.2026/1435/ए.पी. /एच.के. -1

श्री जयराम ठाकुर जारी .....

अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण प्रदेश सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा होता है। लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के एक-से-सोलह तक के पैरा तक आप लगातार केंद्र सरकार को कोसते हैं और उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए अधिकारों की बात करते हैं कि अधिकार हमें मिलने चाहिए। लेकिन कर्तव्यों का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। कर्तव्य यह है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को विभिन्न मदों के अंतर्गत जो बड़ा सहयोग दिया है, उसका आभार व्यक्त करें। यदि उसके बाद आप कहते कि हमारी आर0डी0जी0 भी बहाल की जाए तो हम अभिनंदन करते और ऐसे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते तो हमें समझ में आता कि आपने फेडरल स्ट्रक्चर की भावना का सम्मान किया है। लेकिन आप विधान सभा और जन-सभाओं में गैर-जिम्मेदाराना तरीके से बोलते हैं, गाली-गलौज करते हैं और उसके बाद केंद्र सरकार से सहयोग लेने के बावजूद धन्यवाद या शुक्रिया शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं करते। मैं समझता हूं कि यह व्यक्तिगत रूप से कहीं-न-कहीं उस व्यक्तित्व की कमी है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और भारत की संस्कृति इस बात को कहती है कि हमें कभी भी नाशुक्र नहीं होना चाहिए। मदद जिस रूप में भी मिले छोटी हो या बड़ी हो, ज्यादा हो या कम हो, किसी भी रूप में मिले हमें उसे स्वीकार करते हुए उसका अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहिए। सत्ता पक्ष की ओर से हमें बहुत ज्ञान दिया जाता है और हमेशा यही कहा जाता है। पिछले साढ़े तीन वर्षों का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। आपकी सरकार के समय का यह चौथा अभिभाषण है और इसके बाद केवल एक ही वर्ष आपके पास बचेगा। बहुत सारा वक्त निकल गया है, जो आपका था। लेकिन आने वाला समय आपकी सरकार का नहीं लगता। अंतिम एक वर्ष में दौर अलग होता है। जहां

आप अच्छी बातें करके लोगों का दिल जीत सकते थे, काम करके लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ सकते थे। लेकिन आपने वह सारी चीजें एक-एक करके गवा दी है, बर्बाद कर दी है और इसका पश्चाताप आपको एक वर्ष बाद होगा और आप कहेंगे कि आपसे गलती हुई है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के साथी जिन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और अनुमोदन किया। मेरे से पहले माननीय राठौर साहब

18.03.2026/1435/ए.पी. /एच.के. -2

बोल रहे थे। वे भले आदमी हैं, मुझसे भी ज्यादा भले हैं। कई बार भले आदमी के बारे में बोलने पर भी आफत आ जाती है। लेकिन हमारी विवशता है, राठौर साहब, कि हमें आपकी पार्टी को हराना है। उस जद्द में आप भी आते हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा कुछ नहीं है, इसलिए हम आमने-सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें बार-बार कही जा रही हैं और खासतौर पर मुख्य मंत्री जी बार-बार कहते हैं। आजकल उनके यहां नकल करने का दौर बढ़ गया है और बाकी हमारे साथी भी उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1440/AT/HK /01

श्री जय राम ठाकुर जारी...

मेरा तो सत्ता पक्ष के साथियों से इस बात के लिए आग्रह है कि केवल नकल से काम नहीं चलेगा थोड़ा अकल से भी काम कीजिए वही काम आएगी। अध्यक्ष महोदय, अब बात यह भी आती है कि व्यवस्था तो सरकार के सामने है। अगर काम किया होता तो उसका जिक्र

होता, राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी उसका जिक्र होता। जब किया ही नहीं है तो जिक्र किस बात का करें? इसलिए मुझे लगता है कि आपकी सरकार के कामकाज को 2 मिनट 7 सेकंड में निपटा कर गवर्नर साहब चले गए तो इसका मतलब उन्होंने गलत नहीं बल्कि सही और उचित किया है। क्योंकि आपकी सरकार के कार्यकाल में ऐसा कोई अंश नहीं है जिस पर कुछ बोला जा सके। इतने ही वक्त की आवश्यकता थी।...(व्यवधान) सही बात है। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी, मैंने कहा वह परिस्थिति कुछ अलग प्रकार की होती है। कभी व्यक्ति अस्वस्थ होता है, कई बार उम्र का असर होता है। आपकी और हमारी उम्र भी बढ़ रही है। कहीं आपको राज्यपाल बना दिया जाए और उस उम्र में आप खड़े होने की स्थिति में न हों। भगवान आपको सलामत रखे, स्वस्थ रखें, आपकी टांगें ठीक रहें, सब कुछ ठीक रहे। ऐसी स्थिति में वही होता है जो पहले कई बार हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, इस बार वह स्थिति नहीं थी। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, तो बोलते क्या? जब लिखने के लिए कुछ नहीं था तो लिखते क्या? इसलिए आपको पश्चाताप होगा क्योंकि आपने बहुत सारा वक्त यहां गुजार दिया है। जब आपके माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे तब कहा गया कि हम डिजास्टर के दौर से गुजर रहे हैं, पहले राजनीतिक डिजास्टर, फिर आपदा का डिजास्टर, फिर आर्थिक डिजास्टर, और फिर फाइनेंशियल डिजास्टर। अगर आपके भाग्य और आपके टिपड़े में ऐसा लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं। सरकार की जब टी0पी0एस0सी0 बनी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं सब कुछ खराब ही होना है। एक बात उनकी छूट गई। फाइनेंशियल डिजास्टर के साथ उन्हें यह भी कहना चाहिए था कि सही मायने में सबसे बड़ा डिजास्टर वर्तमान सरकार है। एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही है। विकास कार्यों पर पूर्ण विराम है और विकास कार्यों पर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। अगर आपके पास उपलब्धि के नाम पर कुछ कहने को नहीं था तो आप दूसरा पक्ष भी ले सकते थे। आप यह कह सकते थे कि मैंने हिमाचल

18.03.2026/1440/AT/HK /02

प्रदेश में 2000 चल रहे संस्थान बंद किए, यह मेरी उपलब्धि है। इसे भी उपलब्धि के रूप में गिना जा सकता था। इसका जिक्र आना चाहिए था। आप यह भी कह सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक सभी विकास कार्यों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया, आप यह कह सकते थे, यह भी एक उपलब्धि है। आप आगे यह भी कह सकते

थे कि हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक संकट आया है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। मैं बहुत पुराने समय से इस सदन में यह बात सुनता आया हूं। जब 13वें वित्त आयोग की सिफारिशें आईं तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगभग 7600-7800 करोड़ रुपये रह गई थी। उस समय हम सत्ता पक्ष में थे और हम कहते थे कि यह अन्याय है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। उससे पहले 12वें वित्त आयोग में हमें लगभग 11000 करोड़ रुपये की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी लेकिन बाद में उसे कम कर दिया गया। उस समय केंद्र में आपकी सरकार थी और डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन उस समय आप क्या कहते थे? आप कहते थे, आप केंद्र में जाइए, केंद्र से मदद लेकर आइए, किसने रोक रखा है। आप यही शब्द बोलते थे।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1445/केएस/वाईके/1

श्री जय राम ठाकुर जारी ---

अगर नहीं ला रहे हैं तो सरकार की नाराज़गी है, आप यह भी बोलते थे। अब मैं क्या बोलूं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दो रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट में हिमाचल प्रदेश को एक बार 40 हजार करोड़ रुपये दिए और एक बार 37, 200 करोड़ रुपये दिए और कोविड के कारण 11,600 करोड़ रुपये हमें और दिए। कुल मिलाकर 89 हजार करोड़ रुपये से ऊपर हिमाचल प्रदेश को रेवन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा मिला और आपकी यू0पी0ए0 की सरकार के समय 18 हजार करोड़ रुपये मिले। 72 हजार करोड़ रुपये हमको ज्यादा मिले। हमारी सरकार थी, हमने हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छा सोचा, अच्छा किया। यहां सरकार भले ही आपकी थी लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा किया। यही सोच मनमोहन सिंह जी के मन में क्यों नहीं आई? जब आपकी सरकार केंद्र में सत्ता में थी, यही सोच उस वक्त क्यों नहीं आई कि हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट की घड़ी में मदद करने की आवश्यकता है? उसके बाद आप हम पर आरोप लगाते हैं कि आपके समय में, हम कह रहे हैं कि हमारे समय में अगर आपकी ही उस वक्त

की भाषा का इस्तेमाल करुं तो हम ले करके आए, आपको किसने बांध कर रखा है, आप भी ले कर आइए। अगर मैं उन्हीं शब्दों में ज़िक्र करुं, क्योंकि आपके वे शब्द हमारे कानों में अभी भी अच्छी तरह से गूंज रहे हैं। हम उन बातों को नहीं भूल पाए। आप पर भी यह बात लागू होती है। आप भी जाइए। यहां पर ज़िक्र कर रहे थे कि जय राम दिल्ली गया। कुछ लोग कहते हैं कि जय राम दिल्ली क्यों गया? इन्होंने एक भाषा तय करके रखी है कि जय राम दिल्ली गया तो पैसा रोकने के लिए गया। हम आपसे ज्यादा हिमाचल के हितैषी हैं। हिमाचल हमारे लिए सर्वोपरि है। राजनीति में आना-जाना चलता रहेगा। अगर मैं वित्त मंत्री जी से मिला तो मैंने कहा कि हिमाचल की मदद कीजिए। जिस तरीके से भी कोई रास्ता निकल सकता है, निकालिए लेकिन हिमाचल की मदद कीजिए। हमने गृह मंत्री जी से भी कहा और हमने उनसे निवेदन किया है कि हिमाचल में डिजास्टर के कारण नुकसान हुआ है और हमें आपसे बहुत उम्मीद है। उन्होंने कहा कि हम मदद करने की कोशिश करेंगे। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी बीच में कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह गलत है। क्योंकि यह

18.03.2026/1445/केएस/वाईके/2

परम्परा पिछली बार से शुरू हुई है। जब रेवन्यू डैफिसिट ग्रांट पर चर्चा का मुख्य मंत्री जी जवाब दे रहे थे, उस वक्त हमने बीच में बोलने की कोशिश की थी लेकिन आपने हमें बोलने की स्वीकृति प्रदान नहीं की थी और मुख्य मंत्री बैठे नहीं थे। आप तो चाहते थे कि हम बोलें, हमारी बात सुनी जाए लेकिन ये नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए उचित रहेगा कि मेहरबानी करके आप हमारी बात सुनें।

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, एक मिनट। मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप थोड़ी देर यील्ड कर लो।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, फिर हम बोलना छोड़ देते हैं। ...(व्यवधान) ये भी उस वक्त नहीं बैठे थे।

अध्यक्ष : कोई बात नहीं, आगे से ये बैठ जाएंगे। मुख्य मंत्री जी आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, अच्छी बात है और गवर्नर साहब के शब्दों का और मिनटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नर साहब को पूरा भाषण पढ़ना था क्योंकि वे संवैधानिक पद पर हैं। एक संवैधानिक दायित्व भी होता है लेकिन गवर्नर साहब के सहारे ये अपना चुनाव जीतने की जो कोशिश करेंगे उसका तो वर्ष 2027 में पता लगेगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 के मामले में जो ये बार-बार बोलते हैं कि 13वें वित्तायोग में या 14वें वित्तायोग में ऐसा हुआ था, आर0डी0जी0 तो आपको पता है कि आर्टिकल 275(1) के तहत कभी भी किसी सरकार ने बंद नहीं की। वर्ष 1952 से 77 साल तक कभी किसी सरकार ने बंद नहीं की थी। और आय और व्यय के बीच के अंतर को ही पाटने के लिए टैक्सिस का शेयर होता है। आप 13वें वित्तायोग का 30 या 40 हजार का आंकड़ा बता रहे हैं। जब आपको सत्ता मिली उस समय 48 हजार करोड़ रुपये प्रदेश पर कर्जा था और इनको आर0डी0जी0 और जी0एस0टी0 कंपनसेशन के रूप में 70 हजार करोड़ रुपये के लगभग मिले। अगर ये चाहते, जो ये प्रदेश के हित की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, 48 हजार करोड़ रुपये को कम करके अगर उस समय 70 हजार करोड़ रुपये में से 20 हजार करोड़ रुपये का लोन वापिस कर देते तो प्रदेश पर 28 हजार करोड़ रुपये का कर्ज रहता।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.03.2026/1450/av/yk/1

मुख्य मंत्री------जारी

ये हम पर 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर चले गए। इसके अतिरिक्त 70 हजार करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 भी खा गए। ये अभी कह रहे हैं कि मैं केंद्र में वित्त मंत्री जी और गृह मंत्री जी से मिला। मैं यहां पर बार-बार बोलता रहा कि हम आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हैं। हम ठीक बोलते हैं क्योंकि हम जब उनसे इस बारे में मिलते हैं तो आप उनसे रुकवाने की बात करते हैं। उसके बावजूद आप यहां पर प्रदेश हित की बात करते हैं, अगर ऐसा है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं गए? मैं आपके साथ चलता और मैं अभी भी साथ चलने को तैयार हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आर0डी0जी0 लोगों का अधिकार है न कि

प्रदेश सरकार का अधिकार है। यह प्रदेश की 75 लाख जनता का अधिकार है। मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में उस समय चाहे कोई भी सरकार होती, अगर आय-व्यय में इतना ज्यादा अंतर होता तो इतनी ही आर0डी0जी0 मिलती। इसमें कोई दो राय नहीं है परंतु यह पहली बार किया गया है कि 16वें वित्तायोग द्वारा इसको बंद कर दिया गया है। हम इस संदर्भ में मिलने की बात कर रहे थे, हमने स्पेशल सैशन क्यों बुलाना था? हम चाहते थे कि इस संदर्भ में हमें विपक्ष का समर्थन मिलता और हम सभी मिलकर साथ चलते। परंतु इस संदर्भ में हमारे साथ कोई भी नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं।

18.03.2026/1450/av/yk/2

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप बोलिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हट-फिरकर वही 'ढाक के तीन पात', इस बात को ये सुबह, शाम और दोपहर यानी हर समय कहते रहते हैं कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में ज्यादा पोर्शन आर0डी0जी0 का ही है और इसीलिए यह चर्चा हो रही है। हम कह रहे हैं कि आप अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखिए। आप अपने पक्ष को गाली देकर मत रखिए अपितु तर्क और तहज़ीब के साथ रखिए। जब कोई बात तर्क और तहज़ीब के साथ रखी जाती है तो ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इनसे पहले भी इस माननीय सदन में कई मुख्य मंत्री देखे हैं। वे कभी-कभी राजनीति की बात को छोड़ देते थे परंतु ये 'श्रीमान जी' हैं और ये सुबह से लेकर शाम तक राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते। ये बात भी राजनैतिक करते हैं और राजनीति के अलावा कभी कुछ नहीं करते। कभी प्रदेश को राजनीति से ऊपर भी आने दीजिए। यहां पर विपक्ष के सभी सदस्य बैठे हैं। हमने आर0डी0जी0 का विरोध कब किया? हमें जब यहां पर बोलने ही नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप यहां पर बार-बार कहते रहे कि आप बैठ जाइए, इनको थोड़ा सुन लेते हैं। आपने जैसे अभी मुझे बिठाया और तहज़ीब भी यही बोलती है कि आपने अपने आसन से इशारा किया और मैंने अपना आसन

ग्रहण किया। उसके बाद आपने मुख्य मंत्री जी को बोलने का मौका दिया और मैंने इनकी बात सुनी। उसके बावजूद अब ये न मानें तो उसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि कुछ चीजें ला-इलाज हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आर0डी0जी0 और प्रदेश पर आने वाले आर्थिक संकट को लेकर सारी बातें कह दी हैं। उसके बाद जब आपका बजट आएगा तो हम इस बारे में और ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन आप एक बात मानकर चलिए। बजट प्रस्तुत होने से पहले आपके वित्त विभाग की ओर से जो एक प्रेजेंटेशन आ गई है, उसने सारा काम तमाम कर दिया है। आपके पास बजट में करने के लिए बचा क्या है? जब कह दिया गया है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों को एरियर, डी0ए0, नौकरियां इत्यादि देने व विकास कार्य करने की स्थिति में

18.03.2026/1450/av/yk/3

नहीं है। इसके अतिरिक्त टोटल सब्सिडी विड्रो करनी पड़ेगी। सरकार हिमकेयर का पैसा देने की स्थिति में नहीं रहेगी। कोर्ट के माध्यम से जो 1 हजार करोड़ रुपये की लायबिलिटीज हैं; उनको देने की स्थिति में भी नहीं है। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग की लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की लायबिलिटीज देने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से सारी चीजों का जिक्र तो हो चुका है। आप अगर सब कुछ बंद करेंगे, वैसे तो ये सारी चीजें पहले ही बंद पड़ी हैं। उसके बावजूद 6 हजार करोड़ रुपये का गैप रहेगा उसकी भरपाई करने की स्थिति में भी हम नहीं रहेंगे; इस बारे में वित्त विभाग ने स्पष्ट कह दिया है। परंतु मुख्य मंत्री फिर भी कहते हैं कि यह तो वित्त विभाग का व्यू है और सरकार तो हमें चलानी है क्योंकि फैसले हमें लेने हैं। आप क्या फैसले लेंगे, आप हमें यह बताइए। आपके पास क्या जादू की छड़ी है?

टी सी द्वारा जारी

18.03.2026/1455/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री जय राम ठाकुर .... जारी

कि उसको गिल्ली-गिल्ली घुमाकर आपके पास पैसों का ढेर लग जाएगा? जो स्थिति सामने है, उससे निपटना कैसे है, उसके लिए तैयारी की जाए, मैं यही कहना चाहूंगा। आप उपलब्धि की बात करते हैं, अगर आप यह कहते कि हम कोई उपलब्धि नहीं कर पाए तो बात मानी जा सकती है लेकिन आप कहते हैं कि हमने सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया, यह भी उपलब्धि है। हमने हिमकेयर का पैसा बंद कर दिया, यह भी उपलब्धि है। मुख्य मंत्री जी हमसे पूछते हैं कि आपको जो पैसा मिला, आपने उस पैसे का क्या किया? हमने वह पैसा जनता के बीच में वितरित किया। इसलिए जनता आज उस बात का जिक्र करती है। अब आपका चौथा बजट अभिभाषण है और चौथा बजट प्रस्तुत होने वाला है। मैं आपकी फ्लैगशिप योजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा। "सुख शिक्षा योजना" पर 22 करोड़ रुपये खर्च किए। "सुख सम्मान निधि योजना" पर 7.42 करोड़ रुपये खर्च किए गए। "सुखाश्रय योजना" पर 25.79 करोड़ रुपये खर्च किए और "राजीव गांधी स्टार्टअप योजना" पर 4 करोड़ रुपये खर्च किए गए। आपका 4 वर्ष का कार्यकाल बीतने जा रहा है और इन योजनाओं पर कुल मिलाकर लगभग 60 करोड़ रुपये से भी कम खर्च हुए हैं। आप हमसे प्रश्न करते हैं कि आपको इतना पैसा मिला तो आपने उसका क्या किया? हमने "सहारा योजना" चलाई और 22000 लोगों को उसका लाभ मिला तथा उस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। हमने "हिमकेयर योजना" चलाई और 4.70 लाख लोगों को उसका लाभ मिला तथा 500 करोड़ रुपये से अधिक उस पर खर्च किए गए। हमने "गृहिणी सुविधा योजना" चलाई और 4.80 लाख परिवारों को गैस का चूल्हा दिया। हिमाचल प्रदेश पूरे देश में पहला राज्य बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया गया और उस पर 177 करोड़ रुपये खर्च किए गए । हमने हिमाचल प्रदेश में "शगुन योजना" चलाई और 11000 लाभार्थियों को 40 करोड़ रुपये का लाभ दिया। हमने "मुख्य मंत्री स्वावलंबन योजना" चलाई जिससे 4500 नौजवानों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिला और उस पर 230 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। पहली कैबिनेट बैठक में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया। बाद में 60 वर्ष से ऊपर के लिए भी पेंशन देने का प्रावधान किया गया। 7.80 लाख लोगों को पेंशन दी गई और इस

पर 1300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए। 125 यूनिट बिजली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए फ्री देने का निर्णय लिया। प्राकृतिक खेती की दिशा में आगे बढ़कर उस पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च किए गए और आप हमसे हिसाब पूछ रहे हैं। आपने जितनी स्कीम्स पर पैसा खर्च किया, उससे ज्यादा अपने फोटो छापने यानी विज्ञापन पर खर्च कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, आगे कहते है कि हमने बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया। यहां पर कहा गया कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट का दर्जा समाप्त करने का फैसला लिया । आप किसको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको ठगने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट का दर्जा हटाने से कौन-सा आर्थिक संकट हल होगा। अगर आप उनको पूर्ण रूप से पद से हटा देते तो समझ आता कि उनका पद खाली हो गया है और इससे गाड़ी, दफ्तर, टी0ए0, डी0ए0 एवं अन्य खर्चे कम हो जाएंगे। आपने हिमाचल प्रदेश में उन सारी चीजों को लेकर बड़ा फैसला लिया और उनका कैबिनेट का दर्जा समाप्त किया लेकिन इससे क्या फर्क

एन0एस0 द्वारा .... जारी

18-3-2026/1500/NS-AG/1

श्री जय राम ठाकुर----जारी

इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? सी0पी0एस0 की कुर्सी बचाने के लिए तो आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिए। जब कुर्सी नहीं बच पाई तो आखिरकार क्या सच्चाई है कि आपने उनकी सुविधाएं पूर्ण रूप से वापस ली हैं? उन लोगों के साथ अभी तक भी स्टाफ मेजोरिटी अटैच है। मैं और चीजों के बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। बाकी सारी बातें आप जानते ही हैं। लेकिन आपकी ईमानदारी कहां है? मुख्य मंत्री जी जितनी ईमानदारी दिखने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ईमानदारी होनी भी चाहिए। आप बार-बार बोल रहे हैं कि हमारे कार्यकाल के दौरान आपदा आई। क्या हमारे कार्यकाल के दौरान आपदा नहीं आई?

अध्यक्ष महोदय, दो वर्षों तक कोविड रहा। वह वैश्विक समस्या थी और हमारी लापरवाही की वजह से नहीं थी या हमारी कमी की वजह से नहीं थी। पूरी दुनिया में वह समस्या थी। वह समस्या एक-दो महीने के लिए नहीं बल्कि दो साल तक रही लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य सतत चलते रहे, युद्ध स्तर पर चलते रहे। हर क्षेत्र में विकास कार्य चलते रहे। अब यहां मुख्य मंत्री जी को आदत पड़ गई है कि वहां हजार करोड़ रुपये की बिल्डिंग्ज खड़ी कर दीं। बिल्डिंग्ज खड़ी करने के बाद वहां पर काम होना था। जब वे बिल्डिंग्ज खड़ी कर दीं तो आपका जिम्मा है और आप सत्ता में आए तो उनको फंक्शनल करना चाहिए था। जिस पर्पज के लिए वह बिल्डिंग खड़ी की गई है या जिस मांग को लेकर वहां के विधायक ने बोला है या जिस मांग को लेकर वहां के लोगों ने उस बिल्डिंग को खड़ा करने का आग्रह किया और हमने खड़ी की तो आपको वहां उस काम को शुरू करना चाहिए। उस काम को तो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप वहां पर काम नहीं कर सकते तो आप उन बिल्डिंग्ज को गिरा दें। हम आपको यही बोल सकते हैं। ...(व्यवधान) आपको तसल्ली तो होगी। आपको आनंद की अनुभूति तो तब होगी जब सब कुछ मट्टियामेठ कर देंगे। आपको तब आनंद आता है और वह किसी दूसरे को नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हमें काम करने का आनंद आता था और इन्हें काम बंद करने का आनंद आता है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में यही फर्क है। इन्होंने विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को आर0टी0आई0 के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया। इससे क्या होने वाला है और आप क्या छुपाना चाहते हैं? आप मुझे बताएं कि आप क्या छुपाना चाह रहे हैं? आर0टी0आई0 सेंट्रल एक्ट है। कांग्रेस सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस एक्ट को बनाया था और आप

18-3-2026/1500/NS-AG/2

उसी एक्ट की ऐसी-तैसी करने लग पड़े। यह श्री राहुल गांधी जी का आइडिया है जिनके मार्गदर्शन में आप चल रहे हैं। यह आपकी स्थिति है इसलिए आप बहुत सारी चीजों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति देखिए। दिल्ली में ए0आई0 का एक इंटरनेशनल इवेंट होता है और उसमें यूथ कांग्रेस के नेता कपड़े उतार

कर प्रदर्शन करते हैं। आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? उसके बाद उनको 'हिमाचल सदन' शरणस्थली में दी जाती है। हिमाचल सदन में मुख्यमंत्री जी अपने सूट में ठहरे हैं और दूसरे कमरे में उन मुर्ग-मुस्सलम की पूरी सेवा हो रही है जो कपड़े उतार करके वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद उनकी सेवा वहां पूरी नहीं हुई तो उनको हिमाचल ले आए। उनका पूरी सरकारी सेवा के साथ इंतजाम किया गया जिनके खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार आपके नेतृत्व में उनका संरक्षण कर रही है और जो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आती है तो उसी पुलिस के ऊपर एफ0आई0आर0 दर्ज की जाती है। यह आपकी जवाबदेही है। ...(व्यवधान) आप रूकिए जरा, आप रूकिए तो सही। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में ये सारी चीजें नहीं होती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी पांच वर्षों तक मुख्य मंत्री रहा हूं। जब कोई इस प्रकार के इंटर-स्टेट ऑपरेशन होते थे और जिस राज्य में ऑपरेशन होता है तो वहां की जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे राज्य की पुलिस कार्रवाई करने आई है तो उनको पूरा सहयोग दिया जाए। लेकिन आप उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर रहे हैं। आपको इसमें आनंद आता है। आपको इन बातों से आनंद की अनुभूति होती है------

आर0के0एस0 द्वारा----जारी

18.03.2026/1505/RKS/AS-1

श्री जय राम ठाकुर जारी....

आप विधायकों के विरुद्ध मामलों को खोज-खोज कर निकाल रहे हैं। किसी के घर का रास्ता बंद करने तथा किसी के फार्म हाउस के मार्ग को बंद करने की तैयारियां चल रही हैं। किसी के परिवार के विरुद्ध मामले दर्ज किए जा रहे हैं और कहीं घरों की पैमाइश करवाई जा रही है। ऐसा करने से आपको क्या हासिल होगा? मुख्य मंत्री जी हमने ऐसे दौर भी देखे हैं-हम स्वयं पूरा-पूरा सत्र धरने पर बैठे रहे हैं। स्वाभाविक रूप से नेतृत्व जो निर्देश देता है उसका पालन करना पड़ता है किंतु उसका परिणाम कई बार शून्य ही रहता है। अंततोगत्वा गले ही मिलना पड़ता है। यह इतिहास हमने एक-दो बार नहीं बल्कि अनेक बार देखा है। इसलिए मेहरबानी करके आप अच्छा काम करने की कोशिश करें। क्या वजह

है कि चार साल का कार्यकाल बीत जाने के बाद भी आपकी ही पार्टी का विधायक आपकी 4 स्कीमों का जिक्र नहीं कर पा रहा है? जब आपने काम ही नहीं किया है तो फिर इसका जिक्र कैसे किया जा सकता है? मेरे पास पिछले तीन बजट सत्रों के राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों के प्वाइंट्स भी उपलब्ध हैं। यदि मैं उन सभी का उल्लेख करूं तो इसमें काफी समय लगेगा। आपके प्रथम बजट सत्र में घोषित अनेक योजनाएं ऐसी हैं जिनका चार वर्षों के उपरांत भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। इसी कारण हमें नियम-75 के अंतर्गत यह चर्चा करने के लिए विवश होना पड़ा है कि माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत इस दस्तावेज़ जिसे आपने अपने भाषण में उद्धृत किया है के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है। यह इस बात का साफ संकेत है कि आपका सदन के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। सदन में बोली हुई बात तो पत्थर की लकीर के समान होनी चाहिए। आप पुरानी बातों को तो छोड़िए आपने इसी सत्र की पिछली तीन बैठकों के दौरान कहा था कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की दोनों किस्तें शीघ्र जारी कर दी जाएंगी किंतु अब तक केवल एक ही किस्त जारी की गई है जबकि दूसरी किस्त जारी करने के प्रति आपकी कोई स्पष्ट मंशा दिखाई नहीं देती। इस विषय में भी आपको विचार करना होगा। आप यह भी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आपकी सरकार ने अच्छा कार्य किया है। आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 10 गारंटियों का उल्लेख किया था जिनमें से आप दावा कर रहे हैं कि 6 गारंटियां पूर्ण कर दी गई हैं। आपने महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी। इसके लिए मात्र 7.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि यह राशि भी लोक सभा चुनाव से पूर्व चुनिंदा

18.03.2026/1505/RKS/AS-2

क्षेत्रों में जाकर वितरित करने की घोषणा के रूप में दी गई थी। आपने काजा, पांगी और सुलह क्षेत्रों में महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की थी। आप एक किस्त जारी कर यह कैसे कह सकते हैं कि यह गारंटी पूरी हो गई है? आपने चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा था कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 15-15 सौ रुपये प्रतिमाह दे दिए जाएंगे। लेकिन चार साल बीतने के बाद आपने अभी तक 7.42 करोड़ रुपये की राशि जो साढ़े 35 हजार महिलाओं को एक ही किस्त के रूप में दी है। इसके बाद आपने और कुछ भी नहीं किया है।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

18.03.2025/1510/बी.एस./ए.एस.-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक और चीज कह रहा हूं। एक आपकी फ्लैगशिप और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बड़ी भारी बात सामने आई है। ऑर्गेनिक मक्की मूल्य 40 रुपये प्रति किलो और इसे आपने 740 किसानों से 218 मिट्रिक टन की खरीद की और उसमें आपने 87.20 खर्च किया। उसके बाद ऑर्गेनिक गेहूं, इसके आपने 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 838 किसानों से खरीदा। मैं आपकी फ्लैगशिप स्कीम की हालत देख रहा हूं कि इसका दिवाला निकल गया है। आपने इसमें 212 मिट्रिक टन और 1.27 करोड़ रुपये खर्च किया और इसके बाद ऑर्गेनिक हल्दी, आप हल्दी भी बेच रहे हैं। एक कहावत भी है, उसके बाद आगे बढ़े ऑर्गेनिक हल्दी 90 रुपये के हिसाब से आप प्रति किलो किसानों से ले रहे हैं। यह आपने 13 मिट्रिक टन ली और उसमें 11.17 लाख रुपये खर्च किये। हम अगर कुल मिला करके देखें तो यह आपकी फ्लैगशिप स्कीम की स्थिति है। जब आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ रहा और यह चौथा बजट आ रहा है। आपने अभी तक इसमें 2.26 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। आप क्या कर रहे हो? पंचायत का प्रधान 4 साल में इससे कई गुणा ज्यादा खर्च कर चुका है। आप प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं? आप प्रदेश का क्यों सत्यानाश करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं बाकी चीजों को छोड़ देता हूं। मैं बहुत बातों को सिलसिलेवार कहना चाहता था।

अध्यक्ष : अभी आप बजट भाषण के लिए भी कुछ छोड़ दीजिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ये बजट भाषण में भी इसी प्रकार का दखल देते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं, हम शून्य पर खड़े हैं। आज पूर्ण विराम पर हिमाचल प्रदेश खड़ा है। चाहे हमारा टूरिज्म का सेक्टर है, वहां पर इसे बेचा जा रहा है और बेचने की तैयारी पूरे युद्ध स्तर पर चल रही है। हिमाचल ऑन सेल।

18.03.2025/1510/बी.एस./ए.एस.-2

अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें। आज हेल्थ सेक्टर की बात करें तो रोबोटिक सर्जरी की अच्छी बात है, हाई मेडिकल फैसेलिटीज मिलनी चाहिए। इस बात से कौन बना कर रहा है? परंतु सच्चाई तो यह है जो हमको जानकारी है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। आज 10 करोड़ रुपये की मशीन और 28 करोड़ रुपये की दो मशीनें खरीदनी थी, चार मशीनें खरीद ली है।

मुख्य मंत्री : माननीय नेता पक्ष जी, अभी तो दो और खरीदनी है।

श्री जय राम ठाकुर : आप दो चार और खरीद लीजिए। लेकिन टेंडर की प्रक्रिया आपने केवल दो मशीनों के लिए की थी। अब नए सिरे से आपको वह परचेस करनी हैं तो आपको टेंडर नए सिरे से करने होंगे क्योंकि मार्केट फ्लकचुएट करती है। आप इस कीमत पर बाकी भी

खरीदते जा रहे हैं, तो यह चिंता का विषय है और प्रश्न खड़े हो रहे हैं और बहुत गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इन सारी बातों का जवाब देना मुश्किल है।

आज नियुक्तियों और नौकरियों पर पूर्ण विराम लग चुका है। चारों तरफ हा-हाकार मचा है। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी सड़कों पर, पेंशनर सड़कों पर हैं। बेरोजगार सड़कों पर है। जो हैंडिकैप्ड हैं वह सड़कों पर है। आज पूरा प्रदेश सड़कों पर है। इसलिए महामहिम राज्यपाल के प्रति मेरा पूरा सम्मान है और राज्यपाल के पद के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। लेकिन जिस तरह से इसमें कोई फैक्ट्स नहीं हैं और इस डॉक्यूमेंट में पूर्ण रूप से शून्यता है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.03.2025/1510/बी.एस./ए.एस.-3

अध्यक्षः मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष बेचारे वैसे भी शब्दों का इस्तेमाल आजकल भूलते जा रहे हैं, तनाव ग्रस्त हैं। मैं दो-तीन चीजें इनके ध्यान में लाना चाहता हूं। फ्लैगशिप, हिमकेयर प्रोग्राम इनका था और इसे हम चला रहे हैं। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हैं वे एक सोच और विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हल्दी का रेट अभी बना है और अभी इतनी ही होनी थी क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि हल्दी को भी कभी सरकार 90 रुपये प्रति किलो खरीदेगी और यह एक साल बाद होती है। आप घबराइए मत, मेरे को लगता है कि आप किसान नहीं थे। आप बचपन से ही आर0एस0एस0 में चले गए थे।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.03.2026/1515/DT/DC-1

मुख्य मंत्री जारी

मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को यही बताना चाह रहा हूं कि हिमकेयर में वर्तमान सरकार के समय 6.69 लाख लाभार्थियों को कैशलेश ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया गया और इसके लिए 1017 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने दिये। किसने दिये वह दिये हमारी सरकार ने। ...(व्यवधान) मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूं। पूर्व सरकार के समय 3 लाख 90 हजार लाभार्थी थे और उसमें 350 करोड़ रुपये पूर्व सरकार के द्वारा दिये गये यह तो आपका सहारा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ...(व्यवधान) अगर गलत आंकड़ें हैं तो सही आंकड़े आप रखिये आप जबरदस्ती न किया करें। सहारा योजना का हाल देख लीजिए। ...(व्यवधान)सुन तो लीजिए यह आप के समय के आंकड़ें हैं ...(व्यवधान) श्री विपिन सिंह परमार जी आप भी कमाल है आप नेता प्रतिपक्ष को उकसाते रहते हैं। ...(व्यवधान) मैं मानता हूं इनके ऊपर चार गुटों का दवाब है और जो इनका पांचवा गुट है वह इनका अपना गुट है और ये उसे भी नहीं बचा पा रहे। ...(व्यवधान) यह आंकड़े जिन किताबों में आपने पहले पड़े हैं उन्हीं किताबों में मिलेंगे। ...(व्यवधान) इसलिए मै अब सहारा योजना का दूसरा आंकड़ा दे रहा हूं। सहारा योजना में हमारे समय 36640 लाभार्थी हुए जिन पर 187 करोड़ रुपये हमारी सरकार के द्वारा खर्च किये गये और यह आपका फ्लैगशिप कार्यक्रम था लेकिन इस पर

खर्चा हम कर रहे हैं। ...(व्यवधान)पूर्व सरकार के समय 22000 लाभार्थी थे और उस समय जो खर्चा हुआ वह 140 करोड़ रुपये का था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी जो मैं आंकड़े इस मान्य सदन में रख रहा हूं वह फैक्ट्स के आधार पर रख रहा हूं और यह सब यहां पर रिकार्ड हो रहा है। जो आंकड़े नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस सदन में रखे गये उसके लिए इनके विरूद्ध प्रिवलेज बनता है। ...(व्यवधान) जो आंकड़े आपने इस सदन में रखे हैं मैं उसके बारे में कह रहा हूं। यह एक फैक्ट है कि 37819 लाभार्थी हमारे समय में हैं और इसमें 15774 नये लाभार्थी नये जुड़े जिस पर 202 करोड़ रुपये व्यय हुए और आपके समय में 140 करोड़ रुपये व्यय हुआ। एक और बात मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस प्रदेश में आई। आप यह मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस की श्री जय राम ठाकुर जी के साथ नाराजगी है और उन्होंने विपिन सिंह परमार जी को उठा कर ले जाना है। कानून क्या बोलता है, उच्च्तम न्यायालय की गाइडलाइंस क्या बोलती है? ...(व्यवधान) श्री

18.03.2026/1515/DT/DC-2

जय राम ठाकुर जी पांच साल इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं। हां, आप मुख्य मंत्री रहे हैं इसलिए आप थोड़ा शांत रहें। आप आज कल घटिया, नीच जाने कैसे-कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ...(व्यवधान) स्तर गिरने का कारण तनाव होता है और कोई कारण नहीं होता। तनाव में क्या होता है ...(व्यवधान) आप अपनी कुर्सी बचाने की सोचिए। हमारी सरकार ठीक-ठाक चल रही है और पांच साल ऐसे ही चलेगी। गैर-कानूनी तरीके से जब किसी को ले जाया जाता है तब प्रदेश का मुख्य मंत्री होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि 75 लाख की जनसंख्या वाले प्रदेश में अगर कोई विपिन सिंह परमार जी को ले जाने के लिए पुलिस वाला बिना किसी इन्फार्मेशन के आयेगा तो कैसे चलेगा। इसके लिए हमें देखना है कि कानून क्यो बोलता है, उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं। ...(व्यवधान) मामला दर्ज होने के बाद ही पुलिस आई है। ...(व्यवधान) अरे आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। ...(व्यवधान) आप गुस्सा मत कीजिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय, आप इन्हें प्रोसिजर बताईये that they have to seek the assistance of the local police. मुख्य मंत्री महोदय, आप इतना लंबा क्यों बोल रहे हैं इन्हें इतना कहिए कि they have to seek the assistance of the local police.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा और वह अनुरोध यह है कि आप नेता प्रतिपक्ष की सीट पर पानी का एक गिलास रखें जिसमे आईस-क्यूब्स डाली हों यानी ठंडे पानी का गिलास, क्योंकि यह बार-बार अपने स्थान पर उठ जाते हैं। विपिन सिंह परमार जी मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर माननीय नेता प्रतिपक्ष की सीट पर ठण्डे पानी का गिलास रखवा दूंगा और आपने बस नेता प्रतिपक्ष को ठंडा रखना है। आप स्वयं तो बहुत शांत हो गये हैं। मान लीजिए अगर श्री विपिन सिंह परमार जी ने भी दिल्ली में कोई अपराध किया होता और अगर वहां की पुलिस को इस प्रदेश में इन्हें पकड़ने के लिए आना होता तो दिल्ली पुलिस को संबंधित क्षेत्र जहां से श्री विपिन सिंह पमरार जी संबंध रखते है उस क्षेत्र के एस0एच0ओ0 और उस जिले के एस0पी0 को बताना होता है
श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

18.03.2026/1520/डी.सी.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री..... जारी

तब माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार को ले जा सकते हैं। लेकिन रोहड़ू वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने किसी को भी नहीं बताया था। मैं कहना चाहता हूं कि बी0जे0पी0 के किसी भी गुट के साथ ऐसा होगा तो हमारी सरकार उसकी रक्षा के लिए भी खड़ी रहेगी।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। विपक्ष का यह दायित्व बनता है कि ये लोग अच्छी बात करें और कुछ लोग अच्छी बात करते भी हैं तथा हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। श्री जय राम ठाकुर जी, यह सही है कि कोई नेता जब मुख्य मंत्री बनता है और उसके बाद विपक्ष का नेता बनता है तथा उसकी पार्टी कई गुटों में बंट जाती है तो वह अपनी कुर्सी बचाने के लिए तनाव में रहता है। मेरा यह कहना है कि तनाव होने के बाद भी उस नेता को संयम बरतना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे विनम्र

प्रार्थना है कि आगे अपने भाषण में मैं अन्य फैक्ट्स भी लाऊंगा और विपक्ष के नेतागण मुझे बार-बार टोकेंगे तथा आप मुझे बैठने के लिए कहेंगे और मैं बार-बार बैठना नहीं चाहता हूं इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप बर्फ के पानी का गिलास माननीय नेता प्रतिपक्ष के आसन के पास रख दें ताकि ये ठंडा पानी पीकर शांत रहें। नेता प्रतिपक्ष जी, आपको ठंडा पानी पीना भी चाहिए क्योंकि सेहत का ख्याल रखना अच्छी बात होती है। कुर्सी आती-जाती रहती है लेकिन आप आपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना।

अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी विधायकों के घरों के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार के दरवाजे से सम्पत्ति अर्जित की होती है तो वह सारी जनता की सम्पत्ति होती है। यदि किसी पर कोई केस बनता है तो वह बता देगा कि इतनी सम्पत्ति कहां-कहां से आई है। जब सारे कागजात मिल जाएंगे तो उसके बाद सरकार आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार किसी भी पक्ष की ओर से किए गए भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगी और हम ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं।

18.03.2026/1520/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने किसी भी माननीय विधायक का घर नहीं तोड़ा है। पूर्व सरकार के समय में माननीय सदस्य, श्री सुंदर सिंह ठाकुर के होटल के गेट तोड़ दिए गए थे।...(व्यवधान) आपने तोड़े थे और माननीय सदस्य ने उस मामले को विधान सभा में भी उठाया था।...(व्यवधान) हमने किसी का भी गेट नहीं तोड़ा है। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पारदर्शिता व ईमानदारी से काम कर रही है और जो कोई भी ईमानदारी से अपना काम करेगा उसे हमारी सरकार नहीं छेड़ेगी तथा जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार के माध्यम से सम्पत्ति कमाई है, उसे हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी और उसका सारा केस इस माननीय सदन के सभा पटल पर रखेंगे। धन्यवाद।

18.03.2026/1520/डी.सी.-एन.जी./3

अध्यक्ष : धन्यवाद। मेरे पास कांग्रेस पार्टी की ओर से लिस्ट आ गई है और उसमें पांच माननीय सदस्य शामिल हैं जोकि चर्चा में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे पास अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है इसलिए मैं माननीय सदस्य, श्री राम कुमार से आग्रह करूंगा कि वे इस चर्चा को आगे बढ़ाएं।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 16 फरवरी, 2026 को राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने जैसा कहा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण को बिना पढ़े और बिना यह कहे कि इसे पढा हुआ समझा जाए, केवल यह कह दिया कि मैं इसको नहीं पढ़ सकता। उसके बावजूद भी, क्योंकि हम सत्ता पक्ष के सदस्य हैं और उनके अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव लाना तथा उसका समर्थन करना हमारा धर्म है।

अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में सबसे पहले पैरेग्राफ का मुख्य मुद्दा यह था कि प्रदेश बहुत ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। जब से वर्तमान सरकार सत्ता में आई, तब से वर्ष 2023 और वर्ष 2025 में डिजास्टर हुआ तथा प्रदेश को हजारों करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। केंद्र सरकार की टीमों ने यहां पर भ्रमण किया और उस नुकसान का आकलन भी किया। केंद्र सरकार की टीम ने वर्ष 2023 में लगभग 9200 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश सरकार को उस नुकसान की भरपाई के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। उसके बाद पुनः वर्ष 2025 में आपदा आई और उसका भी यही हाल हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो वहां पर दूसरे देशों के लिए एक-एक हजार करोड़ रुपये की घोषणाएं करते हैं। हमारी सरकार ने विधान

सभा में प्रस्ताव लाया कि प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए लेकिन उसमें विपक्ष के साथियों ने साथ नहीं दिया।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.03.2026/1525/ए.पी. /एच.के. -1

श्री राम कुमार जारी .....

क्योंकि सत्ता पक्ष के पास समर्थन पूरा था, इसलिए प्रस्ताव पारित हुआ और केंद्र को भेजा गया। लेकिन उस प्रस्ताव पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ। वर्ष 2025 में जब आपदा आई, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए और 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश को एक फूटी-कोड़ी तक नहीं मिली। माननीय जयराम जी बार-बार कहते हैं कि हम केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं करते। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है।

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश के पास अपने संसाधन नहीं हैं। प्रदेश के पास जल है, वन हैं, लेकिन वे केंद्र के अधीन हैं। कम संसाधन होने के कारण 10 पैसे प्रदेश को खर्च करने और 90 पैसे केंद्र से हमें तमाम योजनाओं के लिए मिलते रहेंगे और वे पैसे आ भी रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आ रहा था और भाजपा की सरकार है, तब भी आ रहे हैं। लेकिन पहले कभी किसी सरकार ने यह नहीं कहा कि हर योजना के लिए केंद्र का धन्यवाद करें। लेकिन माननीय विपक्ष के नेता चाहते हैं कि हम धन्यवाद करें। हम धन्यवाद करते हैं कि केंद्र ने हमें राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए पैसा दिया। लेकिन आर0डी0जी0 बंद होना मुख्य मुद्दा था। इसके लिए विशेष सत्र बुलाने की बात हुई और चर्चा भी हुई। आज यह कह रहे हैं कि हमने विरोध कब किया, मैं तो कहता हूं कि शरेआम विरोध हुआ। जब हाथ खड़े कि आप आर0डी0जी0 के पक्ष में हैं या नहीं तो मुख्य मंत्री जी ने बार-बार पूछा कि जय राम जी बताइए, आप पक्ष में हैं या विरोध में, एक दो विधायकों ने तो साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं जा

सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बार-बार आग्रह करते रहे कि जय राम जी प्रदेश की बात है, आप साथ चलिए, लेकिन कभी भी उनकी तरफ से सहयोग नहीं आया। चोरी चुपके जा करके पता नहीं दिल्ली में जाकर के कानाफुसी करके आते हैं। और जब माननीय मुख्य मंत्री जी दिल्ली से जाते हैं तो उनको केन्द्र से उन्हें कोरा जबाव मिलता है। आज से वर्ष 1952 तक 15 बार वित्त आयोग का गठन हुआ है, जिनमें

18.03.2026/1525/ए.पी. /एच.के. -2

प्रदेश को आर0डी0जी0 ग्रांट दी गई है। लेकिन 16वें वित्त आयोग का गठन 31.12.2023 को इसका गठन हुआ, जिसका काम था 01.04.2024 से 31.3.2031 तक के पांच वर्षों की योजना की अनुशंसा वित्त आयोग ने करनी थी। लेकिन भारत सरकार की तरफ से डायरेक्शन थीं कि हिमाचल प्रदेश को रगड़ना है, इस प्रदेश का गला ओर घोटना हैं। एक तरफ से कुदरत से प्रदेश का हाल बेहाल किया है दूसरा केन्द्र सरकार भी हमारा गला दबाने का काम कर रही है। केन्द्र सरकार ने 17 राज्यों का नाम लेकर आर0डी0जी0 को बंद कर दिया। आर0डी0जी0 बंद होने के बाद नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है, तीन राज्य ऐसे हैं जिनको आर0डी0जी0 ग्रांट की सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसमें हिमाचल प्रदेश का नाम दूसरे नंबर पर है। नागालैंड का 12 प्रतिशत आर0डी0जी0 ग्रांट थी और हमारी 12.7 प्रतिशत आर0डी0जी0 के रूप में मिलता था। लेकिन इस ग्रांट के बंद होने के बाद प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव इस आर0डी0जी0 का पड़ा। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा में आर0डी0जी0 में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। 15 वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए वर्ष 2021 से 2025-26 तक लगभग 48,630/- करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 अनुशंसा की थी। शहरी और स्थानीय निकायों के लिए विषेश अनुदान राशि 855/- करोड़ रुपये से घटाकर 435 करोड़ रुपये कर दिए गए। 16वें वित्त आयोग ने आर0डी0जी0 को बंद करने की जो अनुशंसा की है। इसके लिए आयोग के संदर्भ में 2,94,500/- करोड़ रुपये जो 15वें वित्त आयोग में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इससे प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हुई है। लेकिन माननीय जय राम जी बार-बार पूछते हैं कि

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1530 /AT/HK/01

श्री राम कुमार जारी...

3 सालों में हमने क्या किया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उन चोर दरवाजों को बंद किया जो माननीय जय राम जी ने खोले थे। आज जय राम जी कहते हैं कि प्रदेश ऑन सेल है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के क्षेत्र में 5000 बीघा जमीन इन्होंने 1 रुपये और 250 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दी जिसकी सैकड़ों करोड़ रुपये की वैल्यू है। एक जगह डेढ़ सौ बीघा जमीन 15000 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से दी गई। मैं इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में उठा चुका हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि उस जमीन को कैंसिल किया जाए और ओपन मार्केट में बेचा जाए तो लगभग 300-400 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। उन लोगों को 2 वर्ष का समय दिया गया था कि वे काम शुरू करें। चाहे किसी भी पैकेज में जमीन दी गई हो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन 2-3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनका काम शुरू नहीं हुआ है। प्रदेश की संपत्ति लुटाई गई है जबकि ये कहते हैं कि हमने संपत्ति नहीं लुटाई 5 साल तक ठेकों से 10 प्रतिशत ज्यादा पैसा लेकर रिन्यूअल करते रहे। टोल टैक्स भी बहुत कम रेट पर नीलामी कि जाती रही। गैर-कर राजस्व में हमारी सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपये तक वृद्धि की है। कर-राजस्व में वृद्धि के अंतर्गत एस0जी0एस0टी0 (SGGST) से 791 करोड़ रुपये, वाहनों पर कर से 306 करोड़ रुपये और वैट से लगभग 700 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय इन 3 वर्षों में अर्जित की गई है। यह सब माननीय मुख्य मंत्री जी के सुधारात्मक कदमों के कारण संभव हुआ है। इसके अलावा, लगाए गए सेस और उपकर से अब तक लगभग 800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्रदेश को प्राप्त हुई है। गैर-कर राजस्व के अंतर्गत बिजली से 499 करोड़ रुपये, माइनिंग से लगभग 110 करोड़ रुपये, और फॉरेस्ट से लगभग 73 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। हमारी मौजूदा सरकार ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए हैं। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आदर्श स्वास्थ्य संस्थान योजना शुरू की गई जिसमें बद्दी का स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल है इसे

100-बेड का किया गया है और मैक्स अस्पताल की तर्ज पर इसे चालू किया गया है,टांडा मेडिकल कॉलेज और आई0जी0एम0सी0 शिमला के बाद बद्दी पहला ऐसा अस्पताल है जहां ओ0पी0डी0 को बाहर अलग से चलाया गया है जिसका

18.03.2026/1530 /AT/HK /02

5 दिन पहले उद्घाटन किया गया है। प्रदेश में अब तक 70 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान शुरू किए जा चुके हैं। इनमें लगभग 134 प्रकार की जांच सुविधाएं जैसे अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्स-रे उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन संस्थानों में कम से कम 6 विशेषज्ञ डॉक्टर मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया और एडर्मेटोलॉजी की सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्रदेश सरकार ने कार्य किया है। राज्य के दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधा देने के लिए सरकार ने 3 वर्षों में एक महत्वपूर्ण पहल की है। जिला सोलन की तहसील कंडाघाट में लगभग 45 बीघा भूमि पर दिव्यांग शिक्षा उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिस पर 168.42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और अब तक लगभग 69121000 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्थान के अंतर्गत 15 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण प्रदेश सरकार द्वारा किया जा चुका है और आगामी वर्ष में इस पर लगभग 20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हमारी सरकार ने सामाजिक कल्याण और जन-स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए जिला सिरमौर के कोटा ब्रोग, उप-तहसील नर्ग, उप-मंडल पच्छाद (सराहां) में 142.07 बीघा भूमि पर नशे के आदी पुरुषों और महिलाओं के लिए 100-बिस्तरों (50 पुरुष, 50 महिलाएं) वाला स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मॉडल नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1535/केएस/वाईके/1

श्री राम कुमार जारी ---

यह हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है क्योंकि प्रदेश के हजारों युवा चिट्टे की लपेट में आ रहे थे जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पैशल ड्राइव स्टार्ट करके पूरे प्रदेश के सभी बच्चों के साथ पहले शिमला में और फिर धर्मशाला में एक रैली की जिसमें हमारे विपक्ष के साथियों ने भी सहयोग दिया, इनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि चिट्टा एक ऐसी बला है जो इसका सेवन करना शुरू कर देता है उसका जीवन तीन या चार वर्ष में समाप्त हो जाता है। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में लगभग 25-30 युवाओं ने इसकी वजह से अपनी जान गवां दी है। हमारा बॉर्डर एरिया है और पुलिस प्रत्येक दिन किसी न किसी युवा को चिट्टे के साथ पकड़ती है लेकिन मात्रा कम होने के कारण उनकी जमानत हो जाती है। मुख्य मंत्री जी ने चाहा कि इसमें कड़े कानून बनाए जाएं और उसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान हो। आरोपियों की संपत्ति को तोड़ने व प्रदेश सरकार के कब्जे में करने का प्रावधान जैसा कानून हमारी सरकार ने बनाया जिसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा।

इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 21 हज़ार 329 लाभार्थियों को लगभग 22 करोड़ 65 लाख व नारी सेवा सदन योजना के अंतर्गत 24 लाभार्थियों को लगभग 51 लाख रुपये की राशि जारी की है।

हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत की है और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 744 किसानों से 218 मीट्रिक टन मक्की, 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 838 किसानों से 212 मीट्रिक टन गेहूं व 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 61 किसानों से 13 मीट्रिक टन प्राकृतिक कच्ची हल्दी की खरीद की गई जिसका ज़िक्र अभी जय राम जी भी कर रहे थे। अभी इसकी शुरुआत है और आने वाले समय में इसकी मात्रा भी बढ़ेगी और हमारे जो किसान इस तरह की खेती करते हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि जैसे-जैसे लोगों को इस बारे में पता लग रहा है, लोग आगे आ रहे हैं।

हमारी सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में मुख्य मंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योना (बाड़बन्दी) के अंतर्गत 520 हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है। क्योंकि हिमाचल में बंदरों

के कारण लोगों ने खेती करना छोड़ दिया था इसलिए इस योजना का लाना बहुत ज़रूरी था। रोज़ हमें कहीं ना कहीं से किसानों के प्रस्ताव आते हैं कि हमारे यहां बंदरों के कारण खेती होना बंद हो गया है, हमारे खेतों को बाड़बन्दी के तहत लाया जाए। तो यह प्रदेश सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी योजना किसानों के हित में शुरू की गई है जिस पर 25 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है और 1 हज़ार 75 किसान लाभान्वित हुए हैं। मुख्य मंत्री कृषि संवर्धन योजना के अंतर्गत भी 18 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई है।

मौजूदा सरकार द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने हेतु आरम्भ की गई हिम कृषि योजना के अंतर्गत अब तक 724 क्लस्टरों की पहचान कर 20 करोड़ **रुपये की राशि आबंटित की गई है जिससे बहुत सारे किसानों को लाभ हो रहा है।**

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री राम कुमार : सर, सिर्फ 2-3 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मौजूदा सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रथम और द्वितीय कक्षा में अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया था और अब शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा तीन से कक्षा पांच तक अंग्रेजी माध्यम लागू किया जा रहा है। यह व्यवस्था आने वाले वर्षों में क्रमशः उच्च कक्षाओं तक विस्तारित की जानी प्रस्तावित है।

प्री-पाइमरी स्कूलों में मजबूत निवेश, बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए हमारी सरकार ने लगभग 6 हजार 297 प्राथमिक स्कूलों में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। 130 के लगभग सी0बी0एस0ई0 स्कूलों की हमारी सरकार ने नोटिफिकेशन की है जिसमें दून क्षेत्र के तीन स्कूल भी शामिल हैं और इसके लिए भी मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। जो आज तक कार्य नहीं हुआ, हमारी सरकार वह कार्य कर रही है।

हमारी सरकार ने वर्ष 2023 में विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया जिसे वर्ष 2025 में भी लागू किया। पहले जहां पूरी तरह से नष्ट हो चुके आवासों के लिए एक आदमी को 1

लाख 30 हजार रुपये मिलते थे अब उनको विशेष पैकेज के तौर पर 7 लाख रुपये की राशि दी जा रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2026/1540/av/yk/1

श्री राम कुमार------जारी

और पहले जहां पर आपदा में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत के लिए केवल 10 हजार रुपये की राशि मिलती थी उसको अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री ने इतनी ज्यादा तंगी के बावजूद भी इन सारी योजनाओं को जारी रखा है। माननीय जय राम ठाकुर कह रहे थे कि आपने हमें जो प्रेजेंटेशन में दिखाया है तो बजट में क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बजट में भी सब कुछ होगा।

आप यहां पर बार-बार 1500 रुपये की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की महिलाओं को जो 1500-1500 रुपये देने का वायदा किया गया है, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री उसको देने के बारे में मन्थन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार अपनी आय बढ़ाने हेतु दिन-रात प्रयासरत है। शराब के ठेकों की नीलामी से राजस्व में अथाह वृद्धि हुई है और उसके तहत प्रदेश सरकार ने पैसा कमाया है।

मेरा अंत में यही कहना है कि जय राम ठाकुर जी ने चोर दरवाजे खोलकर जो प्रदेश की संपदा को लुटाने का काम किया था, हमने उसको बंद किया है तथा प्रदेश की आय में अथाह वृद्धि की है। केंद्र के द्वारा गला घोंटने के बावजूद भी मुख्य मंत्री सभी योजनाओं को ब-दस्तूर रख हुए हैं और आगे भी उनको जारी रखने का मादा रखते हैं।

सभापति महोदय, इन्ही शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

18.03.2026/1540/av/yk/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री प्रकाश राणा भाग लेंगे।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

हम तो समझते हैं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था, उसका पूरा लेखा-जोखा कि सरकार द्वारा की गई किन-किन घोषणाओं को पूरा किया गया है और कौन-कौन से काम अधूरे हैं तथा सरकार को उनको चलाने में क्या-क्या कठिनाइयां आ रही हैं। ऐसी घोषणाएं जो पूरी नहीं हो पाईं उनके क्या कारण रहे। सरकार ने कितना कर्ज लिया, कितना भरा; इस अभिभाषण में ये सारी बातें आनी चाहिए। परंतु यहां पर तो कुछ और चर्चा होती है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश को जो-जो भी समस्याएं आती हैं उनको जनता के सामने रखा जाए। वे चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र की हैं या यहां पर बैठे किसी भी माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र की हैं। यहां पर सभी की यही अपेक्षा रहती है। परंतु मुझे लगता है कि हम यहां पर बार-बार एक ही बात पर जाते हैं और वह एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की बात है। यहां पर या तो कोई ऐसा रूल बनाया जाए कि हम पिछली बातों को ही न उठाएं ताकि हम आगे चलें और आगे चलकर इस प्रदेश के लिए कुछ करें। इस प्रकार से एक-दूसरे के लिए बोलकर टाइम पास करना, मैं भी अब वही बात करूंगा जो सब कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से तीन दिन के लिए बजट सत्र बुलाया गया तो उसमें बजट वाली तो कोई बात ही नहीं थी। उसमें केवल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। यहां पर जो वित्त विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन रखी गई उस सत्र को बुलाने का मुख्य कारण भी वही था। किसी नई चीज, नये कार्य या प्रदेश के लिए इन्कम रिसोर्स कैसे जनरेट करें या प्रदेश के लिए कोई नई योजना आए; कोई भी प्रेजेंटेशन इसलिए रखी जाती है परंतु यह जो प्रेजेंटेशन दिखाई गई उसको देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां पर अपनी असफलता की प्रेजेंटेशन दिखाई गई और उसको पूरे भारतवर्ष व विश्व में देखा गया। यह केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं अपितु हमारे लिए भी एक दुःख की बात है।

टी सी द्वारा जारी

18.03.2026/1545/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री प्रकाश राणा .... जारी

इसमें हम सब भागीदार हैं। मुझे भी कई जगह से कॉल आई कि प्रदेश को क्या हो गया यानी इतनी शौक से असफलता और नाकामयाबी की प्रेजेंटेशन दिखाई गई। इस तरह की प्रेजेंटेशन यहां नहीं होनी चाहिए थी। यह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने जैसा है। इससे किसी का भला नहीं होगा और न ही प्रदेश का हित होगा।

सभापति महोदय, प्रेजेंटेशन ऐसी दिखाई गई कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के हाथ खड़े है। उनका कहना है कि हमारा रेवेन्यू कुल मिलाकर 17000-18000 करोड़ रुपये के आसपास है जिसमें से एक साल में हमने 13000 करोड़ रुपये कर्ज के देने हैं। अब हमारे पास लगभग 5000 करोड़ रुपये बचते हैं। केंद्र का जो शेयर आ रहा है, वह 13,200 करोड़ रुपये है। उसमें वृद्धि हुई है उसके लिए केन्द्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। अगर दोनों को मिलाएं तो लगभग 18,900 करोड़ रुपये सालाना इन्कम बनती है। अगर इसे प्रति माह देखें तो लगभग 1575 करोड़ रुपये हैं। अब इन 1575 करोड़ रुपये से सैलरी देंगे, पेंशन देंगे या प्रदेश का विकास करेंगे, यह सोचने वाली बात है। अगर सैलरी पर 1200-1300 करोड़ रुपये और पेंशन पर 1100 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं यानी लगभग 2400 करोड़ रुपये प्रतिमाह इन पर ही खर्च हो रहे हैं। जबकि हमारे पास 1575 करोड़ रुपये ही हैं। मेरा यह मानना है कि हमें इस पर डिस्कशन करनी चाहिए। हम मुख्य मंत्री जी के प्रोग्राम देखते हैं, जबकि फाइनेंस डिपार्टमैंट कहता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और यह सब बंद करो। लेकिन दूसरी ओर नई पंचायतों की घोषणाएं हो रही हैं। 100, 200, 50 करोड़ व 10 करोड़ रुपये की स्कीम्स घोषित की जा रही हैं लेकिन इनके लिए पैसा कहां से आएगा, यह भी बताना चाहिए। इनका कहना है कि हम कर्ज लेंगे और हमारी लिमिट 10000 करोड़ रुपये है। अगर 10000 करोड़ रुपये कर्ज भी ले लेंगे तो भी स्थिति नहीं सुधरेगी। अगर 1575 करोड़ रुपये सैलरी, पेंशन का देते हैं तो 2400 करोड़ रुपये में से 835 करोड़ रुपये ही बचता है। अगर 10000 करोड़ रुपये को 12 महीने में बांटें लें तो भी वह लगभग 833 करोड़ रुपये बनता है और लगभग 200 करोड़ रुपये की कमी रह जाती है।

18.03.2026/1545/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

आज प्रदेश पर 100000 करोड़ रुपये से अधिक कर्ज है और हर साल 13000 करोड़ रुपये चुकाना पड़ता है। अगर 5 वर्षों में 50000 करोड़ रुपये और जुड़ गया तो कुल कर्ज 150000 करोड़ रुपये हो जाएगा। फिर 20000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे, यह बड़ा सवाल है।

इसके बावजूद भी ये लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं, पंचायतें बनाई जा रही हैं। लेकिन पहले से जो पंचायतें हैं, वहां पंचायत सचिव तक नहीं हैं। कई पंचायतें बिना सचिव के चल रही हैं। एक पंचायत सचिव के पास 3, 4 पंचायतें हैं, कहीं-कहीं 5-5 पंचायतें भी हैं। अगर आप नई पंचायतें बनाने की घोषणा कर रहे हैं तो उनको बनाने का कोई प्रॉपर क्राइटेरिया भी होना चाहिए। जहां 1500, 2000 की आबादी है, वहां भी 2-2 पंचायतें बनाई जा रही हैं। जबकि कई पंचायतें ऐसी भी हैं जहां 3000 से ज्यादा वोटर हैं लेकिन वहां वही स्थिति बनी हुई है। अगर पंचायत बनानी है तो उसके लिए स्पष्ट क्राइटेरिया भी होना चाहिए। एक भवन बनाने के लिए भी कम से कम 150-200 करोड़ रुपये की जरूरत होती है। वह पैसा कहां से आएगा जबकि स्टाफ की पहले ही कमी है। इस तरह से आप प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, यह मेरी समझ से बाहर है। हमें यह सोचना चाहिए कि प्रदेश कैसे चलेगा, पैसा कहां से आएगा? केवल 100, 200 करोड़ या 400 करोड़ रुपये की घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा। क्या यह सच नहीं है कि

एन0एस0 द्वारा .... जारी

18-3-2026/1550/NS-AG/1

श्री प्रकाश राणा ----जारी

मुख्य मंत्री जी ने अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा कर्ज लिया, फिर भी हम वहीं के वहीं पहुंच गए। मैं कहता हूं कि ये जो यहां पर बातें हो रही हैं और जैसा यहां एक मित्र बता रहे थे कि प्रकाश राणा ने भी यहां बोला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राणा सही बात कर रहे हैं और मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैं तो चाहता हूं कि आप प्रदेश को सही दिशा में

लेकर जाएं। यहां पर कर्ज की बात हो रही थी। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इतिहास देखा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे 15 से 17 वर्षों तक प्रदेश में रही हैं और उन्होंने लगभग 17 वर्षों तक उतना कर्ज नहीं लिया जितना आपने 3 साल में ले लिया। अगर ऐसा नहीं है तो आप यहां पर श्वेत पत्र जारी करें। यही सच्चाई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगभग 18 वर्षों तक सरकारें रही हैं और हमारी सरकारों ने इतना कर्जा नहीं लिया जितना वर्तमान सरकार ने साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में ले लिया है। फिर भी प्रदेश वहीं का वहीं है। मैं भी यही कहना चाहता हूं जैसे आप कह रहे हैं कि आज भारत वर्ष में हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें प्रति व्यक्ति के ऊपर 1.50 लाख रुपये का कर्ज हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या देश में ऐसा कोई और राज्य है? हमारे प्रदेश के साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने प्रदेश के लिए मिल कर कुछ करें। हमें अपने इनकम सोर्सिज बढ़ाने होंगे और खर्चे कम करने होंगे लेकिन खर्चे तो कम हो ही नहीं रहे हैं। आपने इस दस्तावेज में लिखा है और बताया है कि हमें प्रदेश को चलाने के लिए कम-से-कम हर साल 48,000 करोड़ रुपये चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि ये 48,000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे? आप विकास कार्य कैसे करने हैं। हमारा स्वास्थ्य व शिक्षा का क्षेत्र कैसे चलेगा? सरकार के पास तो सैलरी और पेंशन देने के लिए भी पैसा नहीं है। तब विकास कार्य कैसे होंगे? हम आपस में क्यों लड़ते हैं और यह बात मुझे समझ नहीं आती है। हम लड़ते थे कि कर्ज मिलेगा तो हम इसको बांटेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब कर्ज की भी लिमिट खत्म हो रही है। आज तो आर0डी0जी0 बंद हुई है अगर कल को कर्ज की लिमिट भी खत्म हो गई तो हम कहां जाएंगे? मुझे लगता है कि ऐसा भी होने वाला है क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है।

सभापति महोदय, यह प्रदेश बर्बाद कैसे हुआ? मैंने उसमें भी नज़र डाली थी कि प्रदेश बर्बाद कैसे हुआ? अब प्रदेश में जैसे ही सरकार चेंज होती है तो पिछली सरकार के समय में हजारों करोड़ रुपये की स्कीमें लगी होती हैं और सत्ता में आने

18-3-2026/1550/NS-AG/2

वाली सरकार उन सभी स्कीमों को बंद कर देती है और नई स्कीम चालू कर देती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपने कार्यकाल में कितनी नई स्कीमें चालू की हैं? अब

तो आपका कार्यकाल भी कम ही रह गया है। प्रदेश की बर्बादी का एक कारण यह भी है। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारी लापरवाही से प्रदेश बर्बाद हो गया।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे क्षेत्र में ऊहल-II। चूल्हा प्रोजैक्ट लगा और 100 मेगावाट का प्रोजैक्ट है। यह प्रोजैक्ट धर्मपुर के आसपास ही है और यहां पर धर्मपुर के विधायक भी भी बैठे हैं तथा इनको भी इसके बारे में पता होगा। र मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि प्रदेश बर्बादी कैसे हुई? जब मैंने इस प्रोजैक्ट की फाइल देखी तो 430 करोड़ रुपये में यह प्रोजैक्ट बनना था। यह प्रोजैक्ट वर्ष 2003 में चालू हुआ और वर्ष 2010 में बन कर तैयार होना था। यह प्रोजैक्ट डीले होते-होते वर्ष 2025 में चला गया और अब चालू हुआ। अब आप बताओ कि 430 करोड़ रुपये का यह 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और आज यह प्रोजैक्ट 3100 करोड़ रुपये में पहुंच गया है। ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। यह प्रोजैक्ट 3100 करोड़ रुपये तक कैसे पहुंच गया और उसको भी मैंने देखा। मैं मानता हूं कि थोड़ा-बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने दोबारा फाइल मंगवाई तो पता चला कि उसमें मशीनरी दोबारा आई और राशि डबल हो गई लेकिन वह तो अभी भी लगभग 900 करोड़ रुपये की है। वहां पर जो लेबर या स्टाफ काम कर रहा है तो उनकी संख्या भी लगभग 200 है और 30-35 करोड़ रुपये उनके बनते हैं। यह प्रोजैक्ट लगभग 1200 करोड़ रुपये का है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब यह 3100 करोड़ रुपये का कैसे हो गया? यह हैरानी की बात है।

सभापति महोदय, इसमें लगभग 1800 करोड़ रुपये तो ब्याज ही हो गया है।

आर0के0एस0 द्वारा----जारी

18.03.2026/1555/RKS/AS-1

श्री प्रकाश राणा जारी....

आप बताइए कि यह 17-18 सौ करोड़ रुपये ब्याज कैसे हो गया? उन्होंने 11.89 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उठाया है। इस प्रोजैक्ट का हर माह बैंक में साढ़े 14 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में जमा हो रहा है। उस प्रोजैक्ट की इतनी इंकम नहीं है लेकिन यह पैसा 30 साल तक

भरना पड़ेगा। इस तरह आप इस प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं? अब प्रश्न यह है कि जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं यह एक क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं लेकिन ऐसा हिमाचल प्रदेश में कई क्षेत्रों में हुआ है। अगर आज हमें 14 हजार करोड़ रुपये ब्याज न देना पड़ता तो प्रदेश की स्थिति भिन्न होती। हिमाचल प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिमाचल की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकते लेकिन हमने इसके लिए पग उठाना छोड़ दिये हैं। अगर RDG बंद हो गई है तो अब आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? हमें अपने संसाधन जुटाकर इस प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। अब RDG के पीछे लगे रहना उचित नहीं है। हमें अपने आय स्त्रोतों को विकसित करना होगा। वर्तमान में प्रदेश मुख्यतः केंद्र की योजनाओं पर चल रहा है। चाहे प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, प्रधान मंत्री सिंचाई योजना हो, फोर-लेन परियोजनाएं हों या रेलवे से संबंधित कार्य हो, ये सब कार्य केंद्र के धन से ही संचालित हो रहे हैं। मैंने देखा कि पिछले तीन वर्षों में केंद्र से इस प्रदेश को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि प्राप्त हुई है। आप इसे मानें या न मानें लेकिन यदि गहराई से देखें तो हमारे पास स्वयं के आय स्त्रोत विकसित करने के पर्याप्त अवसर हैं। हमने आयुर्वेद क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया है। हमारे पास आयुर्वेद में बहुत ज्यादा ऑप्शन्ज हैं। जोगिंदरनगर में लगभग 24 एकड़ भूमि में हर्बल गार्डन स्थापित है जहां विभिन्न प्रकार की औषधीय पौधों की खेती हो रही है। यदि इसके लिए कोई समिति या टीम बनाई जाती तो इसका बेहतर उपयोग किया जा सकता था। इसी प्रकार बिलासपुर के झलेरा में लगभग साढ़े आठ एकड़ भूमि में हर्बल गार्डन स्थापित है। हमीरपुर के नेरी और रोहडू के घमरेड़ा में भी हर्बल गार्डन हैं। आज विश्व आयुर्वेद की ओर बढ़ रहा है और हमारे पास यह अवसर पहले ही उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास जल विद्युत क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। वर्तमान में हमारे प्रदेश में लगभग 14 हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है जबकि यह क्षमता लगभग 25 हजार मेगावाट तक हो सकती है यानी हम लगभग 11 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली तैयार कर सकते हैं। यदि 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक दिन में

18.03.2026/1555/RKS/AS-2

लगभग 90 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की बिजली पैदा करता है तो इसकी संभावनाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास खनन, बागवानी, कृषि

तथा पर्यटन जैसे क्षेत्र भी हैं लेकिन हम इनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इस प्रदेश को चलाना इतना कठिन नहीं है। हमारे पास 68 विधान सभा क्षेत्र हैं। यदि प्रत्येक क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की आय हो तो हमारा कार्य आसानी से चल सकता है। यदि हम 68 क्षेत्रों से प्रतिदिन डेढ़ करोड़ रुपये उठाते हैं तो हम अच्छा बिजनैस कर सकते हैं। हमारे पास केंद्र से लगभग 14 हजार करोड़ रुपये आ रहे हैं जिससे हमारी कुल आय लगभग 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह सीधी बात है और प्रत्येक क्षेत्र में इसके अवसर उपलब्ध हैं। हमारे पास जो संस्थान और रेस्टोरेंट इत्यादि हैं वे सब घाटे में चल रहे हैं। प्रत्येक सैक्टर लोस में चल रहा है। जैसा कि वित्त विभाग ने कहा है- State Government will not be able to defray pay/ pension revision arrears of about Rs. 8500 crore.

श्री बी0एस0 द्वारा जारी....

18.03.2025/1600/बी.एस./ए.एस.-1

श्री प्रकाश राणा जारी...

यानी जो 8 हजार 5 सौ करोड़ रुपये देने को है उसे सरकार दे नहीं पा रही है और 5,000 करोड़ रुपये दिखा रहे हैं कि State Government will not be able to pay DA/DR arrears amounting to Rs. 5000 crore. वह भी 5 हजार करोड़ रुपये है। यानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। इसमें कहा कि जो लायबिलिटी है, जो कोर्ट में अभी डिसीजन पड़े हैं उसके लिए भी अभी एक हजार करोड़ रुपये के करीब है। अगर देखा जाए तो 20 हजार करोड़ रुपये का कर्ज तो यही दिखाई दे रहा है। जिसके लिए लोग आस लगा करके बैठे हैं कि कब देंगे, कब देंगे और कैसा देंगे? इन्होंने सब्सिडी के लिए कह दिया कि सब कुछ जीरो, सब जीरो बता दिया है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रकाश राणा : सभापति महोदय, न फंड है, न पावर सब्सिडी मिलेगी, न सोशल सिक्योरिटी पेंशन है। वह भी हम नहीं दे पाएंगे। तो कुछ भी नहीं है। the DA has to be

frozen यानी सब कुछ ही बंद है। तो फिर इधर लड़ाई किसकी है? यहां पर जब सब कुछ बंद है फाइनेंस जब बोल रहा है या तो फाइनेंस को कहो कि पहले तो यह दिखा दो कि इनके पास क्या है? फिर हम डिस्कशन करें। मेरा कहने का मतलब है, मैं सभापति महोदय और सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसा जो समय अब आया है ऐसा ही समय पहले भी था परंतु सरकार चली, जैसे चली परंतु चली। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा है। अब तो हमारे पास पेंशन सैलरी देने को पैसा नहीं है। जैसा फाइनेंस वाले कह रहे हैं कि 10 हजार करोड़ रुपये हम कर्जा लेंगे और हर साल लेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस कर्जे से जैसे तैसे थोड़ा छुटकारा पाइए। अगर इसे छुटकारा नहीं पाओगे तो अगले 5 सालों में डेढ़ लाख करोड़ कर्ज होगा तो 20 हजार करोड़ रुपये कहां से लाओगे? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मुख्य मंत्री से कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप घोषणाएं कर रहे हैं, पहले यह तो बता दो कि आपके पास पैसा कहां है? आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने सही कहा कि कोई जादू की छड़ी तो नहीं है इधर सब के ऊपर चल जाएगी। हमारे पास पैसा कहां है? अब इधर हम टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट करके क्या फायदा? यहां पर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा करके निकल जाएंगे कि हो गया काम। इतना टाइम अगर कहीं हमें मिलता तो हम ऐसे-ऐसे

18.03.2025/1600/बी.एस./ए.एस.-2

डिसीजन ले लेते कि यह प्रदेश ही उठ जाता है। आज बात प्रदेश को उठाने की कीजिए। ये पहले की बातें भूल जाओ कि उसने क्या किया, उसने क्या किया? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप सही करके दिखाइए कि मैं कहां गलत बोल रहा हूं। आपने कर्ज भी खूब लिया और अब कहते हैं कुछ भी नहीं है। अब बताओ कि क्या करें?

केवल हमारी आर0डी0जी0 ही बंद हुई होती तो हम भी आपके साथ होते। आर0डी0जी0 सब की बंद हुई तो क्या करें? बंद हो गई तो हो गई। इसे मांगेने के लिए अब हम ही चले या बाकी भी केन्द्र सरकार के पास जाएंगे? क्या यह हमारे जाने से मिल जाएगी? आपको अपने साधन जुटाना पड़ेंगे। एक ही फोकस करिए कि हमनें इनकम सोर्सिज कैसे इंक्रीज करने हैं और अपने खर्चे कैसे कम करने हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और आप इसे मानिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप बहुत जोर-जोर से घंटी बजा रहे हैं। मुझे दो मिनट और बोलना था, आपका धन्यवाद।

सभापति : माननीय सदस्य, आपने 20 मिनट से ज्यादा बोल लिया है। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री सुदर्शन सिंह बबलू जी भाग लेंगे।

18.03.2025/1600/बी.एस./ए.एस.-3

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा।

हम भी पिछले तीन वर्षों से देख रहे हैं कि राज्यपाल महोदय आते हैं और सरकार की कार्य प्रणाली जो तीन वर्ष में रही है उसके ऊपर पूरी अभिभाष पढ़ते हैं और लगभग एक घंटा-डेढ़ घंटा वह अभिभाषण पढ़ा जाता है परंतु हमने पहली बार यह देखा है कि सिर्फ डेढ़ मिनट में ही पूरा अभिभाषण पढ़ दिया गया और बाद में यह बोला गया कि यह जो अभिभाषण है इस पूरे को पढ़ा हुआ समझा जाए। अब किस तरीके के प्रेशर के अंदर थे? वह हम नहीं जानते। परंतु फिर भी अपने इस भाषण पर मुझे बोलने मौका दिया मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सरकार की जो 3 वर्ष की उपलब्धियां रही है वे इस पूरे आभूषण में होती हैं तो वह शायद इसमें भी होंगी और इन उपलब्धियों को पढ़ा जाता तो हिमाचल प्रदेश की जनता तक पहुंचनी थी। क्योंकि अभी चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। डेढ़ साल बाद चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले पंचायत के चुनाव हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि कुछ ऐसा प्रेशर उनके ऊपर हो।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.03.2026/1605/DT/DC-1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी...

फिर जो सरकार की तीन साल की उपलब्धियां रहीं हैं वह एतिहासिक हैं। मैं यह समझता हूं कि हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में जहां हमारी सरकार ने चुनौतियों का सामना

किया वहीं प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं की है। यह भी प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। वर्ष 2023 में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा इस प्रदेश में आई थी और उसके बाद वर्ष 2024 में भी प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी। उसके बाद सरकार के ऊपर भी संकट आया। लेकिन इन सभी आपदाओं से उभर कर हमारी सरकार प्रदेश हित में आगे बढ़ रही है। इससे पहले तीन दिन का स्पैशल सैशन माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा बुलाया गया था और उसमें केवल आर0डी0जी0 के ऊपर ही चर्चा होनी थी। मुझसे पहले के वक्ता सम्माननीय श्री प्रकाश राणा जी ने बोला कि हमें प्रदेश की इंकम बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी अपनी बात रखूंगा।

प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा बहुत ही सराहनीय कदम उठाये गये हैं। पूर्व सरकार के समय धर्मशाला में इंवेस्टर मीट आयोजित की गई थी। उसके आयोजन में पूर्व सरकार के द्वारा करोड़ो रुपये खर्च किए गये। लेकिन उस इंवेस्टर मीट पर इतना खर्च करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में कोई कंपनी इंवेस्ट करने आई हो। आपने करोड़ों रुपये का बजट उस इंवेस्टर मीट पर खर्च किया। बड़े-बड़े टेंट लगाये हजारों लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया। उसमें देश-विदेश से इंवेस्टर आये लेकिन प्रदेश में सड़कों की दयनीय स्थिति व तत्कालीन सरकार की कार्य प्रणाली को देख कर वह लोग इस प्रदेश में इंवेस्ट करने नहीं आये। कोई कंपनी यहां इंवेस्ट करने नहीं आई। इसके विपरीत मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार ने सराहनीय कदम उठाये हैं चाहे शराब के ठेकों के टेंडर की बात हो, पूर्व सरकार के समय तो 10 प्रतिशत रेट बढ़ाकर उन्ही लोगों को फिर से टेंडर दे दिए जाते थे। इस दिशा में माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गयें हैं वह सराहनीय हैं जिससे करोड़ों की धनराशि प्रदेश के राजस्व में आई है। इस सदन में खड़े होकर कुछ भी बोलना या सरकार को सलाह देना बहुत ही आसान बात है। लेकिन प्रैक्टिकली इसके ऊपर कैसे काम करना है-यह हमारी सरकार से सीखा जा सकता है। हमारी सरकार आपदाओं से गुजर कर यहां तक पहुंची है और जिस तरीके से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है वह अपने आप में एतिहासिक है। प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में इस प्रदेश सरकार के कार्यों की चर्चा हो रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री श्री शांता कुमार जी, जो भाजपा के बड़े नेता भी हैं, उनके द्वारा भी हमारी सरकार की प्रसंसा की गई है। नीति आयोग

18.03.2026/1605/DT/DC-2

ने भी प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की है। इसलिए मेरा मानना है कि विपक्ष के साथियों को सरकार की उपलब्धियां हज़म नहीं हो पा रहीं। आर0डी0जी0 के ऊपर तीन दिन इस सदन में चर्चा हुई। जो प्रदेश की आर0डी0जी0 केंद्र सरकार के द्वारा बंद की जा रही है वह आर0डी0जी0 प्रदेश सरकार के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के वेल्फेयर के लिए है। इस आर0डी0तजी0 से प्रदेश के आम लोगों को लाभ मिलना था। इस सदन में तीन दिन आर0डी0जी0 पर चर्चा होने के बाद भी विपक्ष द्वारा उसका समर्थन नहीं किया गया।

इस सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह दो बार माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष आर0डी0जी0 को बहाल करवाने के लिए नहीं बल्कि उसे बंद करवाने के लिए वहां पर गये थे क्योंकि आर0डी0जी0 का प्रस्ताव वर्तमान प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया था। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य मंत्री जी प्रत्येक बैठक व प्रत्येक सैशन में नेता प्रतिपक्ष को बोलते रहे कि हम आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास आर0डी0जी0 को बहाल करवाने के लिए चलते हैं। इस सदन में 68 विधायक हैं, मंत्री मंडल यहां पर बैठा है, विपक्ष के लोग यहां पर हैं-तो मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि आपने इस सदन के अंदर आर0डी0जी0 के संबंध में हामी क्यों नहीं भरी कि हम आर0डी0जी0 के फेवर में आप के साथ हैं और हम मिलकर माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष कह रहें हैं कि वह केंद्रीय वित्त मंत्री से मिलकर आये हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि "जंगल में मोर नाचा किसने देखा"। इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से क्या बात की है? वे तो हमें भी पता है कि क्या बात की होगी और प्रदेश की जनता को भी पता है कि क्या बात की होगी। पर तीन दिन आर0डी0जी0 पर इस सदन में सार्थक चर्चा हुई उससे पहले जब हमारे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई तो उस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए हम उस पर भी स्पैशल चर्चा लाये थे लेकिन चर्चा के उपरांत उस प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी तो उस समय भी विपक्ष के हमारे साथी सदन से वॉक-आउट कर गये। इनका यह रवैया यह दर्शाता है कि हिमाचल के लोगों के हितों के लिए इनके मन मे कैसी भावना है। मैं एक उदाहरण के साथ यह बोलना चाहूंगा कि हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता ही है जो

विकास के कामों को रोकता है। हर गांव में अड़ंगे डालने वाला आदमी होता ही है। मेरे गांव में भी एक ऐसा

18.03.2026/1605/DT/DC-3

ही आदमी था जिसका नाम था कपता सिंह उसका यही काम था कि गांव में कोई भी अच्छा काम होता था तो वह उसमें अपनी टांग जरूर अड़ाता था। हमारे गांव में एक आम का बहुत ही पुराना बुटा था और उस बुटे के आम बहुत मिठे थे। लोग उसके आम बहुत शोक से खाते थे। उसको ऐसा लगता था कि आम का जो बुटा है वह मेरे घर से बहुत दूर है और मैं तो उसके फल खा ही नहीं पाता। उस बुटे के फल तो आस-पास के दो चार गांव के लोग ही खा रहे हैं, उस बुटे का मुझे क्या फायदा? उस आदमी ने वह आम का बुटा ही उखाड़ दिया। लोगों ने उसे समझाया कि तू ऐसा न कर

एन0जी0 द्वारा जारी...

18.03.2026/1610/डी.सी.-एन.जी./1

श्री सुदर्शन सिंह बबलू..... जारी

(पंजाबी भाषा में कहा गया) दो-चार पिंडा दे लोग खाए जारे, ते मैनू की फायदा हो रेया और उन्ने अम्ब दा बूटा ही फड़ दित्ता। उन्नौ लोकां ने समझाया सी की लोकां ऐदा दे फल खारे और ओ केन्दा सी कि मैनू तां कोई फायदा ही नी हो रेया।

सभापति महोदय, आज विपक्ष के लोग भी वहीं काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने भी आर0डी0जी0 रूपी उस आम के बूटे (पेड़) को उखाड़ने का काम किया है। उस आर0डी0जी0 से पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को फायदा हो रहा था और विपक्ष के लोगों ने उस आम के पेड़ को काटने की कोशिश की है। इन्होंने उसका समर्थन भी नहीं किया है। मैं यही मानता हूं कि (पंजाबी भाषा में कहा गया) (***)मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति इस प्रकार की नेगेटिव सोच लेकर बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता इनको देख रही है।

सभापति : (***)वाले पार्ट को कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री सुदर्शन सिंह बबलू : सभापति महोदय, हमने तीन दिन तक आर0डी0जी0 के ऊपर चर्चा की और उससे पहले राष्ट्रीय आपदा के ऊपर चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि (पंजाबी भाषा में कहा गया) इना नाल गल करना ही बेकार है और ऐं तां पानी ते मधानी पौण वाली गल है कि पानी ते मधानी पाओ और शोलिया निकलना कुछ नहीं। सभापति महोदय, इसके ऊपर हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं और जरूरी कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं और जिस तरीके से बात हुई है कि हिमाचल को कैसे ऊपर उठाना है, मैं समझता हूं कि अगर विपक्ष के लोगों ने 5 साल पहले ऐसी सोच रखी होती तो आज हिमाचल के हालात ऐसे नहीं होते।

18.03.2026/1610/डी.सी.-एन.जी./2

विपक्ष की सरकार के समय आर0डी0जी0 की पूरी ग्रांट मिली और उसके अलावा केन्द्र सरकार से अन्य सभी फंड भी मिले लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार को 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला। इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ जो पहला वादा ओ0पी0एस0 का किया था, उसे पूरा किया और हमने ओ0पी0एस0 दी। उसके ऊपर भी विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस माननीय सदन के माध्यम से कहा है कि अगर आने वाले समय में हमारी सरकार आती है तो हम देखेंगे कि ओ0पी0एस0 देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि जहां-जहां पर भी बी0जे0पी0 की सरकार आई है, वहां पर ओ0पी0एस0 बंद की गई है।...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि विपक्ष के लोग हमारे कर्मचारी/अधिकारियों के साथ द्वेष की भावना रखते हैं और जब हम हिमाचल के हितों की बात करते हैं तो (***) है।

सभापति महोदय, पूर्व सरकार के समय में इंवेस्टर मीट करके पैसा उड़ाया गया था। वर्तमान सरकार के समय में हमारी कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई है। मेरे क्षेत्र में तीन

प्लांट लगे थे लेकिन जी0एस0टी0 लगने के बाद हिमाचल प्रदेश में 60 प्रतिशत इंडस्ट्री बंद हो गई। मेरे अम्ब क्षेत्र में कामधेनू का सरिया बनता था और वह प्लांट बंद हो गया। इसके अलावा एक ल्यूमिनस का प्लांट था जोकि दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गया। उस समय प्रदेश और केंद्र, दोनों जगहों पर बी0जे0पी0 की सरकार थी लेकिन इन्होंने ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की कि इन प्लांट्स को कैसे बचाया जाए या पुनः चालू किया जाए। नए प्लांट लाना तो दूर की बात है लेकिन जो चल रहे थे वे भी इंवेस्टर मीट के बाद बंद हो गए।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से मुख्य मंत्री जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वे सही नहीं है। यूथ कांग्रेस के लड़कों ने दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करना कोई अपराध नहीं है। इनकी पार्टी के श्री अनिल विज जोकि हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वे तो यू0पी0ए0 की सरकार के समय में (***)।

18.03.2026/1610/डी.सी.-एन.जी./3

विपक्ष के लोग प्रोटेस्ट करने को भी जुर्म मानते हैं। विपक्ष के लोगों की सी0आई0डी0 बड़ी जबरदस्त है और इन्होंने रोहड़ू के अंदर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों को ढूंढ लिया। इन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाने वालों को तो ढूंढ लिया लेकिन बहुत दुःख की बात है कि पुलवामा व पहलगाम में अटैक करने वाले, जिन्होंने हमारे सैनिकों और पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, इन हमलों के दोषियों का आज तक पता नहीं लगाया जा सका। मैं समझता हूं कि अगर कोई केन्द्र सरकार पर सवाल उठाता है तो उसे आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जाती है लेकिन देश में जो असली आतंकवादी हैं, उनको पकड़ने में केन्द्र सरकार नाकामी रहती है।

सभापति महोदय, विपक्ष के लोग कहते हैं कि हमारी सरकार ने 1500/- रुपये नहीं दिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के तीन वर्षो में कहीं-न-कहीं 1500/- रुपये दिए गए हैं। जैसे ऊना में अनेक महिलाओं को 1500/- रुपये दिए गए हैं, माननीय मुख्य

मंत्री जी ने डोडरा-क्वार में भी 1500/- रुपये देने की घोषणा की है। लेकिन विपक्ष की केन्द्र सरकार जब वर्ष 2014 में सत्ता में आई थी तब 15-15 लाख रुपये देने की बात की थी और केन्द्र सरकार ने आज 15 लाख रुपये का नाम ही भुला दिया है। इसके अलावा एक बात और कहते थे कि 'बहुत हुई महंगाई की मार, अबकि बार भाजपा की सरकार'। उस समय पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की भी बहुत बातें होती थी

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.03.2026/1615/ए.पी. /एच.के. -1

श्री सुर्दशन सिंह बबलू जारी .....

उस समय पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की भी बहुत बातें होती थी और आपकी ही पार्टी की पूर्व मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी उस समय प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेजने की बात करती थी। आज वे कहां छुपी हैं। गैस को लेकर आज आम लोगों ने आप लोगों का जुलूस निकाल दिया है। आज गैस सिलेंडर की किल्लत की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि महिलाओं को लंबी कतारों में खड़ा होकर गैस सिलेंडर लेना पड़ रहा है और इससे कई महिलाओं को दिल का दौरा भी पड़ा, कई महिलाएं बेहाश तक हो गई। आज माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी जी को चूड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं। लगता है कि कंपनी ने चूड़ियां बनाना ही बंद कर दिया है या उनको प्रधानमंत्री जी का नाप नहीं मिल रहा। इन मुद्दों पर कभी सार्थक चर्चा नहीं होती। जब राज्यसभा के चुनाव हुए तो कई भाजपा नेताओं ने कहा कि अब फिर से चुनाव आ रहा है। आप कुछ तो शर्म करो राज्य सभा के चुनावों ने आपके 6 विधायकों की बली दे दी। पिछली बार आपने 6 जीते हुए प्रतिनिधियों को घर बैठा

दिया। उनकी हालत ऐसी है जैसे बरसात में डोहरू वाले आते हैं, गूगा के डोहरू बांधते हैं और चले जाते हैं। आज वे सारे प्रतिनिधि अपने-अपने घरों में डोहरू सुन रहे हैं। विपक्ष को पंचायत चुनावों की भी बहुत चिंता हो रही है। धर्मशाला में हुए सत्र में विपक्ष ने केवल यही मुद्दा उठाया कि पंचायत चुनाव कब होंगे। विपक्ष को चुनावों का बड़ा शौक है। लेकिन अगर पिछले 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखें तो विपक्ष जीत ही नहीं पाया। जब उनकी सरकार थी तब भी उपचुनाव हुए और हम चारों सीटें जीते। वर्ष 2022 में चुनाव हुए और हम 40 सीटें जीतकर सत्ता में आए। एम.सी. शिमला के चुनाव में भी हमारी पार्टी एकतरफा जीती। एक-एक घर में चार-चार विधायक बैठा दिए। विपक्ष ने पूरी कोशिश की लेकिन हार गया। हमारी सरकार गिराने की कोशिश भी हुई, 9 विधायक चले गए और 6 विधायकों को घर बैठा दिया गया लेकिन वहां भी विपक्ष हार गया। अब विपक्ष पंचायत चुनावों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए हम आपको वहां भी हराएंगे। वर्ष 2027 में भी हम उन्हें दिखा देंगे कि हम क्या हैं। ...(व्यवधान)

18.03.2026/1615/ए.पी. /एच.के. -2

Chairman : Please don't disturb. ...(Interruption). Hon'ble Member please wind-up.

श्री सुर्दशन सिंह बबलू : सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने सार्थक काम किया है। पहले हम 22वें स्थान पर थे। विपक्ष ने कहा कि उन्होंने 900 संस्थान खोले। मेरी विधान सभा में स्वर्गीय राजा वीरभद्र जी के समय दो कॉलेज खोले गए, एक चौकी मनियार और दूसरा चिंतपूर्णी में। चिंतपूर्णी कॉलेज ऊना जिले में आता है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में जस्वां प्रागपुर में दर्ज है। आपकी सरकार में उस समय जस्वां प्रागपुर से मंत्री थे और उन्होंने कॉलेज के निर्माण पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया। आज उस कॉलेज की हालत यह है कि उसकी बिल्डिंग गिरने वाली है और बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे। चौकी मनियार कॉलेज हमारी सरकार के समय खुला। भाजपा सरकार आने के बाद वह स्कूल के दो कमरों में चल रहा था। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से बात की और उन्होंने कॉलेज का काम शुरू करवाया। इसके लिए 13 करोड़ रुपये दिए गए और चार मंज़िलें बनाई गईं। इसके लिए मैं माननीय शिक्ष मंत्री माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद

करता हूं। जल्द ही वह कॉलेज तैयार हो जाएगा। अगर मैं अम्ब अस्पताल की बात करूं तो यह अस्पताल मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। जब मैं विधायक बना, मैंने रोगी कल्याण समिति की बैठक की। वहां के बी0एम0ओ0 ने बताया कि तीन वर्षों से बैठक हुई ही नहीं थी। उस अस्पताल में चार डॉक्टर थे। वहां एक अल्ट्रासाउंड मशीन पड़ी थी लेकिन उससे केवल एक ही अल्ट्रासाउंड हुआ था वह भी स्थानीय विधायक का। मशीन बंद पड़ी थी। हमने डॉक्टर का प्रबंध किया और मशीन को ठीक करवाकर 350 महिलाओं का मुफ्त टेस्ट किया। बाद में मशीन फिर खराब हुई और बी0एम0ओ0 ने बताया कि इसे ठीक करने के लिए 5 लाख रुपये लगेंगे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1620/AT/HK/01

श्री सुदर्शन सिंह बबलू जारी...

हम नई मशीन लेंगे। हमने चिंतपूर्णी और अम्ब के लिए नई मशीनें लीं। पहले हमारी महिलाएं टेस्ट करवाने के लिए नंगल और होशियारपुर जाती थीं, लेकिन आज उनके टेस्ट अम्ब अस्पताल में मुफ्त हो रहे हैं। वहां पहले केवल चार डॉक्टर थे। हमने पता किया तो मालूम हुआ कि स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है। हमने स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करवाई। उसके बाद बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत थी तो उनकी भी नियुक्ति की। फिर हमने डॉक्टर स्केटरी की नियुक्ति की उसके बाद एनेस्थीसिया डॉक्टर की नियुक्ति की, और फिर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की। अभी हाल ही में हमने जनरल सर्जन की भी नियुक्ति की है। और बहुत जल्द ही हम ऑरथो के डॉक्टर की भी नियुक्ति भी करने वाले हैं। और वहां ऑपरेशन थियेटर चालू करने के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहां नई ओपीडी के लिए 3.5 करोड़ रुपये दिए हैं। हम वहां नई ओ0पी0डी0 बनाने जा रहे हैं। हमारी सरकार एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम को लेकर बहुत गंभीर है। जब हमारी सरकार वर्ष 2022 में बनी, तब हिमाचल प्रदेश का एजुकेशन सिस्टम 22वें स्थान पर था, और आज हम 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री मंत्री और शिक्षा मंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों

का धन्यवाद करता हूं। आज विपक्ष के लोग धर्म की बात करते हैं। कई बार हमें और मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं कि आप वहां नहाकर नहीं आए कि आप वहां पर नहाकर चले गए। विपक्ष के सदस्य ऐसी बातें करते हैं। हमें लोगों ने यहां इस बात के लिए नहीं भेजा है कि कहां नहाना है और कहां नहीं। हमारे मुद्दे कुछ और हैं। भगवान को मानना हमें आता है। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी का उदाहरण देना चाहूंगा वे हर महीने दो बार चिंतपूर्णी माता जी के दर्शन करने और वहां की व्यवस्था को देखने जाते हैं। माननीय उप-मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ रुपये की एक योजना, जो लंबे समय से लंबित थी, उसे शुरू किया और उसका उद्घाटन भी किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस योजना के तहत आइ0पी0एच0 की स्कीम चलाई गई और माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई। मैं माननीय उप-मुख्यमंत्री जी

18.03.2026/1620/AT/HK /02

का धन्यवाद करता हूं कि उनके साथ मेरी रोज चर्चा होती है और हम माता मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए काम कर रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी और उप-मुख्यमंत्री जी ने 130 करोड़ रुपये की पहली किस्त हमें दी है, जिससे माता चिंतपूर्णी जी के लिए सुंदर भवन बनाया जाएगा। इन नवरात्रों में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से नींव रखने जा रहे हैं और एक साल के अंदर हम इसे पूरा करने का लक्ष्य है। हम जगन्नाथ पुरी, तिरुपति नाथ और वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर एक सुंदर भवन बनाने जा रहे हैं। मैं अपनी सरकार का इसलिए धन्यवाद करना चाहूंगा। ये लोग कहते हैं कि हमें केंद्र से 55 करोड़ रुपये प्रसाद योजना से मिले। लेकिन सच यह है कि हमने वह पैसा कोर्ट में जाकर हासिल किया। इन्होंने मना कर दिया था कि हमें प्रसाद योजना का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन हमने हाईकोर्ट में केस जीता और उसके बाद वह पैसा हमे मिला। आज वह पैसे को भी हम माता के भवन में लगाने जा रहे हैं। पहले चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप-मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई थी। हमारा लक्ष्य है कि हम लगभग 500 करोड़ रुपये उस मंदिर में खर्च करने जा रहे हैं। लाखों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए यह जरूरी है। मैं मानता हूं कि यह हमारी

सरकार की सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है।

आज माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आपको श्राप लगेगा और भगवान भी आपकी सरकार को नहीं बचा पाएगा। लेकिन अगर आपको भगवान पर इतनी आस्था है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यहां श्राप नहीं लगेगा, इनको तो आशीर्वाद मिल रहा है और भगवान शिव का भी और माता चिंतपूर्णी जी का भी आर्शीवाद माननीय मुख्य मंत्री जी को मिल रहा है। और मैं यह समझता हूं कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, हिमाचल को आगे लेकर जाने की बात कर रहे हैं। चाहे आर0डी0जी0 मिले या न मिले, हमारी कैबिनेट ने भी यह मंजूर कर दिया है कि हम ओ0पी0एस0 बंद नहीं करेंगे। हम हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे हम और धन अर्जित करके हम अपने पैरों पे खड़े होने की ओर आगे बड़ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी पूरे देश में एक योद्धा मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। वे हिमाचल के लोगों के लिए

18.03.2026/1620/AT/HK /03

लगातार लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने हमें भी निर्देश दिए हैं कि हम हिमाचल के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि –

आंधियों से तूफानों से लड़ करके आए हुए हैं और इस सिंहासन पर बैठे हुए हैं, आंधियों से और तूफानों से लड़ करके आए हैं और इस सिंहासन पर बैठे हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। आपकी छोटी सी फूंक से बुझ जाए, ऐसा दीया नहीं है वो)

अंत में, मैं यह बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग हमेशा सरकार को गिराने ओर बुराई करने में लगे रहते हैं और सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपका बनता भी है क्योंकि आप पांच गुटों में बंटे हैं

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1625/केएस/वाईके/1

श्री सुदर्शन सिंह (बबलू) जारी ---

कौन ऊपर जाएगा, कौन नीचे जाएगा, ये चीजें तो आपको दिखानी ही पड़ेंगी परंतु ये चीजें हमारे प्रदेश के हित में नहीं हैं। हमें यहां पर लोगों ने प्रदेश के हित के लिए चुनकर भेजा है। हमारे विधान सभा के लोगों ने हमें यहां इसलिए भेजा है ताकि हम यहां पर अपने क्षेत्र के बारे में सार्थक चर्चा करें। सभापति महोदय, जिस तरीके से हैल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में हमारी सरकार कार्य कर रही है, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मुझे तो अभी काफी कुछ कहना था लेकिन वह मैं बजट पर चर्चा के दौरान बोलूंगा क्योंकि आपने दो बार घंटी बजा दी है और समय भी 22 मिनट हो गए हैं अतः मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय माता चिन्तपूरनी।

18.03.2026/1625/केएस/वाईके/2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल भाग लेंगे।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का जो 16 फरवरी, 2026 को अभिभाषण हुआ, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। जहां तक इसको सपोर्ट करने, अनुमोदन करने या इसके पक्ष में बोलने की बात है, मैं इस अभिभाषण का ज़रा भी समर्थन नहीं कर पाऊंगा। मैं पक्ष या विपक्ष से भी हटकर कुछेक बुनियादी प्वाइंट्स पर बात करुंगा। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत कुछ हो गया, एक छोटा सा क्लू बता दूं कि अगर आपके चुनाव क्षेत्र में कोई ज्यादा कार्य हुए हैं तो यह याद रखना कि वे विपक्ष में बैठे हुए हम 28 लोगों की कॉस्ट पर हुए क्योंकि हमारे चुनाव क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। यह एक तथ्य है और मैंने डिफरेंट फोरम्ज़ पर जहां-जहां बात हुई, वहां तथ्यों सहित इसको स्पष्ट भी किया है। बजट पॉलिसी और प्रोग्राम्ज़ को इंडिगेट करता है और गवर्नर एड्रेस सरकार के कार्यकलाप को, पॉलिसी प्रोग्राम्ज़ की जो उपलब्धियां होती हैं, निष्कर्ष होता है या एक साल के अंतराल के बाद जिस स्थिति में हम पहुंचे होते हैं, उसके ऊपर एक रूपरेखा

तैयार करके विधान सभा सदन में प्रस्तुत की जाती है। यह आपका दायित्व है कि आप सच-झूठ करके उसके पक्ष में बोलेंगे और हमारा भी दायित्व है कि उसमें जितनी भी खामियां, व्यवस्था-अव्यवस्था कुछ भी नज़र आए तो उसको हाईलाइट करें और आम जनमानस तक तथ्यों के साथ उन्हें पहुंचाएं। आपका घोषणापत्र गारंटियों से शुरू हुआ था। घोषणापत्र को ज्यादातर एक पॉलिसी डाक्यूमैंट माना जाता है। आपने भी माना और उसके ऊपर काम करने का संकल्प लिया परंतु आज चौथा बजट पेश होने जा रहा है और चौथा गवर्नर एड्रेस प्रस्तुत हो गया है। 3 साल पूरे हो गए हैं और मात्र एक वर्ष ही रहा है जो कार्य करने का होगा बाकी जो वर्ष 2027 का समय होगा वह ना आपके पास और ना ही हमारे पास होगा, वह जनता का होता है और जनता के बीच में जा कर हमें अपने-अपने पॉलिसी प्रोग्राम्ज़ की जो उपलब्धियां हैं या जो हमें दायित्व मिला था, वह अपोजीशन के नाते या रूलिंग पार्टी के नाते आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। आपने 1500 रुपये की बात की थी, ओ0पी0एस0 की बात की थी, 5 लाख नौकरियां देने की बात की थी, 300 युनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, 100 रुपये या 80 रुपये किलो दूध खरीदने की बात की थी, 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात की थी। ये आम जन-मानस से जुड़े मुद्दे थे। धरातल पर जो कृषि फार्म सेक्टर है, जो गांव से जुड़े लोग हैं, लगभग 74 लाख में से 53-54 लाख लोग यानी लगभग 57 प्रतिशत लोग फार्म सेक्टर पर निर्भर करते हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.03.2026/1630/av/yk/1

श्री जीत राम कटवाल------जारी

मैंने सदन में इस बारे में पहले भी कहा है कि प्रदेश की जनसंख्या व इस व्यवस्था को चलाने में उनका बहुत योगदान रहता है। आपने यह बात पकड़कर लुभावने वायदे भी कर दिए थे। परंतु मात्र ओ0पी0एस0 को छोड़कर आपने आज दिन तक अपना कोई भी वायदा ढंग से पूरा नहीं किया है। आप ढंग तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी राजस्थान में लगी थी। वहां पर माननीय मुख्य मंत्री का बहुत बड़ा बोर्ड लगा था कि हमने यह कर दिया, वह कर दिया। मैं बहुत हैरान हुआ और लोग मुझे वहां पर उसके बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, यहां से 1700 किलोमीटर दूर है इसलिए बोर्ड

लगा सकते हैं। परंतु प्रदर्शन का जो वाज़िब तरीका है उसको न रूलिंग पार्टी को भूलना चाहिए और न ही हम भूलते हैं।

मैं यहां पर गारंटीज की बात करूंगा। भारत सरकार भी एक सिस्टम में सांझी होती है। पीछे तीन दिन आपने आर0डी0जी0 पर चर्चा की जिसमें बहुत बहुमूल्य विचार आए। कई विचार आक्रोशित थे परंतु कुछ अच्छे सुझाव भी आए और इस सदन की नोलेज डैफिनेटली बड़ी है। केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम फ्री राशन देती है। इसके अतिरिक्त 11 करोड़ लोगों को 'उज्ज्वला गैस' स्कीम के अंतर्गत गैस कनैक्शन दिए। 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत 23 करोड़ लोगों को शौचालय दिए तथा 5 करोड़ लोगों को घर व 50 करोड़ लोगों को 'आयुष्मान भारत' दिया। 'वन रैंक, वन पेंशन' दी, साथ ही 10 करोड़ परिवारों को 'किसान सम्मान निधि' जिसकी 22वीं किस्त अभी 6 दिन पहले ही जारी की गई है। ये सारी गारंटीज पूरी हुईं और धरातल पर दिखती भी हैं। लेकिन आप जो किन्तु-परन्तु वाली बातें करते हैं, इसके बारे में आपको खुद समझना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से भी पूछना चाहिए। मैं इसके ऊपर आंकड़े देकर बात करूंगा। आपका जो डवलपमैंट मोडल 'व्यवस्था परिवर्तन' माइनस बजट के साथ चल रहा है। अगर बजट माइनस हो यानी आपने किसी चीज के लिए 100 रुपये रखे हैं और उसमें से केवल 35 रुपये ही खर्च हो रहे हैं तो मैं उसको बजट नहीं कहूंगा। वह कोई बजट नहीं होता, आपको समझना चाहिए कि एक रेड़ी वाला भी अपना बजट

18.03.2026/1630/av/yk/2

ध्यान में रखकर अपनी व्यवस्था चलाता है। वह चाहे 200 रुपये, 400 रुपये या 500 रुपये कमाये। मैं कुछ आंकड़े दूंगा और आप खुद फैसला कर लेना कि क्या आप सही हैं? यहां पर केवल बोलने से कुछ नहीं होता कि हमने यह कर दिया या वह कर दिया।

यहां पर माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार बोल रहे थे जिन्होंने इस प्रस्ताव को मूव किया। ये बोल रहे थे कि इंटलैक्चूअल, किसान और युवा बड़े खुश हैं। अरे! खुशी का कोई पैमाना तो बताइए, आपने खुशी वाला कोई काम किया है तो बताइए? यहां पर सुदर्शन सिंह बबलू

जी बोल रहे थे कि यह कार्य भी हुआ, वह भी हुआ लेकिन आप यह क्यों नहीं बताते कि आपने 1100 संस्थान एक ही झटके में बंद कर दिए थे।

प्लानिंग की बैठक में मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे थे कि मैं बरंठी गया था परंतु आप वहां नहीं आए। मैंने कहा कि बुलाने का एक तरीका होता है। आप प्रवास कार्यक्रम विधायक को दें तो मैं नहीं आता, आप मेरे जितने मर्जी परिचित या माननीय हों। उन्होंने कहा कि मैंने वहां तहसील दे दी। मैंने कहा कि आप वह भी गिना दीजिए जो आपने वहां पर 16 चीजें बंद की हैं। वे चीजें दोबारा से वहीं-की-वहीं दे दीं और मुझे लगता है कि वे अब खुलेंगी भी नहीं। आज जवाब आया है परंतु मैंने थोड़ी व्यस्तता के कारण वह अभी पढ़ा नहीं है। तलाई की सब-तहसील के लिए पहले बोला गया था कि यह खुलनी नहीं चाहिए थी। अब उन्होंने बोला की मैंने खोल दी है। मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी, आपने खोली नहीं अपितु रिस्टोर की है जिसके लिए मैं और मेरी जनता आपसे शुरू से अनुरोध कर रही थी। आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। मेरे वहां कुछ दिन

टी सी द्वारा जारी

18.03.2026/1635/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री जीत राम कटवाल.... जारी

पहले एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मैं शिमला से जा रहा था और 5.50 बजे मुझे मैसेज आया जबकि यह घटना 4.30 बजे की थी। मैंने 5.50 बजे ही एस0पी0 को टेलीफोन किया। उसके बाद भी वहां 7.00 बजे तक केवल 4 पुलिस के कर्मी पहुंचे और एस0एच0ओ0 महोदय 8.00 बजे पहुंचे। डी0एस0पी0 8.30 बजे पहुंचे और एस0पी0 स्वयं 8.45 बजे मौके पर पहुंचे।

यह बात सही है कि कानून अपना कोर्स लेता है लेकिन भगदड़ और कानून-व्यवस्था को संभालने की जरूरत थी। मेरे पार्टी के मण्डल अध्यक्ष ने अपने स्तर पर स्थिति संभाली।

लेकिन आपके नेता, जो एक विशेष समुदाय से संबंधित व्यक्ति था और इस मामले में इन्वॉल्व था, उसके पक्ष में खड़े नजर आए और दूसरे दिन डिप्टी कमिश्नर महोदय के साथ बैठक कर रहे थे कि इनके धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जबकि जिस परिवार के साथ यह घटना घटी उनको उनके साथ खड़े होना चाहिए था। जब भाई-भाई में झगड़ा होता है तो कानून की स्थिति वहां भी खराब होती है। It is not a question of minority or one section of society or another. अगर परिवार में भी झगड़ा हो तब भी कोई-न-कोई कानून-व्यवस्था होती है। लेकिन वे उनके साथ खड़े होकर मीटिंग कर रहे थे। मैं उस क्षेत्र का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। एक विधायक होने के नाते मुझे जानकारी भी है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर महोदय ने मुझे नहीं कहा कि आप भी कुछ बताइए। यह है आपका प्रशासन, यह है आपका व्यवस्था परिवर्तन। कुछ लोगों के साथ खड़े होकर व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता। इससे आप कानून का दुरुपयोग ही नहीं करते बल्कि बहुत बड़ा गलत संदेश भी देते है।

अब मैं दूसरा विषय रखना चाहता हूं। (कुछ कागजात दिखाते हुए) यह जंगलों की कटाई का मामला है। हमारे क्षेत्र में जो 10 वर्ष का फेलिंग सर्किल था, उसे भी हमारे क्षेत्र में बंद कर दिया गया। अब जंगल नहीं कटेगा क्योंकि जो आपके अपने ठेकेदार थे यानी आपके जो अपने करीबी थे, उनको लोगों ने दरख्त काटने के लिए नहीं दिए होंगे और इसका कारण आदमी का व्यवहार होता है।

18.03.2026/1635/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

एक गरीब किसान 5, 6, 10 वर्ष तक इंतजार करता है, अपने बच्चे की शादी, पढ़ाई या मकान निर्माण के लिए या अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वह फेलिंग सर्किल का इंतजार करता है। लेकिन आपने वह 10 साल का फेलिंग सर्किल भी सुपरसीड कर दिया। यह है आपकी कानून-व्यवस्था और व्यवस्था परिवर्तन, इसको भी देखना चाहिए। मैंने इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री को भी लिखा है। यह गंभीर विषय है। आप चाहे विधायक या कोई भी व्यक्ति हों, लेकिन आम जनमानस के साथ इस प्रकार के दुराग्रह से काम करना किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता।

इसके साथ ही बड़ी-बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। सरकार आने पर कहा गया कि वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर प्रदेश होगा और वर्ष 2032 तक उत्कृष्ट राज्य बनेगा। इसमें कहीं भी आर0डी0जी0 का हवाला नहीं था। पहले 14वें वित्तायोग में अनुच्छेद 280 के तहत 13 राज्य आर0डी0जी0 के अंतर्गत थे और भी टैक्स का डेवोल्यूशन होता है। 15वें वित्तायोग में 17 राज्य इसमें शामिल किए गए। यह केंद्र सरकार का नीतिगत फैसला है। आर0डी0जी0 सभी राज्य की बंद हुई है। आप कहते हैं कि हम यहां नहीं चले, वहां नहीं चले लेकिन क्या आपने कभी केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया। आपको 5000-6000 करोड़ रुपये मिले, आप उसका भी जिक्र नहीं करते। अगर आप पार्टी लाइन पर इतने कठोर और निष्ठुर रहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री आपको प्रधानमंत्री नहीं लगते या केन्द्र सरकार आपको अपनी सरकार नहीं लगती तो इस तरह से नहीं चलेगा। आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और संविधान लेकर घूमते हैं लेकिन सबसे बड़ा उल्लंघन आपने पंचायत चुनावों को डेफर करके किया है और लोगों को बार-बार परेशान किया गया। कोई बता रहे हैं कि आज यह पंचायत बन रही है कल कोई दूसरी पंचायत बन रही है। आप जिस मर्जी को पंचायत बनाओ। हमने भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी ने हमें चिट्ठी लिखी थी, हमने भी केसिज भेजे थे।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

18-3-2026/1640/NS-AG/1

श्री जीत राम कटवाल----जारी

माननीय अनिरूद्ध जी ने लिखा था कि आप माननीय विधायकों के माध्यम से प्रस्तावनाएं दें। हमने भी दे दी। हमने कोई अपने आप नहीं बनाई। हमें जो जनता ने दिया हमने भी उसको ही दिया है। आप एक बात याद रखें कि जो जनता पंचायत स्तर पर होती है वह एक जैसा व्यवहार करती है। वह पार्टीबाजी में नहीं जाती है। लोकल सेल्फ गवर्नमैंट का व्यवहार पार्टी लाइन से ऊपर उठकर चलता है। उसमें थोड़ा-बहुत क्षेत्रवाद चलता है तो वे पंचायतें आप अभी बना रहे हैं। मैंने एक अधिकारी को पूछ लिया कि पंचायतों का सीमांकन

तो इलेक्शन कमीशन ने नवंबर में फ्रीज कर दिया है। तब वह अधिकारी कहता है कि कमीशन की कौन मानता है? यहां तो सब कुछ चलता है। यह चलता नहीं है, यह बजट की या आपकी सरकार की अच्छी दिशा नहीं है। यह बजट सरकार का या लोगों को आगे ले जाने का या पहले से अच्छा बनाने का रास्ता नहीं है। आपको सिस्टम का पालन करना चाहिए क्योंकि सिस्टम भी इसी हाउस में, इसी सिस्टम में और इसी विधानसभा के साथ पिछली जितनी भी विधानसभाएं बनी हुई हैं, उन सबने इसमें योगदान दिया है। आपने इसके लिए एक्ट भी बताया है कि वर्ष 1994 में शायद कांग्रेस की सरकार थी और अगर एक्ट बनाया है तो उसका पालन भी कर लेते। आप यहां पर बोलते हैं कि हमने ओ0पी0एस0 दिया है। इसके लिए आपका धन्यवाद। आप एक बात बताइए कि आपको इन चुनावों से ऐसा कौन-सा फर्क पड़ने वाला है? मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव जनता के हैं और आपका काम तो रेफरी का है। आपने सीटी बजानी और आपके सिस्टम ने काउंटिंग टोटल करनी है तथा जो अधिकारी/कर्मचारी हैं वे आज के जमाने में इसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अभी पिछले साल आपने प्रदेश में शत प्रतिशत लिटरेसी घोषित की है। आप अपने को क्यों झूठला रहे हैं कि आप चुनाव का 31 मार्च को करेंगे, 30 अप्रैल या 31 मई को करेंगे। आप कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, कभी कहां जा रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ी है? आप इलेक्शन करवा लो। कोई नहीं होता, जिसकी सरकार होती है सारे उसके साथ आ जाते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो शत प्रतिशत हमारे साथ आएंगे क्योंकि आपसे उनको थोड़े दुख व टेंशन का माहौल बना हुआ है। आपको ये बातें भी देखनी चाहिए। ऐसा कोई इस तरह का व्यवहार आपके इस गवर्नर अभिभाषण में नहीं लगता और न ही इस तरह की कोई रूपरेखा लगती है। प्रदेश की खुशहाली का क्या

18-3-2026/1640/NS-AG/2

आधार होता है? उसका आधार इन्कम होता है। 'भूखे पेट भजन भयो ना गोपाला।' आपकी जो सामर्थ्य है तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस स्टेट के सामर्थ्य के लिए एनर्जी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर अच्छे तरीके थे। मैं आपको इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूं कि सरकार की जो पर्सनल पॉलिसी होती है, वह बहुत जरूरी होती है। आप ठीक जगह, ठीक आदमी लगाइए ताकि वह आपकी भाषा को समझे और आपको

आक्रोशित होकर न बोलना पड़े, गुस्से में न बोलना पड़े और आपको चीख कर नहीं बोलना पड़े। आज जिस तरीके से माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने बोला कि officers with doubtful integrity. उस गांव वालों ने उसको निकालने का आदेश दिया और आपने उसको दूसरी बार एक्सटेंशन दे दी। चलो आपने एक्सटेंशन दे दी, यह आपकी खुशी की बात है और सरकार के कई बड़े प्रयोग होते हैं, कई कंसीडरेशन्ज होती हैं, कई कंबिनेशन्ज होती हैं पर उसे उस गांव में न लगाएं जहां उसका विरोध किया। यह आपने कौन-सा व्यवस्था परिवर्तन कर लिया? वह पूरा गांव आपके खिलाफ हो गया और वह आपके 4 से 6 गांव और खराब करेगा। वे ये मानेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको डस्टबिन में नहीं डाला बल्कि ठुड मार के बाहर फेंका है। वक्त आने पर हम भी ठुड का प्रयोग करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है। चिढ़ाने के लिए ऐसे काम भी नहीं करने चाहिए। यह व्यवस्था परिवर्तन भी कुछ जचता नहीं है।

मैंने जैसे पर्सनल पॉलिसी के बारे में कहा कि चीफ सेक्रेटरी हैं और ऑफिशिएटिंग हैं, डी0जी0 आफफिशिएटिंग हैं। आप उनको रेग्युलर कर दो। जिस किसी को भी बनाओ, सरकार अत्यंत पावरफुल होती है, बड़ी शक्तिमान होती है, शक्तिशाली होती है और गाड़ियों में झंडे लगे होते हैं, रेस्ट हाउस जाते हैं तो सैल्यूट करते हैं लेकिन जनता को पता है कि यह सरकार है। लेकिन आपके तो मुख्य सचिव और डी0जी0

आर0के0एस0 द्वारा----जारी

18.03.2026/1645/RKS/AS-1

श्री जीत राम कटवाल जारी....

जैसे महत्वपूण पद भी officiating चल रहे हैं। ऐसे में उच्च पदों पर adhoc व्यवस्था अच्छे प्रशासन की निशानी नहीं मानी जाती। आपने जो OPS के संबंध में निर्णय लिया है इसका हम स्वागत करते हैं लेकिन कर्मचारियों को समय पर वेतन भी दिया जाना चाहिए। वर्तमान

स्थिति यह है कि कर्मचारियों को वेतन व DA नहीं मिल रहा है। आप लाइबिलिटीज की बात करते हैं परंतु management should be pro-public. जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। अब यह भी चर्चा है कि APL वर्ग से 100 रुपये वाटर सैस लिया जाएगा जबकि BPL वर्ग के लिए 25 रुपये की बात कही जा रही है। लेकिन अभी तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई है क्योंकि कई बार सोशल मीडिया में झूठ भी चलता है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी मुंह हिला रहे हैं। सरकार के ऊपर कर्मचारी, आम जनता, किसान और यहां तक कि जंगली जानवर भी आश्रित हैं। जंगली जानवर इस धरती पर रहने वाले जीव हैं उनका भी यहां कुछ हिस्सा होता है। इसलिए इन सबके लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि उन्हें शांतिप्रिय तरीके से अपना-अपना हिस्सा मिल जाए। राज्य की पहचान उसकी कानून-व्यवस्था से होती है। State is known by the status of law. राज्य कानून व्यवस्था को मेंटेन करता है इसलिए सबके साथ बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए। हम लोग विपक्ष में है और आप हमारे साथ भेदभाव करते रहते हैं। हमारी NABARD की किसी भी योजना का लाभ हमारे क्षेत्र को नहीं मिला है। आप कह रहे थे कि इस कार्यकाल में बहुत से काम हुए हैं। मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी इस विषय को उठाया था। मैंने जो नौ पुल बनाए हैं उनमें से चार पुलों पर डंगे तक नहीं लगे हैं। उनकी अप्रोचिज तक नहीं बनी हैं। जब हम इसके लिए बजट मांगते हैं तो PWD में बजट शून्य बताया जाता है। SCDP के संदर्भ में जो प्रश्न लगा था उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जो लिखित जवाब दिया है उसे मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। बजट में डैश-डैश दर्शाया जा रहा है और यह भी एक व्यवस्था की ही बात है। यह प्रदेश के 74-75 लाख लोगों का हिस्सा है। हम 28 आदमी विपक्ष के हैं और आप हमसे इतना भी भेदभाव न करें। मैंने माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय से कई बार बस सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। मैंने लिखित रूप में भी दिया परंतु उस प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया गया। अब फोरलेन के साथ बागछाल पुल बन गया है इसलिए आप तलाई से बस सेवा शुरू कर दें। वहां आपकी पार्टी के कोई नेता हैं जो इस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। जो दिल्ली से मरोतल बस

18.03.2026/1645/RKS/AS-2

आती है वह AIIMS की तरफ भी जाती है। AIIMS में सुबह 8-8:30 बजे पर्ची बनती है लेकिन आप इस बस सेवा को 10 बजे चला रहे हैं। आप यह भी व्यवस्था कीजिए कि जो

आदमी इलैक्टिड नहीं है वह उद्घाटन करने के लिए सक्षम नहीं है। वह एक आम नागरिक है इसलिए आप ऐसे उद्घाटन मत करवाइए। जनता ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है और समय आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मैंने भी इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। आप इस बारे में जरूर विचार करें। यह एक अच्छे प्रशासक और प्रशासन की निशानी नहीं है। आप मेरे चुनाव क्षेत्र के बारे में मुझसे पूछ लेते तो अच्छा होता। हम कभी गलत सलाह नहीं देते हैं क्योंकि अंततः जनता ही निर्णय करती है और जनता सब जानती है। जनता मौके का इंतजार करती है इसलिए आप ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न करें कि आने वाले 10-15 वर्षों तक जनता आपकी तरफ देखे ही नहीं। आपने जिस तरह का घटनाक्रम चला रखा है वह ठीक नहीं है। ऊर्जा क्षेत्र में भी पिछले पांच वर्षों में कोई नई परियोजना नहीं आई। पहले 12.5 हजार मेगावाट की बिजली क्षमता विकसित हुई थी। आपने कांगड़ा को tourism hub बनाने की बात कही है। मेरा सुझाव था कि प्रत्येक जिले को tourism hub बनाया जाए और इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। केवल बिल्डिंग्स खड़ी करके विकास नहीं हो सकता बल्कि इन भवनों को ऐसे तरीके से चलाएं ताकि इनसे लोगों को आय के साधन उत्पन्न हो। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में जो आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 90:10 की रेशो सुनिश्चित की है उसका भी आप उचित उपयोग करें। पूर्व में जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो उस समय यह रेशो 70:30 थी। उन्होंने हमारा विशेष राज्य का दर्जा भी छिन्ना था। अभी बजट के लगभग 28-29 हजार करोड़ रुपये वेतन और पेंशन में जा रहे हैं। 16-18 हजार करोड़ रुपये इंटरस्ट सर्विस और प्रिंसिपल लोन में वापिस जाएंगे। डवलपमेंट के लिए कमिटिड एक्सपेंडिचर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और खादों की सब्सिडी आदि पर भी 4—5 हजार करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं। ऐसे में विकास कार्यों के लिए बहुत कम राशि बचती है। पिछले से पिछले साल 9700 करोड़ रुपये प्लांड बजट था।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

18.03.2025/1650/बी.एस./ ए.एस.-1

श्री जीत राम कटवाल जारी...

और आपका खर्च 5140 करोड़ रुपये है।

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : और अब आपने 7640 करोड़ रुपये रखा है और आपका खर्च 4 हजार करोड़ रुपये आएगा। इसलिए आपकी डेवलपमेंट माइनेस में चल रही है। कृपया, आप इसे देखिए, यह बहुत गलत तरीके से चल रही है और जैसे आपने लिखा है कि हम हाइड्रो पावर पर कार्य कर रहे हैं। क्या आपने कभी हाइड्रो टारगेट देखे हैं? या कभी आपने इस गवर्नर एड्रेस में वे टारगेट दिए हैं कि हमने ये-ये अचीवमेंट की है? या हम ये-ये कार्य कर रहे हैं? यह रिटेलर शॉप, फुटकर की दुकान की तरह एड्रेस है। हम इसको नहीं मानते कि यह एड्रेस है, worth governor address ये किसी भी अधिकारी द्वारा या किसी भी सिस्टम में बना, it is not worth to that level. आपके जो टारगेट पीछे हैं उनका cumulative figure दीजिए कि आपने क्या-क्या किया? जब विपक्ष के सदस्य बोलें तो वे सोच समझकर बोलें कि इन्होंने सच में कार्य किया हुआ है और वह धरातल में दिखता है। ऐसा अभी तक कुछ नहीं नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि जो आपने लोगों को गारंटियां दी हैं, आज कर्मचरियों का डी0ए0 पेंडिंग है और आप अन्य लायबिलिटीज भी बताते हैं।

इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज का एक रूल था कि जिनका कोटा 90 प्रतिशत था और जिन्होंने बिजली डिपार्टमेंट खड़ा किया। उनका 10 प्रतिशत कोटा कर दिया और 10 प्रतिशत वालों का आपने 90 प्रतिशत कर दिया। वे लोग अलग से पीड़ित हैं। आपने अपने घोषणा पत्र में सेल्समैन को बोला था कि आपको 20,000 रुपये सैलरी देंगे परंतु उसे भी बंद कर दिया गया।

सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : मैंने दो बार शून्य काल में आंबनबाड़ी अध्यापिकाओं का मुद्दा उठाया उन्हें दो सालों से कोई पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे ही चौकीदार, नंबरदार, सिलाई टीचर्ज को कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप इस भाषण में ये चीजें डालिए कि इनको भी कुछ

देना है और लायबिलिटी कितनी है? एग्रीकल्चर का योगदान 14 प्रतिशत होता है, तो उस पर भी कुछ जोर लगाइए।

आपकी ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी हैं कि कई जगह आदमी ही नहीं हैं और जो एग्रीकल्चर के आदमी है वे ड्रम बेच रहे हैं, आप उनसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम लीजिए न कि ड्रम बेचना का, ड्रम बेचने का कार्य किसी दुकानदार को दे दीजिए जो दुकान का काम करता है। कोई ड्रम बेच रहे हैं तो कोई खाद बेच रहे हैं।

सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : यह जो आपकी नेगेटिव ग्रोथ है, इस पर काबू पाएं। मैं इसके अलावा बजट भाषण में बोलूंगा। मैंने बहुत लंबा बोल दिया और जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट की बात थी, इस पर भी गौर करें। यह जो डैफिसिट चल रहा है यह कोई शुभ नहीं है। यह सरकार का ही काम नहीं, पूरी स्टेट का काम है और हर एक व्यक्ति का काम है। इसको भी देखिए कि यह किस तरीके से इतना घाटा, बेकाबू घाटा चल रहा है। उसके ऊपर आपकी इकोनामिक हेल्थ जो है वह चरमराई हुई है और यह बहुत ज्यादा चरमराई है। उसको संभालने का काम करें। आपके एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनर्जी पावर में क्या कार्य हो रहे हैं? आपका सोलर एनर्जी का 600 मेगावाट का टारगेट था यह 75 मेगावाट नहीं हुआ। अभी तक पेखुबेला में 32 मेगावाट का कार्य हुआ और वह भी पानी में डूब गया।

सभापतिः माननीय सदस्य, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जीत राम कटवाल : सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। परंतु मैं इस अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकता, शुक्रिया।

सभापति : उप मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

18.03.2025/1650/बी.एस./ ए.एस.-3

उप मुख्य मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य कटवाल जी ने यहां पर पानी में टैक्स लगाने की बात की है। मैं हाउस को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने आग्रह किया है कि पानी का मिनिमम चार्ज किया जाए और पूरे देश को कहा है कि आप 100 रुपये हर परिवार से लीजिए और 25 रुपये बी0पी0एल0 से लीजिए। हिमाचल प्रदेश ने इसको लागू नहीं किया है, लेकिन यह रिक्वायरमेंट जल जीवन मिशन की है और वहां से बार-बार रिमाइंडर आ रहे हैं।

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी भगा लेंगे। कृपया, समय का ध्यान रखें।

श्री किशोरी लाल : सभापति महोदय, 16 फरवरी 2026 को महामहिम राज्यपाल जी ने इस सदन में संबोधन किया और उस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, साढ़े तीन साल पहले प्रदेश में चुनाव हुए। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देकर प्रदेश में सरकार बनाई। जैसे मुख्य मंत्री जी ने सरकार संभाली, 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज और 11,000 करोड़ की देनदारियां पिछली सरकार छोड़कर गई। उसके बाद वर्ष 2023 में प्रदेश में भारी तबाही हुई, आपदा आई।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.03.2026/1655/DT/DC-1

श्री किशोरी लाल जारी...

भारी तबाही हुई, आपदा आई, प्रदेश में 500 के लगभग जाने गई। कई घर बरबाद हुए, सड़कों को भारी नुकसान हुआ। बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली के स्कीम्ज, पानी की स्कीम्ज को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इस प्रदेश में पहले आपदा से प्रभावित लोगों को जहां एक लाख रुपये का मुआवजा मिलता था प्रदेश सरकार ने श्री सुखविन्द्र सिंह

सुक्खू के नेतृत्व में फैसला लिया कि इस मुआवजे को बढ़ा कर सात लाख रुपये किया जाये। जिन लोगों के घर टूट गये थे उन लोगों को सात-सात लाख रुपया मुआवजे के रूप में दिया गया। 4500 करोड़ रुपये का पैकेज प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों को दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस प्राकृतिक आपदा का सिलसिला लगातार जारी रहा। वर्ष 2024 में प्रदेश में कम आपदा आई लेकिन वर्ष 2025 में फिर से भारी आपदा प्रदेश में आई और प्रदेश में भारी तबाही हुई। प्रदेश सरकार द्वारा फिर से प्रभावित परिवारों की मदद की गई और मैनुअल डिजास्टर एक्ट में इस राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया गया। जिन लोगों के घर आपदा में टूट गये थे या बह गये थे उनके लिए फिर से घर बनाए गये और उन घरों में उन्होंने रहना शुरू किया। जो लोग किराये के मकान में रहते थे सरकार के द्वारा उनको किराया मुहैया करवाया गया। प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से जूझती रही। लेकिन प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री, उप-मुख्य मंत्री व मंत्री भी फील्ड में उतरे और प्रभावित लोगों की मदद करने पहुंचे। प्रदेश को फिर से पटरी पर लाया गया। प्रदेश के जिन विधान सभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ वहां के विधायक लगातार उस आपदा से निपटने में लगे रहे। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी आपदा आई। छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल के क्षेत्र में अनाज की कमी हुई। लोगों को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए मुझे भी पैदल बरोट से छोटा भंगाल के एक क्षेत्र तक जाना पड़ा। जहां पर भेड़-पालकों के डेरे थे उस जगह का नाम प्लाचक है, यह क्षेत्र बड़ा गांव से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं पैदल इस क्षेत्र में पहुंचा और मैने वहां जाकर लोगों के लिए राशन का इंतजाम किया और बड़ा भंगाल में राशन पहुंचाया। सरकार की मेहनत से यह सब संभव हुआ। जिस-जिस जगह पर लोगों का नुकसान हुआ था उनके नुकसान की भरपाई सरकार के द्वारा की गई। कांगड़ा जिले के इंदौरा के मंड क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ। किसानों के घर टूट गये और फसले बह गई। किसानों को टेंटों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां पर जो जन-सेवक थे, महिला मंडल के सदस्य थे, उन्हें मैं इस सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने भी आपदा के समय सराहनीय कार्य किया।

18.03.2026/1655/DT/DC-2

बैजनाथ का तारापूरी महिला मंडल है उन्होंने जीप भर कर अनाज, कपड़े, तेल व अन्य खाद्य सामग्री आपदा प्रभावित क्षेत्र में भेजी। उनके द्वारा भेजा गया सामान भी प्रभावित

लोगों तक पहुंचा जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। ये सब कार्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपदा के समय किये गये। इसके लिए मैं सरकार को और विशेषकर मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं। बार-बार यह बात कहना कि वर्तमान सरकार द्वारा बहुत अधिक कर्ज ले लिया गया यह गलत बात है। 48000 करोड़ रुपये का कर्ज वर्ष 2017 में कांग्रेस सरकार के द्वारा छोड़ा गया था इस कर्ज को 75000 करोड़ रुपये तक पूर्व सरकार द्वारा पहुंचाया गया। इससे यह अंदाजा हम लगा सकते है कि पूर्व सरकार द्वारा कितना कर्ज लिया गया। पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मौजुदा सरकार प्रदेश के लोगों की सरकार है और यह सरकार लगातार प्रदेश के लोगों के हित में काम करती आ रही है। जब मैं राज्यपाल महोदय का अभिभाषण सुन रहा था दो लाईनों के बाद उन्होंने कह दिया कि इस अभिभाषण को पढ़ा हुआ समझा जाए। जो अभिभाषण उनके द्वारा पढ़ा जाना था उसको पढ़ा नहीं गया।

सभापति : माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी कृपया दो मिनट के लिए आप बैठ जाएं। अभी माननीय सदस्य के अतिरिक्त पांच और सदस्य बोलने वाले हैं, अगर सदन की अनुमति हो तो सदन का समय बड़ा दिया जाए? अब इस सदन की बैठक एक घंटे तक बढ़ाई जाती है।

(**सदन की बैठक एक घंटे यानी छः बजे सायं तक बढ़ाई गई**)

श्री किशोरी लाल : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोल रहा था जो अभिभाषण उनके द्वारा पढ़ा जाना था उस पुस्तक में कुछ ऐसे अंश थे जिसे राज्यपाल महोदय ने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी..

18.03.2026/1700/डी.सी.-एन.जी./1

श्री किशोरी लाल..... जारी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक पांच वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्तायोग राज्यों को भारत की संचित निधि से राजस्व सहायता

अनुदान देने की अनुशंसा करता है। इसके अलावा वित्त आयोग स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए भी अनुदान की अनुशंसा करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत उन राज्यों को ऐसे अनुदान प्रदान करने का प्रावधान करता है, जो अपनी राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच की खाई को पाट नहीं सकते और यह हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत जरूरी था।

सभापति महोदय, 16वें वित्त आयोग का गठन दिनांक 31.12.2023 को किया गया था ताकि वह दिनांक 01.04.2026 से दिनांक 31.03.2031 तक की पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुशंसाएं कर सके। वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा यह रिपोर्ट दिनांक 01.02.2026 को संसद में रखी गई और भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई। जिस कारण हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आर0डी0जी0 बंद हो गई है। मैं कहना चाहता हूं कि केवल आर0डी0जी0 बंद नहीं हुई हैं इसके अलावा जी0एस0टी0 का कंपनसेशन भी बंद हुआ है और हिमाचल प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। इस सब के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के विकास की गति को न रुकने दिय जाए, इसके संदर्भ में प्रदेश सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

सभापति महोदय, आर0डी0जी0 की अनुशंसा सभी पूर्ववर्ती वित्त आयोगों द्वारा की गई है जोकि प्रथम वित्त आयोग (1952) से लेकर पंद्रहवें वित्त आयोग तक जारी रही परन्तु 16वें वित्त आयोग (2026-31) द्वारा इस सन्दर्भ में अपनी अनुशंसा में आर0डी0जी0 को शून्य कर दिया गया है और इससे उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र आज हिमाचल प्रदेश को अपने साधन तैयार करने होंगे।

18.03.2026/1700/डी.सी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला जी0एस0टी0 कंपनसेशन भी बंद है और इस संकट से उभरने के लिए प्रदेश सरकार को उचित कदम उठाने होंगे।

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार समाज के पिछड़े व कमज़ोर वर्गों के कल्याण तथा उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। चालू वित्तीय वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत 16,988 अतिरिक्त मामले स्वीकृत करके कुल 8 लाख 41 हजार 917 व्यक्तियों को लगभग 1,060/- करोड़ रुपये की राशि पेंशन हेतु व्यय की जा रही है। अनुसूचित जातियों के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 1,228 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने तथा अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रोत्साहन राशि को 50 हज़ार रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ 18 लाख रुपये की राशि व्यय कर 453 दम्पतियों को लाभान्वित किया गया है।

सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री सुख-आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 30 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जिसमें से 25 करोड़ 7 लाख 96 हज़ार रुपये की राशि 4 हजार 131 लाभार्थियों पर व्यय की गई है। 114 बच्चों को चण्डीगढ़, दिल्ली, आगरा, गोवा, अमृतसर एवं कपूरथला के शैक्षणिक भ्रमण पर भी भेजा गया। सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 183 लाभार्थियों को लगभग 93 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके अलावा मुख्य मन्त्री शगुन योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 1,118 लाभार्थियों को लगभग 3 करोड़ 47 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत 46 लाभार्थियों को 91 लाख 45 हज़ार रुपये की राशि वितरित की गई।

18.03.2026/1700/डी.सी.-एन.जी./3

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं, मक्का, कच्ची हल्दी तथा पांगी क्षेत्र की जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। जिसके तहत किसानों से 40/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मक्की, 60/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं व 90/- रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कच्ची हल्दी की खरीद की गई है।

सभापति महोदय, हिमाचल प्रदेश की सरकार हर व्यक्ति के कल्याण के लिए वचनबद्ध है तथा इसके लिए अलग-अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं। पूर्व में पांच साल जो सरकार थी उन्हें आर0डी0जी0 व जी0एस0टी0 कंपनसेशन के माध्यम से लगभग 70 हजार करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। यदि पूर्व सरकार चाहती तो प्रदेश के कर्जे को कुछ कम किया जा सकता था लेकिन पूर्व सरकार ने इस पर कोई भी फैसला नहीं किया और सारा-का-सारा पैसा योजनाओं पर खर्च कर दिया। अगर पूर्व सरकार कर्जे को कम करती

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.03.2026/1705/ए.पी. /एच.के. -1

श्री किशोरी लाल जारी .....

तो आज इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं होती। आज प्रदेश पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज़ है, यह सभी जानते हैं। प्रदेश की जनता यह भी जानती है कि वर्तमान मुख्य मंत्री प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार इस ओर अवश्य कामयाब होगी।

पिछली सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने केवल भ्रमण और हवाई यात्राएं ही कीं। पूर्व सरकार ने जनता के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, मैं उसका समर्थन करता हूं और अपना संबोधन यहीं समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा बैजनाथ, जय कांग्रेस पार्टी।

18.03.2026/1705/ए.पी. /एच.के. -2

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे श्री रणबीर सिंह निक्का जी।

श्री रणवीर सिंह : सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभापति जी, पैरा नंबर 64 में कहा गया है कि राजस्व न्यायालय के लंबित मामलों को कम करने के लिए तहसील स्तर पर हर महीने राजस्व लोक अदालतें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा। लोग तहसील कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं और तकसीमों में उलझे रहते हैं। नूरपुर विधान सभा की उप-तहसील सदवा में तहसील खुली है, लेकिन वहां पर जब बारिश और तूफान आता है तो उससे बचाव के लिए न तो काई भवन बना है और न ही किसान सम्मान निधि की जो अपडेट होती है उसकी आई0डी0 भी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। वहां पर इंतकाल और तकसीम का काम नहीं हो रहा, यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पैरा नंबर 68 में बताया गया है कि इस त्रासदी के कारण निजी सम्पत्तियों को बड़े पैमाने पर हुए नुक्सान को ध्यान में रखते हुए आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को विशेष राहत पैकेज प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में विशेष राहत पैकेज अधिसूचित किया जिसे वर्ष 2025 में भी लागू किया गया। इसमें कहा गया कि जिन घरों का पूरा नुकसान हुआ है, उन्हें 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये दिए जाएंगे। लेकिन धरातल पर ऐसा नहीं है। मेरी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिझग्राम और गांव मोगनयान में जो हमारी एस0टी0 आबादी प्रभावित हई है उन लोगों को केवल 2-2 लाख रुपये ही मिले, 7 लाख रुपये की

राशि नहीं दी गई। अगर मैं बात करू पैरा नंबर 128 में कहा गया है कि हिमाचल सरकार रेल नेटवर्क के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। लेकिन पठानकोट-जोगिंदर नगर रेल लाइन पिछले तीन वर्षों से बंद पड़ी है। इससे माता ज्वाला जी, चामुंडा देवी और अन्य धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भारी दिक्कत हो रही है। इसमें बताया गया है कि पैरा नंबर 130 में कहा गया है कि हिमाचल सरकार खेलों के माध्यम से युवाओं को उच्च नैतिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता का विकास कर समाज कल्याण हेतु निरंतर प्रयासरत है और 43 करोड़ 34 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। लेकिन मेरी विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के चौहान स्टेडियम में पिछले तीन वर्षों से काम रुका हुआ है। वहां के नौजवान टूर्नामेंट आयोजित करने में असमर्थ हैं।

18.03.2026/1705/ए.पी. /एच.के. -3

मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य द्वारा राज्यपाल महोदय पर टिप्पणी की गई थी कि जब त्रासदी आई तो उन्होंने

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1710 /AT/HK /01

श्री रणवीर सिंह निक्का जारी....

हिमाचल के लोगों का ध्यान नहीं रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल जी जब त्रासदी आई तो दो दिन चंबा के दौरे पर रहे और प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। वहां पर लोगों को राशन, कंबल और गद्दे रेड क्रॉस के माध्यम से वितरित किए गए। यह बात भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। बार-बार बात कही जाती है हिमाचल सरकार के द्वारा हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे है हिमाचल सरकार को केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा और केंद्र सहायता नहीं कर रहा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जिन लोगों के घर कच्चे थे उन्हें प्रधानमंत्री आवास

योजना के तहत लगभग 93,000 घर बनाने के लिए केंद्र सरकार से अनुदान (ग्रांट) मिला। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करूं तो 1538 किलोमीटर सड़कों के लिए लगभग 294 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं। यह केंद्र सरकार की मदद है जिसके माध्यम से हर गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। अगर मैं हिमाचल की सरकार की बात करूं तो जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब सहारा योजना चलाई गई थी जिसे बंद कर दिया गया। हिमकेयर योजना चलाई गई थी उसका भी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं बार-बार केंद्र की बात की जाती है। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग द्वारा मेरी विधान सभा (नूरपुर) में 38 टैंक बनाए गए हैं और हर घर को नल से जल देने की योजना पर काम हुआ है। आप बार-बार हम पर आरोप लगाते हैं कि आपके उपर राजनीतिक दबाव है। हिमाचल की सरकार कांग्रेस के लोग चला रहे है कांग्रेस के मुख्य मंत्री हैं। हम तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जो भी मुद्दा होगा उसे सदन के अंदर उठाएंगे। हमारे ऊपर किसी प्रकार का केंद्र का राजनीतिक दबाव नहीं है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं तो हमारे उप-मुख्यमंत्री जी जब भी यहां से प्रस्ताव लेकर केंद्र में जाते हैं तो वे अपनी विभाग की कई योजनाओं की स्वीकृति लेकर आते हैं चाहे नदी का तटीयकरण (क्रेट वर्क) हो या अन्य कार्यों के लिए बजट लाना हो। उन्हें स्वीकृति मिलती है। अगर मैं लोक निर्माण विभाग की बात करूं तो हमारे मंत्री भी जब-जब केंद्र में जाते हैं तो माननीय

18.03.2026/1710 /AT/HK /02

गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं और अपने विभाग के लिए अच्छा-खासा बजट लेकर आते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार केंद्र द्वारा किए गए काम की एक बार भी सराहना नहीं करती। इसकी मैं निंदा करता हूं। मैं पिछले तीन वर्षों की बात करना चाहता हूं जब भी हमने विधायक प्राथमिकता के कार्य नाबार्ड के तहत दिए आज तक एक भी डी0पी0आर0 तैयार नहीं हुई। द्वेष की भावना से विपक्ष के विधायकों का काम किया जा रहा है। अगर डी0पी0आर0 बनती तो लोगों को पानी, सड़कों और पुलों की सुविधा मिलती। मैं

आपके समक्ष एक और बात रखना चाहता हूं नूरपुर विधान सभा क्षेत्र में कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार है लेकिन मात्र 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की जरूरत है। पुरानी बिल्डिंग बरसात के दिनों में पानी से भर जाती है पुरानी बिल्डिंग बनी है फिर भी सरकार 5 करोड़ रुपये देने में असमर्थ है। अगर मैं आगे बात करूं तो मैंने इस पर प्रश्न भी लगाया था हमारे विधानसभा क्षेत्र में बारड़ी का एक पुल बनकर तैयार है लेकिन केवल 30 लाख रुपये की आवश्यकता है। अगर यह राशि पीडब्ल्यूडी विभाग पुल बनाने के लिए दे दे तो वहां की एसटी बस्तियों को आने जाने के लिए बहुत लाभ मिलेगा। बरसात के दिनों में बच्चे खड्ड में पानी पार करके स्कूल जाते हैं। इसी तरह खजन का एक पुल है वहां पर भी एस0टी0 की आबादी रहती है

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1715/केएस/वाईके/1

श्री रणवीर सिंह (निक्का) जारी --

इसी तरह एक खज्जन का पुल है। वहां पर भी एस0टी0 आबादी है और लगभग 40 लाख रुपये की राशि वहां के लिए चाहिए मगर प्रदेश सरकार इस बजट को मुहैया करवाने में असमर्थ है। नूरपुर में हमारे चौगान में एक शॉपिंग कॉम्पलैक्स बन कर तैयार है। वहां पर लगभग 100 दुकानें बन कर तैयार हैं। अगर उनका आबंटन किया होता तो सरकार को रेवन्यू भी आता और रेहड़ी-फड़ी वालों को एक-एक दुकान भी मिलती। वह बिल्डिंग बन कर तैयार है, मात्र उसमें शटर वगैरह लगने हैं जिसके लिए 20 लाख रुपये की ज़रूरत है।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी इस माननीय सदन में बात रखी है कि नूरपुर विधान सभा के अंदर खजियां में हमारी मात्र एक गौशाला है। वहां पर बहुत बड़े-बड़े शैड बने हुए हैं। जब फोरलेन का प्रोजैक्ट बना, मात्र दो कमरे उस फोर लेन की जद में आए हैं और उसका मुआवजा भी सरकार के पास पड़ा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो मुआवजा मिला है, उसी राशि से दो कमरे बनाए जाएं। वहां पर इसके लिए बहुत सी जगह है। उस इलाके के लोगों को गौसदन की सुविधा मिलनी

चाहिए। सड़क में आए दिन कोई ना कोई एक्सिडैंट होता रहता है। बार-बार पशुओं को हमें इंदौरा भेजना पड़ता है और लोगों को बहुत मुश्किल आती है। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं करुंगा। हम विपक्ष की भूमिका में हैं। विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। नूरपुर विधान सभा क्षेत्र की, हिमाचल प्रदेश की जब-जब कोई बात होगी हम सदन के अंदर बखूबी उठाएंगे और सरकार का काम है। हिमाचल प्रदेश की सरकार आप चला रहे हैं। हिमाचल के हितों की रक्षा आपने करनी है। जब हमारी सरकार आएगी, हम योजनाएं ले कर आएंगे और हिमाचल प्रदेश के लोगों को कर्ज मुक्त हिमाचल बनाकर दिखाएंगे। तब हमारा हिमाचल के लोगों के साथ वायदा होगा कि किस तरह हम कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे। आप बार-बार कर्ज लेने की बात करते हैं, इतना सुंदर, इतना प्यारा हमारा हिमाचल है। यहां धौलाधार की पहाड़ियां हैं, इतना अच्छा टूरिज्म का क्षेत्र अतः सरकार आगे बढ़कर काम करें । हम बाहर के देशों में भी जाते हैं। दुबई में जा कर देखों, गोआ जा कर देखो, वहां की तरह ही यहां पर भी अच्छे-अच्छे प्रोजैक्ट्स आने चाहिए। यहां पर भी कैसिनो बनना चाहिए। बाहर से टूरिस्ट आते हैं, उनके माध्यम से हिमाचल की इन्कम बढ़े और हमारा

18.03.2026/1715/केएस/वाईके/2

हिमाचल कर्ज मुक्त हो, ऐसी मैं आशा करता हूं। आप बार-बार कर्ज लेने की बात करते हैं। इतने सुंदर पहाड़, दरिया, नाले, बाग-बागीचे हर चीज़ हिमाचल प्रदेश में है। हमारे यहां पर माइनिंग की बड़ी-बड़ी खदानें हैं। सरकार आगे बढ़कर काम करें और बार-बार जो कर्ज लेने की बात होती है, उससे निकलकर हिमाचल के हितों की रक्षा करें। ज्यादा ना कहते हुए सभापति महोदय, मैं इस अभिभाषण का समर्थन नहीं कर सकता। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय नूरपुर, धन्यवाद

18.03.2026/1715/केएस/वाईके/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर जी भाग लेंगे।

श्री नीरज नैय्यर : सभापति महोदय, 16 फरवरी,2026 का जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने सदन के समक्ष रखा, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, सत्र के वे तीन दिन मुख्य रूप से आर0डी0जी0 के ऊपर चर्चा के लिए रखे गए थे। इसके अंदर यही मुख्य बात थी कि सदन के समक्ष चर्चा की जाए कि प्रदेश की वित्तीय हालत क्या है और हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे विपक्ष के साथी हमारी बात सुनेंगे और हमारे साथ दिल्ली तक प्रधान मंत्री जी के समक्ष आर0डी0जी0 के मुद्दे को ले कर जाएंगे। किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 1952 से 15वें वित्तायोग तक हमारे प्रदेश को लगातार आर0डी0जी0 मिलती आ रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

18.03.2026/1720/av/yk/1

श्री नीरज नैय्यर------जारी

हम सब जानते हैं कि वर्ष 1952 से 15वें वित्तायोग तक आर0डी0जी0 लगातार हमारे प्रदेश को मिलती आ रही है। मैं अभी अपने विपक्ष के साथियों को सुन रहा था। कइयों ने यह कहा कि 14 राज्यों के अंदर आर0डी0जी0 बंद हो गई, इसीलिए हिमाचल प्रदेश में भी बंद हुई। यह केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं की गई है, it was an unilateral decision for all India. मैं यह बोलना चाहूंगा कि जब हिमाचल प्रदेश बना तो हमें पहले से पता था कि we are not a financial viable State. यह प्रदेश इसलिए बना था क्योंकि हमारा रहन-सहन और खान-पान देश के दूसरे राज्यों से भिन्न था और हम अपनी संस्कृति को बचाए रखें। यह ऑलरेडी एक नॉन फैक्ट था। प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए

आर0डी0जी0 एक बहुत जरूरी चीज थी। लेकिन अब बंद हो जाने की वजह से हमारे सभी विकास के कार्य स्थगित हो जाएंगे। यह बात केवल काँग्रेस या भाजपा की नहीं है, यह प्रदेश के हित से जुड़ी हुई बात है और सरकारें तो आती-जाती रहती हैं।

मुझे लगता है कि पिछले कल आर0डी0जी0 से संबंधित रिपोर्ट संसद की सभा पटल पर रखी गई थी। हम तो अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं। यहां पर विपक्ष के साथी हंस रहे थे और बोल रहे थे कि कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए हमें अभी भी आस है कि शायद कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन अगर यह आर0डी0जी0 की कटौती हुई तो अगले आने वाले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश की जनता को सफर करना पड़ेगा। हम चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में, यह कोई अच्छी बात नहीं है।

अभी हमारे एक विपक्ष के साथी बोल रहे थे कि आर0डी0जी0 के बारे में कितनी रट लगाएंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक दिन में ठीक हो जाएगी, इसमें समय लगेगा। श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी जिस दिन मुख्य मंत्री बनें तो इन्होंने प्रदेश की वित्तीय हालत के बारे में स्पेसिफिकली बात रखी थी। हालांकि मुझे यह पता नहीं था कि आर0डी0जी0 बंद हो जाएगी, मैं भी अपने पक्ष व विपक्ष के मित्रों से पूछता रहता था कि क्या यह बंद हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था जबकि अब सारे बोल रहे हैं कि हमें पता था और यह तो बंद होनी ही थी। परंतु फिर भी

18.03.2026/1720/av/yk/2

सबने उम्मीद लगा रखी थी। अभी नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर कह रहे थे कि मैं खुद वित्त मंत्री जी के पास गया था कि हमारे प्रदेश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है इसलिए इसको जारी रखना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह शायद किसी को भी पता नहीं था कि यह बंद होनी है। मैं विपक्ष के साथियों को बोलना चाहता हूं कि आप एक चीज के बारे में ध्यानपूर्वक तरीके से सोचिए। लोक सभा में हमारे 4 सांसद हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने संसद में प्रधानमंत्री जी को भरपूर सहयोग दिया है। मुझे याद है क्योंकि एम0पी0 के चुनाव के दौरान मैंने भी दिन-रात मेहनत की थी और मैंने भी सोचा था कि शायद मैं भी

अपने विधान सभा क्षेत्र से लीड लेकर आऊंगा। परंतु ऐसा सम्भव नहीं हो सका। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिमाचल के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बहुत सपोर्ट किया है। यहां से चार एम0पी0 और दो राज्य सभा की सीट्स भारतीय जनता पार्टी की है। अभी राज्य सभा की एक चेंज हुई है। इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि केंद्र में हिमाचल प्रदेश के हितों को ठीक ढंग से रखा जाए। साथियों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपदा के दौरान प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश आए थे। वे धर्मशाला आए थे, वहां पर माननीय मुख्य मंत्री भी गए थे। उन्होंने वहां पर 1500 करोड़ रुपये की अनाउंसमैंट की थी।

टी सी द्वारा जारी

18.03.2026/1725/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

श्री नीरज नैय्यर.... जारी

उसके बाद बिहार के चुनाव आए। जब बिहार के चुनाव आए तो 10 हजार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डाले गए। जिसका मतलब है कि 10,000 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने डारेक्ट इन लोगों के खाते में ट्रांसफर किए। तब तो दिल्ली की सरकार के पास पैसा था। हमारे यहां तो आपदा आई हुई थी। हमारा तो उस लिहाज से हक बनता था लेकिन हमें तब भी नहीं मिला। उसके बाद मैं एक और विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जब बिहार की बात आती है, आंध्र प्रदेश की बात आती है तो उन राज्यों को स्पेशल पैकेजिज मिलते हैं। हमारा क्या कसूर है, हमारे सिर्फ 4 सांसद हैं क्या इसलिए हमें नजरअंदाज किया जाता है? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यह हम सबका दायित्व बनता है कि हमारा जो केस है, वह प्रोपरली केन्द्र सरकार के समक्ष रखा जाए।

मैं सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का दिल से समर्थक हूं, जिस स्थिति में उन्होंने प्रदेश को संभाला, पहले तो हमारी आर0डी0जी0 बंद हो गई। जब मुख्य मंत्री बने तो 2023 की आपदा आई और बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद 2025 की आपदा आई और उसमें भी

बहुत नुकसान हुआ। जो भी हमारे पास सीमित संसाधन थे, मुख्य मंत्री जी ने पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 7 लाख रुपये घरों को दिए, which was out of the way. उन्होंने सारी सड़कें खुलवाई और हर संभव काम किया। चंबा के अंदर भरमौर कितने दिन तक बंद रहा। मुझे याद है, सब लोग बोल रहे थे कि मुख्य मंत्री जी चंबा नहीं आए। वे हेलिकॉप्टर से आए और जैसे ही चंबा आए तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग ली और वहां जो श्रद्धालु फंसे हुए थे उनको Chinook helicopter से लाया गया। They are very expensive helicopters for special missions. श्रद्धालुओं को शिफ्ट करने के लिए स्पेशल परमिशन ली गई। वे पहले भरमौर में लैंड नहीं कर सके लेकिन बाद में Chinook helicopter भरमौर में लैंड किया। राजस्व मंत्री, श्री नेगी जी पैदल भरमौर तक आए। कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को तरक्की की राह पर अग्रसर किया है। यह मैं पहली बार देख रहा हूं कि प्रदेश के अंदर कोई ऐसी सरकार आई है जिसने प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के बारे में सोचा है। इससे पहले जितनी भी सरकारें आईं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार थी उनको लोन और आर0डी0जी0 की सुविधा थी तो सोच यही रहती थी कि पैसा मिले और उसे खर्च कर

18.03.2026/1725/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

करें। लेकिन इस बार मुख्य मंत्री जी ने liquor vends के ठेकों को ऑक्शन किया। मेरे यहां भी ठेकेदार लॉबी थी। वे मुझसे आग्रह कर रही थे कि प्लीज ऑक्शन मत होने दो, 10 प्रतिशत इंक्रीज करके हमें ही दे दो। लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उस समय एक कठिन निर्णय लिया। इससे प्रदेश की आय में बढ़ोतरी हुई। इसी तर्ज पर वाइल्ड फलावर हाल का केस लड़ा गया और उसमें भी जीत मिली जिससे राज्य की आय बढ़ी। वाटर सैस भी लागू किया गया। चंबा के अंदर NHPC hydro projects में डोमिनेट करता है। हाल ही में NHPC के अधिकारियों की मीटिंग हुई। I ask them what is your turnover.उन्होंने बताया कि NHPC का टर्नओवर करीब 68000 करोड़ रुपये है। अगर SJVN की बात करें तो वह इससे भी ज्यादा हो सकता है। हमारे प्रदेश के अंदर इतने बड़े पब्लिक सैक्टर यूनिटस चल रहे हैं। उन्होंने अपने लोन्स भी पूरे कर दिए हैं।

एन0एस0 द्वारा .... जारी

18-3-2026/1730/NS-AG/1

श्री नीरज नैय्यर ----जारी

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी भी यहां बैठे हैं और ये राख की एक सड़क के बारे में बोलते रहते हैं तो वहां पर एन0एच0पी0सी0 वाले कितनी बार डंगे लगाएंगे। वे हर बार डंगा लगाते हैं और हर बार डंगा गिर जाता है। मैंने बेसिकली यह चीज ऑब्जर्व की है कि एन0एच0पी0सी0 के जितने भी हाइड्रो प्रोजैक्ट्स हैं इनकी इन्कम हजारों करोड़ों रुपये है और इनको ये भी पता नहीं है कि इस पैसे को कहां खर्च करना है? वहां पर ठेकेदार आते हैं और अपने एस्टिमेट देते हैं तथा पैसा ऐसे ही चला जाता है। ये प्रोजैक्ट्स टोटली फ्री हैं। चमेरा-I टोटली फ्री है और Chamera-III is also free. सबसे पुराना प्रोजैक्ट जो सलूणी की तरफ लगा था वह कई सालों से फ्री हो गया है। अगर वाटर सैस के माध्यम से या फिर इन प्रोजैक्टों में हिमाचल प्रदेश का जो शेयर है वह बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि हमें बाहर से किसी वित्तीय सहायता की जरूरत नहीं रहेगी। मैं विपक्ष के साथियों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि सरकारें किसी की भी हों। जो चीज़ सही है उसको सही कहना चाहिए और जो चीज़ गलत है उसको गलत कहना चाहिए। जब वाटर सैस की बात हुई तो भारत सरकार कोर्ट में चली गई अन्यथा यह निर्णय भी हमारे हक में आ सकता था। अगर हमारे हक में नहीं भी आता तो जो हमारा शेयर उस प्रोजैक्ट में कम था नेगोशिएशन के साथ उसको बढ़ाया जा सकता था। मुख्य मंत्री जी ने कुछ अच्छे स्टेप्स प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए उठाए हैं। अभी यहां पर भांग की खेती की बात चल रही थी और मैं सुन रहा था कि इस सत्र के अंदर शायद उसको भी स्वीकृति मिले। हमारे हिमाचल प्रदेश को किसी चीज़ की कमी नहीं है। We are young Himalayas. जब मैं किसी टाइम में बिजनैस करता था तो मैं अपने प्रोडक्टस को हिमालय के नाम पर इंटरनेशनल में बेचता था। जब कोई प्रोडक्ट एल्पस और एंडीज या रॉकी के नाम से बिकता था। These are all mountain chains. जब हिमालय का नाम आता था तो इंटरनेशनली सबसे ज्यादा वैल्यूज हिमालय

की होती थी। They are known all over the world. हम हिमालय की गोद में बैठे हुए हैं। हमें दुःख इस बात का है कि जंगल हमारे, पानी हमारा, संपदा हमारी और उसका सारा कंट्रोल भारत सरकार के हाथ में है। मैं यह इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपकी सरकार है या किसी ओर की सरकार है लेकिन दुःख की बात यह है कि अभी प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई और लोग रोज मेरे घर में आते हैं

18-3-2026/1730/NS-AG/2

और कहते हैं कि हमें घर बनाने के लिए पैसे मिले हैं लेकिन जिस जगह में उन्होंने घर बनाने हैं वह जगह घर बनाने लायक नहीं रही है। अब हम उनको लैंड कहां से दें? हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम उनको जमीन दे सकें। These are things, which are very important and debatable. अभी मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि वे अब नई टाउनशिप बनाने की बात कर रहे हैं। I think this is a good decision. हम जैसे सारे लोग कोई मोहाली में कुछ खरीद रहा है, कोई चंडीगढ़ में कुछ खरीद रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई टाउन नहीं है जबकि हम चंडीगढ़ के साथ लगते हैं। यहां पर कोई सैटेलाइट टाउन ही नहीं है। This is a good decision. इससे भी प्रदेश की आय में बढ़ौतरी होगी। आप लोगों ने सरकार की आलोचना करनी है और हम लोगों ने पक्ष में बोलना है। यह हमारा धर्म है और हमें करना भी पड़ेगा तथा करना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कंसिस्टेंटली कुछ ऐसे डिसीजन्स हैं, सरकारें आती-जाती रहती हैं they should continue on continuity, which is very important and good for the overall health of the State. मैं आपके समक्ष एक और बात रखना चाहूंगा। जहां तक मेरे चम्बा विधान सभा क्षेत्र की बात है और मैं 15 वर्षों के बाद चम्बा से विधायक चुनकर आया हूं। यहां पर विपक्ष के कई साथी बोल रहे थे कि आपके यहां पर काम हो रहे हैं

आर0के0एस0 द्वारा----जारी

श्री नीरज नैय्यर जारी.....

लेकिन हमारे चुनाव क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहे हैं और हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों से भाजपा का विधायक सत्तासीन था लेकिन मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। हर व्यक्ति जो विधायक बनता है अपने विधान सभा क्षेत्र में काम करवाने की कोशिश करता है। यह कोई नहीं चाहता कि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में काम न करवाऊं। वित्तीय संकटों के बावजूद भी हमारे चम्बा विधान सभा क्षेत्र की एक वर्षों पुरानी पार्किंग की डिमांड को पूरा किया गया है जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पिछली बार श्री पवन नैय्यर जी चम्बा से विधायक थे। उन्होंने भी पार्किंग बनाने की कोशिश की थी लेकिन किसी कारण से वे कामयाब नहीं हो पाए। इस पार्किंग की कंस्ट्रक्शन बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा की जा रही है और अब इसका कार्य शुरू हो गया है। चम्बा डिस्ट्रिक हैड क्वार्टर है लेकिन वहां पर अभी तक मिनी सचिवालय स्थापित नहीं है। वहां पर अब मिनी सचिवालय का कार्य 38 करोड़ रुपये की लागत से शुरू हुआ है। सुल्तानपुर हैलीपैड को हैलीपोर्ट में कंवर्ट कर दिया गया है। उस हैलीपोर्ट का कार्य भी 75 प्रतिशत पूर्ण हो गया है और इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। अगले वर्ष वहां से फ्लाइट्स शुरू हो जाएगी। इस हैलीपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत हम लोगों को ही है। चम्बा, भरमौर और चुराह चुनाव क्षेत्रों से शिमला का इतना लम्बा फासला है कि अगर हम लोग गाड़ियों से शिमला आएं तो हमारी उम्र 10 साल घट जाती है। इसलिए हैलीपैड बनाना हमारी प्राथमिकता है। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह के लिए 4 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। हमारे साहो में एक पुरानी कूहल थी उसके लिए भी 5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरोल-हरिपुर-राजपुरा सीवरेज के लिए 20.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। जब आपकी सरकार थी तो आपको केंद्र सरकार से 70 हजार करोड़ रुपये मिले थे जबकि इसके वनस्पत हमें बहुत कम राशि मिली है। मैं पहली बार विधायक बना हूं। आपका फंड उतना सा ही है लेकिन आप अपने फंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं यह विचार करने की

बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

18.03.2026/1735/RKS/AS-2

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री दीप राज जी भाग लेंगे।

श्री दीप राज : सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्री, श्रीमती कमलेश ठाकर और श्री संजय अवस्थी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे तीन साल लगातार इस सदन में बात रखने के बाद श्री बेली राम जी को पेंशन मिल गई। जब मैंने लगातार तीन साल यह विषय इस सदन में उठाया तो श्री बेली राम जी को पेंशन मिली। लेकिन यह विचार करने की बात है कि न जाने आज कितने बेली राम सड़कों में अपनी रातें गुजार रहे हैं। यह आपका व्यवस्था परिवर्तन है। सरकार की इस व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र क्या है? सरकार का मूल मंत्र है धन दो, काम लो, धन दो, ट्रांसफर लो, धन दो, पेमेंट लो, धन दो, जोब लो, धन दो, 118 लो, धन दो, पेड़ काट लो। यह वर्तमान सरकार की व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को कांग्रेस सरकार के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी बहुत पहले जान गए थे। इसलिए उन्होंने कहा था कि जब मैं दिल्ली से 100 रुपये भेजता हूं तो उसमें से सिर्फ 15 रुपये ही अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वे कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ताओं की मंशा बहुत पहले जान गए थे। विडम्बना देखिए कि ऐसी ही परिस्थिति आज हिमाचल प्रदेश में बन गई है और हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस की ही सरकार सतासीन है। जो बात

श्री बी0एस0 द्वारा जारी.....

18.03.2025/1740/बी.एस./ए.एस.-1

श्री दीप राज जारी...

स्वर्गीय राजीव गांधी जी इतने वर्ष पहले कह गए थे, वे इनकी मंशा बहुत वर्ष पूर्व समझ गए थे और इस सरकार में अध्यक्ष महोदय सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके कुछेक उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। सराहन पंचायत के अन्तर्गत एक कोठी गांव आता है। सरकार घर बनाने के लिए सात लाख रुपये की बात कर रही है परंतु मेरे वहां पर आपके कार्यकर्ता 12 लाख रुपये में एक कमरा और एक सीढ़ी नहीं बना पाए।

दूसरा, करसोग विधान सभा क्षेत्र में काणू पंचायत में सरकारी सीमेंट की चोरी हो रही है। बकायदा लाइव के माध्यम से, न्यूज़ों के माध्यम से वह प्रकाशित हुआ है। लेकिन उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। इसके इलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक करोड़ रुपये की सड़कें, एक माननीय जिन्हें सरकार में ऊंचा पद मिला है, एक करोड़ रुपये की स्कूटी से वे सड़कें निकाल गए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है और तो और अध्यक्ष महोदय, जब आपदा के बाद केंद्र सरकार ने पी0डी0एन0ए0 के तहत हर विधान सभा के लिए पैसे दिए, एक करोड़ रुपये के अंडर द टेबल हायरिंग के टेंडर लगा दिए गए। अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर नहीं तो क्या है?

इसके अलावा आपदा का जो समय था, इन्होंने आपदा के समय को भी नहीं छोड़ा। आपदा के समय को अवसर बनाकर अपने लोगों को पिक और चूज करके घरों के लिए डंगे दिए और घरों के लिए पैसे दिए। जिसका मैंने सुबह जिक्र किया था, एक व्यक्ति को सिर्फ 3 लाख रुपये दिए हैं और 7 लाख रुपये की बातें कर रहे हैं। इस संबंध में आपका उत्तर था और कहते हैं कि गत वर्ष की बात हो रही है। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पूरे 3 वर्षों की बात हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं छोटा था तो कई बार पिता जी के साथ चंडीगढ़ जाया करता था। बचपन में क्या होता है कि जादू के शो देखने का बड़ा शौक रहता है और बच्चे जादूगर सम्राट के शो के लिए बड़े मुरीद रहते हैं। जादूगर क्या करता है? चमक-धमक, अच्छे कपड़े पहन करके लाइट की चकाचौंध में गुलाब दिखाता है और गायब कर देता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब मैं इस विधान सभा में पहुंचा तो मुख्य मंत्री

18.03.2025/1740/बी.एस./ए.एस.-2

जी की भ्रमित करने वाली कार्य प्रणाली ने तो जादूगर सम्राट को ही पीछे छोड़ दिया। परंतु फिल्मों में एक जादूगर गोगो आते हैं झूठ बोलने में और भ्रमित करने में गोगो को भी पीछे छोड़ दिया और जादूगर सम्राट से भी एक कदम आगे निकल कर आए।

सबसे पहले जादू क्या होता है। सबसे पहले जादू बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 150 स्कूलों को सी0बी0एस0ई0 स्कूल कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड है, एच0पी0 भी बोर्ड है। आप हिमाचल प्रदेश के बोर्ड को खत्म कर रहे हो। एच0पी0 बोर्ड और सी0बी0एस0ई0 बोर्ड तो एन0सी0ई0आर0टी0 को फॉलो करता है। आज हमें यह समझने की जरूरत है कि प्राइवेट स्कूल इतने अच्छे क्यों हैं, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है। टीचर तो उनके कम तनख्वाह पर काम करते हैं, उसके बावजूद उनका रिजल्ट अच्छा रहता है। सबसे पहले क्या जादू चलाया कि डे-बोर्डिंग खोलेंगे। ये आपकी बुक में था। पूरे हिमाचल प्रदेश में 68 विधान सभा क्षेत्रों में 68 साइट्स आइडेंटिफाई की। ऐसा जादू, अध्यक्ष महोदय, 68 में से एक भी धरातल पर नहीं पहुंची। सारा खाली और चकाचौंध और भाषण तालियां बजाने वाले होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी ये नहीं रुके, उसके बाद जब एच0पी0 बोर्ड को इन्होंने खत्म करने की बात कही तो इससे अच्छा ये करते कि कम-से-कम एच0पी0 बोर्ड के जो स्कूल थे, उन्हीं को डेवलप करते, अच्छी स्मार्ट क्लासेस बनाते, प्लेइंग ग्राउंड को बड़ा करते और तो और क्या कर दिया गया कि जो टीचर इतनी सालों से नौकरी कर रहे हैं, उन टीचरों की फिर से स्क्रूटनी होगी, उनका टेस्ट होगा। मुख्य मंत्री जी, तो यहां नहीं हैं, अगर आज दसवीं का पेपर दोबारा देने के लिए बोलेंगे तो हम में से कोई पास नहीं कर पाएगा। यहां पर आई0ए0एस0 बैठे हैं इन्हें बोलो कि एक बार फिर से आई0ए0एस0 का पेपर निकाल कर दिखाएं।

इनके साथ यह भेदभाव नहीं तो अध्यापकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपका यह भेदभाव नहीं है? आप एच0पी0 बोर्ड को खत्म कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अप्लाई नहीं कर रहे, वे

18.03.2025/1740/बी.एस./ए.एस.-3

बेचारे परेशान हैं। अब सोचिए, यह तो प्रश्न चिन्ह है, जो एच0पी0 बोर्ड में पढ़ा रहे थे, उनको पेपर देना पड़ेगा। मतलब अभी तक जो पढ़ाया जा रहा था वह गलत पढ़ाया जा रहा था, वह सिस्टम ही नहीं था। ऐसी तो इनकी कार्य प्रणाली है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी ने जब एक्साइज पॉलिसी बनाई, तो यह आइडिया भी मुख्य मंत्री जी का ही है। इन्होंने अकेले में सोचा कि एक्साइज पॉलिसी का आइडिया आ गया। फिर मन ही मन में उन्होंने अपनी सराहना भी खुद कर ली कि यह तो बहुत एक्सीलेंट आइडिया है, वेरी नाइस आइडिया है। सबको बुलाया गया और इस आइडिया को धरातल पर उतारने की बात कही गई। अध्यक्ष महोदय, केग की रिपोर्ट पिछले एक साल से बता रही है कि यह जो एक्साइज ड्यूटी आपने लगाई है और जो एक्साइज पॉलिसी आपने बनाई है, इस एक्साइज पॉलिसी की वजह से अपने ऑनलाइन की बात की। आपके 50 प्रतिशत से ज्यादा ठेके बिक नहीं रहे हैं। जिन ठेकेदारों ने पिछली साल ठेके लिए थे, उनके घर बिकने पर आ गए।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

18.03.2026/1745/डीसी/डीटी-1

श्री दीप राज जारी.....

उनके photo बैंकों में लगे हैं। और तो और इस बार आपके पास कोई apply करने के लिए नहीं रहा। इसके बाद आपने क्या किया? अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जो लोग मनरेगा में काम करते हैं, जो लोग दिहाड़ी में काम करते हैं, जो मजदूर तबके का काम होता है, वे लोग अधिकतर देसी शराब पीते हैं। देसी शराब का इन्होंने रेट बढ़ा दिया है। अब जो आदमी बेचारा छह सौ रुपये की दिहाड़ी कमा रहा है, वह तीन सौ रुपये की तो

दारू पी जाएगा। उसके घरवाले क्या खाएंगे? किस तरह से पिछड़ों और गरीबों का खून चूसा जाए, ऐसी है यह व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार। ...(व्यवधान) इससे भी तो रेवेन्यू आता है, हिमाचल प्रदेश की आय बढ़ती है। अगर Dry state कर दिया जाए तो आप लोगों का तो यहां आना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही आर0डी0जी0 बंद की गई इन लोगों ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। सनसनी फैलाने के बाद बेचारा बनने की कोशिश की गई। अब इन्होंने कैबिनेट रैंक के चेयरमैनों की शक्तियां कम कर दी। इसका मतलब तो यह था कि पिछले तीन सालों से जो RDG का पैसा आ रहा था उससे मित्रों की मौज हो रही थी। उस RDG के पैसे से तीन साल मौज की गई। आज जब यह बंद की गई तो ये cabinet rank के पदों को बंद करने की कगार में खड़े हो गए। लेकिन इसका दोष केंद्र सरकार को दिया गया। यह जादू यहां तक ही नहीं रुक रहा है। हमारे HRTC Minister अभी यहां उपस्थित नहीं है।। इस जादू ने ऐसा कमाल किया कि हिमाचल प्रदेश में पांच सौ बसें नई आई। मैं बड़ा खुश था कि पांच रूट दे दिए गए और करसोग में कहा कि अब प्रदेश में बसें ही बसें चलेंगी। लेकिन हुआ क्या? पैंतीस रूट बंद कर दिए गए। जिन पिछड़ों की, जिन स्कूल के बच्चों की, जिन महिलाओं की, जिन गरीबों की, जिस अंतिम व्यक्ति के विकास की आप बात करते थे, वे लोग इन बसों में ट्रैवल करते थे । आप शहरों वाली विधान सभा क्षेत्रों को छोड़ कर कभी हमारे पहाड़ी क्षेत्र के विधान सभा क्षेत्र में आइए। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी ठीक कह रहे थे कि कहां द्रंग है, कहां करसोग है और ऐसे ही करसोग विधान सभा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। वहां लोगों के पास इतनी आय नहीं है कि वे अपनी गाड़ियां खरीद सके। चौहरीदार से कटौल के लोगों को इतना परेशान किया गया। पहले तो वहां जाकर झूठी घोषणा कर दी कि हम सड़क बनाएंगे। जो रूट

18.03.2026/1745/डीसी/डीटी-2

वर्ष 2023 में नुकसान में चल रहे थे क्योंकि वर्ष 2023 में आपदा आई थी और वहां बसें चलनी ही नहीं थी। जब बसें चली ही नहीं तो यह कैसे identify हो गया कि इस रूट पर आय ही नहीं हो रही है। इस रूट के आय के साधन ही बड़े कम हैं। आपने कहा कि आपदा में हमने डंगे लगा दिए, पुल बना दिए, सड़कें बना दी। मैं तीसरी साल फिर बोल रहा हूं कि

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुन्नी का जो एक पुल था वह अभी तक नहीं बना। कामाख्या माता मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वहां से छोटे-छोटे बच्चे खड्ड को क्रॉस करके स्कूल के लिए जाते हैं। वहां भी पुल नहीं बना। यह भी आपका हवाई जादू है। मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन जादू करसोग में किया। CRF के तहत पहली बार करसोग के लिए 31.80 करोड़ रुपये आए। उन्होंने उसका वहां शिलान्यास किया और शिलान्यास करते हुए कह गए कि मैं आंवले की तरह हूं और मैं बाद में समझ आऊंगा। प्रदेश को और करसोग वालों को आंवला समझ आ गया है। अब बहुत बढ़िया आंवला आ रहा है। वहां पर शिलान्यास कर दिया लेकिन उसके कागजात बनाए ही नहीं हैं। 31.80 करोड़ रुपये को आए हुए डेढ़ साल हो गए हैं लेकिन उसका टेंडर ही नहीं हो पा रहा है। CRF के तहत जो पैसे आए थे उनका तो टेंडर लगा ही नहीं। यह भी जादूगर सम्राट से बड़ा जादू है। ये तो जादूगर गोगो से बड़े जादूगर निकले। हमारे मुख्यमंत्री जी जादूगर मंगल तारा से ज्यादा जादूगर निकले। इन्हें भी अगर जादूगर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी आर्थिकी सेब की है। हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष अट्ठानवे हज़ार पांच सौ छह मीट्रिक टन C grade सेब खरीदा गया जिसमें से पचास प्रतिशत सेब सड़ गया है। लोग लाखों की पर्चियां लेकर घूम रहे हैं। अब आप वर्ष 2027 में वोट मांगने जाना आपको पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है? उस समय आपका कोई जादू नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश के किसानों के साथ भी भद्दा मजाक किया गया। बड़ी जोरो शोरों से प्रचलन किया गया कि हल्दी उगाइए। हिमाचल प्रदेश की जनता पचहत्तर लाख है जिनमें से 70 प्रतिशत किसान हैं। आपने दस लाख लोगों में से केवल इकसठ लोगों की ही हल्दी खरीदी। यह आपका पीला और काला जादू था। ...(व्यवधान)

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

18.03.2026/1750/डी.सी.-एन.जी./1

श्री दीप राज..... जारी

...(व्यवधान) आप अभिभाषण वाली किताब में पढ़ लीजिए कि 75 लाख लोगों में से 61 किसानों से सरकार ने हल्दी खरीदी है और मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की जनता को इनके लिए तालियां बजानी चाहिएं क्योंकि प्रदेश सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा मिल्क सेस के संदर्भ में बड़ी बात की जाती है कि हमने दूध का रेट बढ़ा दिया।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, शहरों में गाय नहीं होती, उसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों जैसे आनी, सिराज, करसोग आदि क्षेत्रों में जाना पड़ता है क्योंकि वहीं पर अच्छी किस्म की गाय होती हैं। सरकार की योजना को देखकर और स्टार्टअप समझकर कई लोगों ने गाय खरीद ली। अब जिस आदमी ने अपनी जवानी में चार गाय रखी हैं और वह उनको पाल रहा है, उनके लिए घास व फीड इकट्ठा कर रहा है लेकिन उस व्यक्ति के बिजली के बिल में भी मिल्क सेस लगाया गया है और उसकी दारू में भी मिल्क सेस लगाया गया है। मैं तो बेचारे मनरेगा वालों का सोच रहा हूं कि वे पीएंगे कैसे? इसके अलावा मिल्क सेस के पैसे ही कम-से-कम मिल्कफैड को मिल जाते तो अच्छा होता लेकिन वे भी नहीं मिले और यह भी बहुत बड़ा जादू है। मिल्क सेस का पैसा कहां जा रहा है, यह भी तो माननीय सदन में बताया जाए? मिल्क सेस के नाम पर पूरे हिमाचल प्रदेश में ठगी की जा रही है। प्रदेश सरकार केवल यह कह रही है कि दूध का दाम 52-54 रुपये होगा लेकिन यह नहीं बताया कि गाय के दूध की क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या काम किया गया? प्रदेश सरकार ने न तो कोई सब्सिडी दी और न ही फीड के लिए कोई पैसा दिया, बस इतना कह दिया कि मिल्क सेस लगाएंगे। सत्तापक्ष के लोग अभी बता रहे थे कि 2-4 सेस और लगाने वाले हैं। सभापति महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा जनता के पैसे को लूटकर खजाना भरा जा रहा है और ऊपर से दोष-प्रत्यारोपण की राजनीति की जा रही है और कहते हैं हम सब एक हैं। यहां पर अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि 20-30 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सभापति महोदय, मेरे गांव में मैं तीन साल से कह रहा हूं कि एक छोटा-सा पुल बना दो क्योंकि वहां से छोटे-छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और प्रदेश सरकार से उसके लिए तो पैसे दिए नहीं जा रहे तथा बात समानता की करते हैं।

18.03.2026/1750/डी.सी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, प्रदेश सरकार ने सबसे बड़ा जादू तो युवाओं, पिछड़ों और महिलाओं के साथ किया है। इस अभिभाषण में लिखा गया है कि 645 पटवारी की पोस्टें खोली गईं हैं और उसमें 40 हज़ार रुपये की सैलरी भी बताई गई है। मैं बताना चाहता हूं कि 70 हजार बच्चों ने पटवारी का टेस्ट भरा। सत्ता पक्ष के लोगों ने उसमें क्या जादू किया? पहले जो टेस्ट होते थे, उसमें चाहे अनुसूचित जाति के बच्चे हों, ओ0बी0सी0 के हों या महिलाएं हों, उन सभी को फीस में छूट मिलती थी लेकिन इस सरकार ने सबसे 800-800 रुपये लिए। यह सरकार महिलाओं व ओ0बी0सी0 की विरोधी सरकार है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के लोगों की भी विरोधी सरकार है। इन्हीं लोगों की वजह से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था क्योंकि उस समय देश में सत्ता पक्ष के लोगों की सरकार थी। इतनी महान हस्ती को भी धर्म बदलने पर इन्हीं लोगों ने मजबूर किया।...(व्यवधान) मैं सच्चाई बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, समय कम है इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं। अंत में मैं एक शायरी कहना चाहता हूंः-

मिजाजी मानव के मुकद्दर में मौजे हैं हज़ार,

नीचे नाव नहीं और हाथ में है पतवार।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम इसका समर्थन कदापि नहीं कर सकते क्योंकि (***) धन्यवाद।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

Speaker: This will not be part of the record. (***)will not be part of the record.

अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री मलेन्द्र राजन भाग लेंगे।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

18.03.2026/1750/डी.सी.-एन.जी./3

श्री मलेन्द्र राजन : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, श्री सुरेश कुमार द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह अभिभाषण हिमाचल प्रदेश की जनता के विश्वास, उसकी उम्मीदों और हमारी सरकार के संकल्प का एक दस्तावेज है। यह ठीक है कि राज्यपाल महोदय ने उस प्रस्ताव को यहां पर पढ़ा नहीं और पढ़ा हुआ समझा जाए,

श्री ए0पी0 द्वारा.....जारी

18.03.2026/1755/ए.पी. /एच.के. -1

श्री मलेन्द्र राजन जारी .....

ऐसी टिप्पणी करके वे चले गये लेकिन पिछले तीन वर्षों में जब से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पूरे प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर शुरू किया, तब से अनेक चुनौतियां सामने आईं। वर्ष 2022 में सरकार बनने के समय भी कई चुनौतिया थीं, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं। जो हमारे वायदे प्रदेश की जनता के साथ थे उन्हें पूरा करने की दिशा में सरकार पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। बीच-बीच में काफी चुनौतियां भी आईं। अगर हम वर्ष 2023 की बात करें तो उस समय बड़ी प्राकृतिक आपदा प्रदेश में आई। वर्ष 2024 में राजनीतिक संकट और वर्ष 2025 में फिर प्राकृतिक आपदा ने प्रदेश को झकझोर दिया। इससे बहुत-सा

नुकसान प्रदेश में हुआ। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार लगातार प्रयासरत हैं कि प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाया जाए। जिस तरह से आम जनमानस के साथ हमारी कमिटमेंट थी उनको पूरा करने की दिशा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से पिछले तीन वर्षों में कई अभूतपूर्व योजनाएं शुरू हुईं जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचा है। यह ठीक है कि विपक्ष के साथी हर बात में सरकार की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हर बात पर गुमराह करने की राजनीति करते हैं। लेकिन धरातल पर हम देखें तो जिस तरह से वर्ष 2024 में राजनितिक आपदा आई थी उसके बाद 9 विधायक जिसमें से 6 विधायक हमारी पार्टी के थें और वे हमारी पार्टी को छोड़कर चले गये थे। जिससे उत्पन्न परिस्थिति में प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव हुआ और हमारी पार्टी ने एक बार फिर से 40 सीटें जीतीं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जैसे हम लोग राजनीति में है और यहां पर जनता के सामने जो हमारी परीक्षा है जिसमें की हमें जनता के बीच जाना पड़ता है और वर्ष 2024 में उस परीक्षा में जनता ने हमें दोबारा चुना और हमें एक बार फिर से 40 सीटों पर पहुंचाया। नेता प्रतिपक्ष माननीय जयराम ठाकुर जी तुलना कर रहे थे कि उनकी सरकार में करोड़ों के काम हुए। लेकिन यदि वास्तव में ऐसा होता तो जनता उन्हें विपक्ष में नहीं बैठाती। यही हाल वर्ष 2024 में भी हुआ और आने वाले समय में भी जिस निष्ठा और चुनौतियों के साथ हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर

18.03.2026/1755/ए.पी. /एच.के. -2

रहे है और आगे लेकर भी जा रहे है निश्चित रूप से वर्ष 2027 में भी हम पक्ष में ही बैठेंगे और आप विपक्ष में ही रहोगे। यह सुनिश्चित है क्योंकि प्रदेश की जनता हर चीज को भली-भांति देख रही है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर आर0डी0जी0 की बात की जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं विधायक निधि की जो बात की जा रही है कि एक करोड़ रुपये की विधायक निधि नहीं मिली तो हमारे विपक्ष के साथियों को इतनी चिंता हो गई। लेकिन प्रदेश की जनता का हर साल 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ उसकी इनको चिन्ता बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश की जनता का पांच सालों में 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है उसकी चिंता विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1800 /AT/HK /01

श्री मलेन्द्र राजन जारी...

उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्षः ठाकुर साहब बैठिए।

श्री मलेन्द्र राजनः मैं इस बात का जिक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि इस दिशा में कोई भी सकारात्मक पहल हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा नहीं आई है।

अध्यक्षः माननीय राजन जी, अभी माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष बोल चुके हैं। अभी एक माननीय सदस्य दिलीप सिंह जी हैं और मलेन्द्र राजन जी बोल रहे हैं तो **अब इस माननीय सदन की बैठक 6:30 तक बढ़ाई जाती है।**

श्री मलेन्द्र राजनः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात का जिक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल हमारे विपक्ष के नेता या विपक्षी साथियों की तरफ से नहीं आई। यह प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाने का प्रयास है। निश्चित रूप से यह पैसा प्रदेश की जनता के विकास कार्यों के लिए खर्च किया जाना था जिसका नुकसान आज प्रदेश के अंदर हुआ है। यह कोई माननीय मुख्य मंत्री जी के निजी पैसे नहीं हैं और न ही कांग्रेस पार्टी के पैसे हैं बल्कि यह प्रदेश की जनता के पैसे हैं जिनका हक केंद्र सरकार ने दबाया है। जब प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई तो प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार की तरफ एक आस और उम्मीद के साथ देख रही थी। प्रदेश की जनता ने ही चार लोकसभा सांसद केंद्र में भेजे हैं इस उम्मीद के साथ कि जब जरूरत होगी ये सांसद हमारी

आवाज उठाएंगे और प्रधानमंत्री महोदय, जो इस प्रदेश को कभी अपना दूसरा घर, कभी तीसरा घर और कभी चौथा घर कहते हैं, उन्होंने यहां आकर 1500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी लेकिन उस पैकेज का एक भी पैसा आज तक नहीं आया। प्रदेश की जनता यह सवाल हमारे विपक्षी साथियों और उन सभी लोकसभा सांसदों से पूछना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया यह आश्वासन अब तक झूठा साबित हो रहा है।

18.03.2026/1800 /AT/HK /02

मैं समझता हूं कि इन बातों का जिक्र हमारे विपक्ष के साथियों को भी करना चाहिए। सभी लोग आए दिन दिल्ली जाते हैं तो इन मुद्दों को वहां भी उठाया जाए ताकि प्रदेश की जनता का हक का पैसा उन्हें मिल सके। चाहे वर्ष- 2023 की आपदा हो या वर्ष- 2025 की पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है। अगर मैं अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां भी काफी नुकसान हुआ है। आदरणीय श्री किशोरी लाल जी यहां बैठे हैं उन्होंने अपने भाषण में मंड क्षेत्र का जिक्र किया। पोंग डैम से जब एक्सेस पानी छोड़ा जाता है तो उससे हमारे क्षेत्र में काफी नुकसान होता है। चाहे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र हो या इंदौरा विधान सभा क्षेत्र सभी पंचायतें प्रभावित होती हैं। वर्ष-2023 में भी और वर्ष-2025 में भी ऐसा हुआ। इस बार इंदौरा टाउन में भी काफी पानी भर गया जिससे भारी नुकसान हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी इस बात को कहा था कि वहां पर परमानेंट चाहे प्रोटेक्शन वर्क किया जाए या NABARD के अंतर्गत जो डीपीआर (सीवरेज) इंदौरा के लिए प्रस्तावित है उसे स्वीकृति दिलाई जाए ताकि बार-बार होने वाले नुकसान का स्थायी समाधान निकल सके। इसके अलावा मैं अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की एक और बात करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वर्ष- 2026 में हमारे यहां केयालू बाबा महाराज जी का प्रसिद्ध दंगल जिला स्तरीय घोषित किया गया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार इंदौरा उत्सव की भी हमने शुरुआत की जिसे प्रदेश सरकार द्वारा जिला स्तरीय दर्जा दिया गया। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी .....

18.03.2026/1805/केएस/वाईके/1

श्री मलेन्द्र राजन जारी ---

यहां पर एक और बात का ज़िक्र आया कि जे0जे0एम0 के अंदर पूर्व की सरकार ने रैस्ट हाउसिज़ बनाए। धर्मपुर और सिराज का ज़िक्र आया कि कहीं पर 12 और कहीं पर 14 रैस्ट हाउसिज़ खोल दिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर भी जे0जे0एम0 के अंतर्गत एक रैस्ट हाउस बनाया गया और वह निजी फायदे के लिए शमशान घाट के अंदर बना दिया गया। आज भी वह एक बुत की तरह वहां पर खड़ा है और लोग उसको देखकर हंसते हैं। जल शक्ति विभाग का रैस्ट हाउस शमशान घाट में बना दिया गया, यह उपलब्धि पूर्व की सरकार की रही । वहां के एक स्थानीय भाजपा के नेता ने अपने निजी फायदे के लिए, अपने यूज़ के लिए उसको उस जगह पर बनवा दिया। मैं इस बात का ज़िक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि पूर्व सरकार की विकास को ले कर यह सोच रही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा तो नहीं गया परंतु रखा गया, उसमें प्रदेश सरकार की बहुत सी उपलब्धियों का ज़िक्र किया गया है जिसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। चाहे दूध की बात की जाए या हल्दी की बात की जाए, आज 90 रुपये किलो के हिसाब से हल्दी प्रदेश सरकार खरीद रही है। यह निश्चित रूप से प्रदेश सरकार की शुरुआत है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हमने सिर्फ 100 या 200 किसानों को देनी है। जितने किसान इसमें आते जाएंगे निश्चित रूप से उनको हल्दी से भी और दूध से भी फायदा होगा और जो मक्की और गेहूं के रेट हैं, किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर उनके आने वाले समय में दूरगामी परिणाम होंगे। आज विपक्ष के साथी जो बार-बार माननीय मुख्य मंत्री जी और प्रदेश सरकार पर यहां से टिप्पणियां कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, हमने सोसायटी में भी देखा है कि जब कोई व्यक्ति आम परिवार से निकलकर किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से उस पर टीका-टिप्पणियां होती हैं। मुख्य

मंत्री जी एक आम परिवार से निकलकर प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर बैठे हैं और यही बात हमारे विपक्ष के साथियों को हज़म नहीं हो रही है कि कैसे एक आम घर से निकला हुआ व्यक्ति आज मुख्य मंत्री बन कर पूरे प्रदेश को इन तमाम वित्तीय, राजनीतिक और प्राकृतिक संकटों के

18.03.2026/1805/केएस/वाईके/2

बावजूद भी लगातार एक योद्धा की तरह आज पूरे प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहा है और उसकी पूरे देश में सराहना भी हो रही है। विपक्ष के साथी जो अलग-अलग गुटों में बंटे हैं, अंदर-अंदर ये भी इस बात को समझते हैं, जानते हैं लेकिन एक पार्टी लाइन पर रहकर बोल नहीं पाते हैं। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता निश्चित रूप से इस बात को भली-भांति जानती है, समझती है। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के लिए एक शेर के माध्यम से अपनी बात रखकर समाप्त करुंगा किः-

हमने कुर्सी को नहीं, जिम्मेदारी को निभाया है।
हमने कुर्सी को नहीं, जिम्मेदारी को निभाया है,
जनता के हर दर्द को दिल से अपनाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.03.2026/1805/केएस/वाईके/3

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी और कुछ मित्रों ने कहा कि आपदा आई,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

18.03.2026/1810/av/yk/1

श्री दलीप ठाकुर------ जारी

उसके बाद राजनैतिक व वित्तीय आपदाएं आ गईं। आपदाएं आई क्यों, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। अगर ये आपदाएं आईं तो उसके लिए कहीं-न-कहीं यह सरकार जिम्मेवार है। यह सरकार तीन बजट पेश कर चुकी है और चौथा बजट माननीय मुख्य मंत्री दिनांक 21 मार्च, 2026 को पेश करने जा रहे हैं। पहले बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने एक शब्द निकाला 'व्यवस्था परिवर्तन। जब दूसरा बजट पेश किया तो माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि हर काम 'नीड बेस' पर किया जाएगा और जब तीसरा बजट पेश किया तो मुख्य मंत्री ने तीसरा शब्द निकाला तथा कहा कि अब सारे कार्य 'चरणबद्ध तरीके' से होंगे। परंतु माननीय मुख्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि हमने आते ही यहां पर कितने संस्थान बंद कर दिए जो जनता व विधायक की मांग पर पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने खोले थे। आपने उनको बंद करने का काम किया। आपने अनेकों संस्थान बंद किए जिनमें बजट का प्रावधान भी था, यहां तक कि कई संस्थानों को चले हुए एक-एक वर्ष का समय हो चुका था। आज माननीय मुख्य मंत्री कह रहे थे कि आपने एक हजार करोड़ रुपये के भवन बना दिए। वे भवन इसलिए बनाएं क्योंकि जनता की मांग थी। अगर कहीं अस्पताल की बिल्डिंग बनी तो वह इसलिए बनीं क्योंकि वहां जनता की मांग थी कि इसका स्तर बढ़ना चाहिए। अगर सौ बैडिड होस्पिटल है तो इसको डेढ़ सौ बैडिड किया जाना चाहिए। अगर किसी होस्पिटल को 500 बैडिड से 700 बैडिड किया गया तो उसको जनता की मांग पर किया गया। अगर कहीं पर स्कूल का भवन बना है तो वह भी जनता की मांग पर बनाया गया।

यहां पर जैसे मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि मेडिकल यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट स्थानांतरित कर दिया। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं परंतु मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में मेरा विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा सैनिक क्षेत्र है जहां

से न जाने कितने ही लोग शहीद हुए हैं। हमारे लोगों ने सीमा पर अपनी जानें गवाई हैं। परंतु पूरे प्रदेश में अगर कहीं एक सैनिक अकादमी खुली थी तो वह पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने सरकाघाट में खोली थी। वह इसलिए खोली थी कि सरकाघाट सैनिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां से हजारों की

18.03.2026/1810/av/yk/2

संख्या में युवा फौज में जाते हैं। वे अपनी रोज़ी-रोटी और देश की सेवा के लिए सेना में जाते हैं। परंतु माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उस अकादमी में मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलूंगा। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप खोलिए, हमारे पास सरकाघाट में जगह है। आप आइए और बजट का प्रावधान करके वहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी को खोला जाए। वहां पर पिछली सरकार के कार्यकाल में जो सैनिक अकादमी बनी है जहां से हमारे बच्चे फौज में जाने के लिए तैयार हैं, उसको वैसे-का-वैसा रहने दिया जाए ताकि वहां पर हमारे दोनों संस्थान चलें। अग्निवीर में सब जाना चाहते हैं। ...(व्यवधान) आदरणीय कैप्टन रणजीत सिंह राणा, सब जाना चाहते हैं। इसमें जो बच्चे तीन वर्षों में 28-28 लाख रुपये कमा कर ला रहे हैं वे केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। कैप्टन साहब, आप जब हमारी पार्टी में थे तो ठीक भाषा बोलते थे परंतु अब उधर चले गए हैं तो आपकी भाषा में भी अंतर आ गया है। ...(व्यवधान) मैं अब दूसरी बात करता हूं। आप लोग कहते हैं कि राजनैतिक आपदा आ गई। लेकिन यह राजनैतिक आपदा क्यों आई? आपके अपने लोग आपसे नाराज होकर चले गए, आप अपने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए तथा उनके काम नहीं कर पाए। उनकी जो अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की मांगें थीं आप उनको पूरा नहीं कर पाए इसीलिए वे आपसे दूर हो गए।

टी सी द्वारा जारी

श्री दलीप ठाकुर.... जारी

और आपके सामने राजनीति की आपदा आई। इसे बुरा मत मानिए, कमी आपकी है, आपकी सरकार की है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। वर्ष 2023 में मेरे क्षेत्र में आपदा से सड़कों को भारी नुकसान हुआ। मेरा आज भी प्रश्न लगा था जब मैंने इन सड़कों के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि इन सड़कों के लिए पैसे का प्रावधान नहीं है। इन सड़कों के लिए हम पैसों का प्रावधान कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी वर्ष 2023 में सरकाघाट में आए थे। उन्होंने कहा था कि सड़कों को तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने आपदा के समय सरकाघाट के हर गांव में गए और उनकी समस्या को समझने का प्रयास किया लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्री जी आए और घोषणा करके चले गए कि मैं इन सड़कों को ठीक करवाउंगा। मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र में स्कूल का ग्राउंड चला गया, स्कूल का भवन चला गया। जुकाण और ज्वाली पंचायत में मिडल स्कूल चला गया। आज भी ज्वाली में स्कूल किराए के भवन में चल रहा है। लोग आज भी किराया मांग रहे हैं लेकिन सरकार के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। वहां स्कूल का भवन आज तक नहीं बन पाया। आज भी बच्चे किराए के भवन में पढ़ रहे हैं।

हमारी पूर्व सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। केंद्र की सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया। आज भी अखबार में लोक निर्माण मंत्री जी की खबर छपी है और इन्होंने केन्द्र की सरकार का धन्यवाद किया है कि केंद्र की सरकार ने बहुत पैसा दिया है और 15000 किलोमीटर सड़कों का काम शुरू करने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नाबार्ड के तहत सड़कें बन रही हैं। अगर पैसा आ रहा है तो केंद्र सरकार की वजह से आ रहा है। अगर प्रदेश में काम हो रहे हैं तो वे जे0जे0एम0 के माध्यम से हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में शिवा प्रोजैक्ट के काम पिछली सरकार के समय में चले थे। पिछली बार माननीय मुख्य मंत्री रात 8 बजे पहुंचे लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया था, फिर भी मैं गया। मैंने सोचा कि उनका स्वागत करुंगा और उनके समक्ष अपने क्षेत्र की समस्या का जिक्र भी करुंगा। उन्होंने टॉर्च लेकर कुएं में देखा कि पानी है या नहीं लेकिन जब पानी नहीं होगा तो कुआं सूखेगा ही। कुछ दिन पहले राजस्व मंत्री जी भी वहां गए थे, वे सायं 6

18.03.2026/1815/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

बजे वहां पहुंचे। हमें कोई सूचना नहीं दी गई यानी चुने हुए प्रतिनिधि को जानकारी तक नहीं दी गई। वे एक क्लस्टर में गए और वहां से मण्डी चले गए। लोगों ने कहा कि पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। आज जो भी काम हो रहा है, वह केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। आज जितने भी बड़े,बड़े प्रोजैक्ट आ रहे हैं चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान, उज्ज्वला योजना की बात हो, वे केन्द्र सरकार की वजह से चल रही हैं। हिमकेयर, सहारा योजना और गृहिणी योजना जय राम ठाकुर जी ने शुरू की थी। ये योजनाएं आम आदमी के लिए थीं, गरीबों के लिए थीं। आपने आते ही इन योजनाओं को बंद कर दिया। आज कोई योजना सही तरीके से नहीं चल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब मांगने की बात होती है तो कहते हैं यह हमारा अधिकार है। लेकिन आपने दिल्ली में संबंध नहीं बनाए। अगर संबंध बनाए होते तो प्रदेश को और पैसा मिलता।...(व्यवधान) हम तो चाहते हैं कि आपके संबंध बने लेकिन आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, आपकी नीयत ठीक नहीं है सरकार इस दिशा में काम नहीं करना चाहती। जिस तरह से आप काम करना चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं होगा।

मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत-सारी समस्याएं हैं।

एन0एस0 द्वारा ... जारी

18-3-2026/1820/NS-AG/1

श्री दलीप ठाकुर ---- जारी

इस कार्यकाल में सरकार का चौथा बजट पेश होने जा रहा है। पिछली बार मैं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात कर रहा था, 4 लाख रुपये का बजट जिस डिवीजन को मिलेगा उसमें एक्सिअन की गाड़ी का डीजल ही आएगा। आपने उसी तर्ज पर अबकी बार भी यह काम शुरू किया है और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि आपकी इस वर्ष भी कोई काम करने की इच्छा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि पिछली सरकार यानी श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने बहुत लोन ले लिया। आप देखिए कि आपकी सरकार ने साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में कितना लोन लिया है फिर भी विकास के कार्य ठप हैं। प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा है। आप रोना रोते रहेंगे, अब तो आपके पास कुल डेढ़ वर्ष का कार्यकाल रह गया है। अभी आप चौथा बजट पेश करेंगे। फिर आप पांचवां बजट पेश करेंगे तो फिर जैसा आपने हमारे साथ किया है आपके साथ भी वैसा ही होगा क्योंकि आपने जितने संस्थान बंद किए हैं जब हमारी सरकार आएगी तो उन संस्थानों को दोबारा से चलाएगी। आपके ही पार्टी के मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी कहते थे कि अगर एक बच्चा भी पढ़ने वाला होगा तो उसके लिए भी स्कूल खुलेगा। आपने 1000 संस्थान बंद कर दिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभिभाषण आपने राज्यपाल महोदय से पढ़वाया और यह आपकी सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। इसलिए राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि इसमें बहुत-सी कमियां हैं। आपने केंद्र सरकार के विरुद्ध सारी बातें लिखी हैं इसलिए इसको पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि आपने इसमें झूठ बोलने की कोशिश की है। जैसे यहां पर हल्दी की बात हुई कि हल्दी खरीद ली। कितने आदमियों ने हल्दी खरीदी? 60 से 61 आदमियों ने हल्दी खरीदी। आपने मक्की 30 रुपये खरीदी और फिर 40 रुपये खरीदी। गरीब आदमियों को डिपुओं के माध्यम से 50 रुपये प्रति किलो आपने मक्की का आटा बेचने का काम किया जबकि हमारे प्रदेश में मक्की की पैदावार ज्यादा हुई थी। आप कहां जनहित की बात करते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने लोगों के साथ जुड़ना है तो लोगों के हित की बात कीजिए, गरीब आदमी के हित की बात कीजिए और विकास के सारे काम कीजिए। ...(व्यवधान) इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पढ़ाने का प्रयास किया जो आपकी सरकार द्वारा लिखा गया है, मैं

18-3-2026/1820/NS-AG/2

उसका समर्थन करने में बिल्कुल असमर्थ हूं। मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता हूं क्योंकि यह झूठ का पुलिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

18-3-2026/1820/NS-AG/3

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी ने शिवा क्लस्टर के बारे में बात की है। मैं उस संबंध में बताना चाहता हूं कि यह कोई केंद्र सरकार की योजना नहीं है। इनके इलाके में बहुत सुंदर क्लस्टर लग रहे हैं और जिस जगह पर मैं 8:00 बजे गया आज उसमें फल भी लगने शुरू हो गए हैं। हमारी जितनी भी स्कीमें हैं उनमें पानी की आपूर्ति एश्योर्ड है। यह ठीक है कि कहीं हम थोड़ा टाइम लाइन से पीछे हो गए हैं परंतु सब जगहों पर बढ़िया काम हो रहा है। जहां तक इनको सूचना देने की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं जिस भी इलाके में जाता हूं मेरे ऑफिस से उस इलाके के माननीय सदस्य को सूचना दी जाती है। अब ये वहां आए या न आएं ये इनके ऊपर निर्भर है। ये 08:00 बजे आए थे और बड़े प्यार से मिले तथा इन्होंने कोई शिकायत नहीं की। आज पता नहीं दो वर्षों के बाद इनको शिकायत की बात याद आ रही है। ये बड़ी-बड़ी स्कीमों की बात कर रहे थे जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है इन्होंने कांग्रेस सरकार की यू0पी0ए0 गवर्नमैंट ने डॉ0 मनमोहन सिंह जी के समय में अनेकों स्कीम बनाई गई थीं और इन्होंने उनके नाम ही बदल दिए हैं। अब अगर मैं इन्हें पढ़ कर सुनाऊं तो मेरे पास 23 ऐसी स्कीमें हैं जिनके नाम इन्होंने बदले हैं। अगर यह माना जाए कि पढ़ा हुआ समझा जाए तो सदन का समय बच जाएगा। ये एक भी नई स्कीम बताएं जिसमें इन्होंने काम किया है। चाहे वह एल0पी0जी0 की है, चाहे वह मनरेगा की स्कीम है। मनरेगा को आपने जी राम जी बना दिया। स्वच्छ भारत अभियान का नाम भी इन्होंने बदल दिया। मेरे पास यहां पर समय नहीं

हैं परंतु जब भी मुझे बोलने का समय मिलेगा मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस बारे में बता दूंगा। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 19 मार्च 2026 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 18 मार्च, 2026 **सचिव।**